ISSN-0971-8397

योजना

जुलाई 2021

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

मास्क अप इंडिया

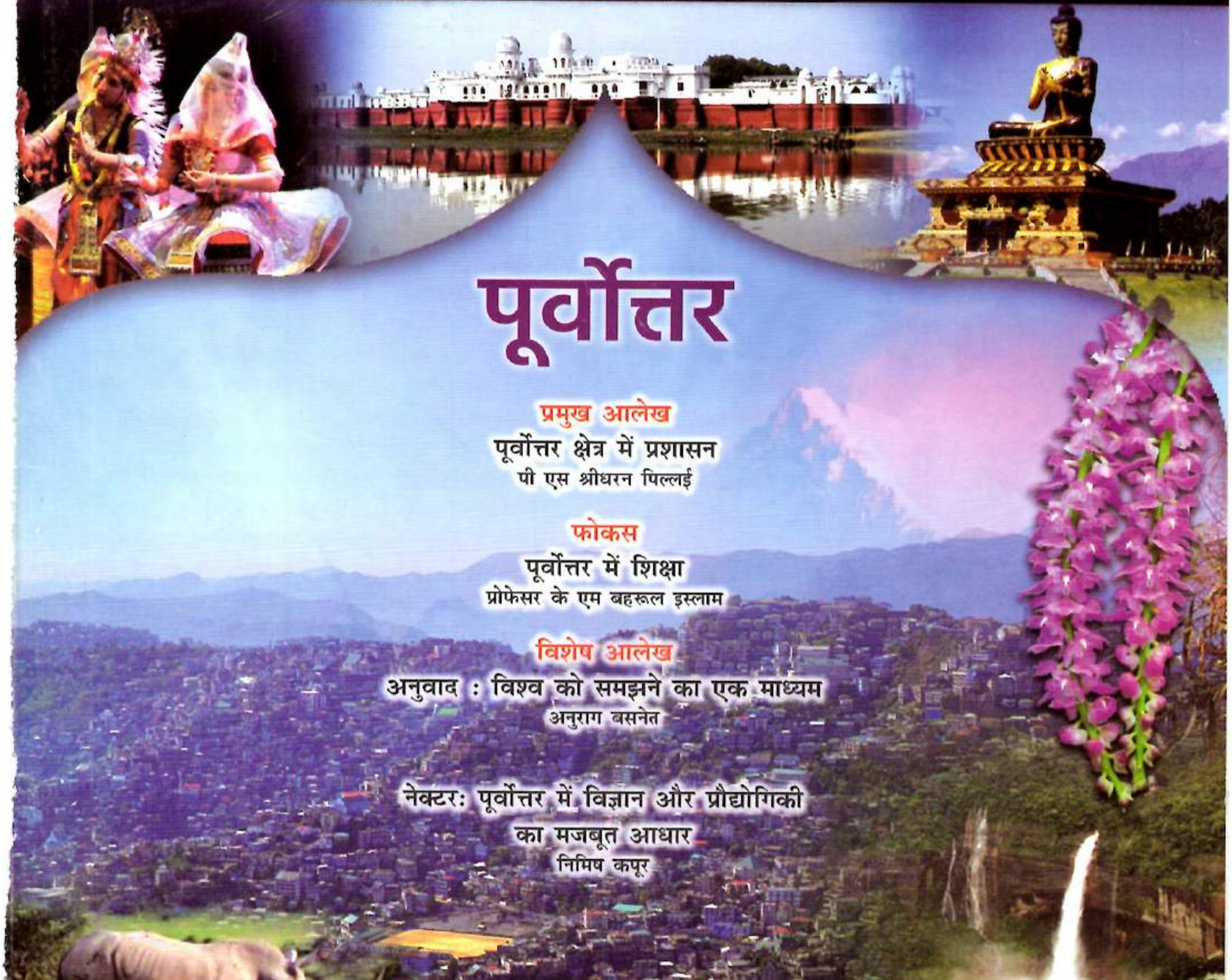

पूर्वोत्तर

प्रमुख आलेख

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासन

पी एस श्रीधरन पिल्लई

फोकस

पूर्वोत्तर में शिक्षा

प्रोफेसर के एम बहरूल इस्लाम

विशेष आलेख

अनुवाद : विश्व को समझने का एक माध्यम

अनुराग बसनेत

नेक्टर: पूर्वोत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मजबूत आधार

निमिष कपूर

ऊर्जा दक्षता उपाय

भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन स्तर को कम करने और ऊर्जा बचाने के उद्देश्य से उद्योगों और प्रतिष्ठानों में आधुनिक उपकरणों के उपयोग के जरिये विभिन्न उपायों को लागू कर रहा है। इस संबंध में *परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड* (पीएटी) यानी 'प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार' योजना बड़े उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों को उन्नत करके अथवा ऊर्जा की खपत को कम करने संबंधी आंतरिक पहल के जरिये ऊर्जा बचत की लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत पहचान की गई बड़ी इकाइयों के लिए अनिवार्य लक्ष्य और उनके द्वारा बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों को उनके ऊर्जा खपत के स्तर और ऊर्जा बचत की क्षमता के आधार पर अलग-अलग ऊर्जा दक्षता लक्ष्य दिए गए हैं।

वर्ष 2020 तक इस योजना का विस्तार सीमेंट, लौह एवं इस्पात, उर्वरक, ताप विद्युत संयंत्र, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और रेलवे सहित सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाले देश के 13 क्षेत्रों तक किया गया है। इस पहल से फिलहाल लगभग 1.7 करोड़ टन तेल समतुल्य ऊर्जा की बचत हो रही है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 8.7 करोड़ टन की कमी आई है जो बांग्लादेश जैसे देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग बराबर है।

घरेलू स्तर पर अथवा कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत के मुख्य बिंदु विद्युत उपकरण होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा खपत वाली उपभोक्ता वस्तुओं में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर विद्युत ऊर्जा की मांग हर साल बढ़ रही है। यदि उपभोक्ता उच्च दक्षता वाले उपकरणों को प्राथमिकता देंगे तो बिजली इस बढ़ती हुई मांग को नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा कुशल उत्पादों के बाजार में बदलाव के लिए *ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी* (बीईई) यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मानक एवं लेबलिंग यानी *स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग* (एसएंडएल) कार्यक्रम शुरू किया गया था। एसएंडएल का उद्देश्य ऊर्जा बचत की संभावना के बारे में उपभोक्ताओं को एक विकल्प प्रदान करना और इस प्रकार बाजार में उपलब्ध उत्पादों के जरिये लागत में बचत करना है। इस योजना में न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों की व्यवस्था के साथ प्रमुख ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों पर ऊर्जा प्रदर्शन संबंधी लेबल को प्रदर्शित करना शामिल है। अब इस योजना में मार्च 2021 तक 28 उपकरणों को शामिल किया गया है और ऊर्जा कुशल उत्पादों के 15,000 से अधिक मॉडलों को स्टार लेबल दिया गया है जो ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं के बीच एक लोकप्रिय प्रतीक है। नागरिकों द्वारा बड़ी तादाद में ऊर्जा कुशल उत्पादों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान 56 अरब यूनिट बिजली की बचत होने का अनुमान है जिसकी कीमत करीब 30,000 करोड़ रुपये है। यह पहल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को हर साल लगभग

4.6 करोड़ टन कम करने में प्रभावी रही है। इस प्रकार के कदम बहुत प्रभावी हो गए हैं और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक सरल दृष्टिकोण को कहीं अधिक उपयोगी माना जाता है। कई देशों ने इस लेबलिंग कार्यक्रम को अपनाया है जिससे ऊर्जा बचत का फायदा मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आई है।

यदि सभी संभावित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा दक्षता संबंधी उपायों को अपनाया जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों में नियामकीय और बाजार आधारित नीतियों के मेल से काफी आशाजनक परिणाम मिलेंगे। यह पर्यावरणीय अखंडता को बनाए रखने और जलवायु के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों का समर्थन करेगा।

कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर एक चर्चित ग्रीनहाउस गैस है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता तेजी से बढ़ने के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है जिससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा होती हैं। 'ग्रीनहाउस प्रभाव' कार्बन डाइऑक्साइड की उस स्थिति में काम करता है जब सौर विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराता है और गर्मी का कुछ हिस्सा वायुमंडल से बाहर निकल जाता है लेकिन शेष गर्मी उसमें फंस जाती है जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यह एक ऐसी घटना है जिसे *ग्लोबल वार्मिंग* के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव डालता है जिसका सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों पर और सभी उद्योगों एवं दुनिया भर के लोगों पर प्रभाव पड़ता है।

बीईई के बारे में

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधान के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के दायरे में भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्व-विनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है। इसे सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को तेजी से और लगातार अपनाने पर जोर दिया जाएगा। बीईई के ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता प्रयासों के दायरे में उपकरण, भवन, परिवहन और कृषि, नगरपालिका एवं उद्योग व अन्य प्रतिष्ठानों में प्रमुख मांग के प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं। ■

योजना

वर्ष : 65
अंक : 07

जुलाई 2021
आषाढ़-श्रावण, शक संवत् 1943

मूल्य : ₹22
पृष्ठ : 64

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-58** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष: 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

@DPD_India

इस अंक में

प्रमुख आलेख

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासन
पी एस श्रीधरन पिल्लई..................... 6

संस्कृति के माध्यम से विकास
डॉ नरेंद्र जोशी......................................12

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि
डॉ एम प्रेमजीत सिंह............................16

दीर्घावधि शांति और विकास
मृणाल तालुकदार..................................20

फोकस

पूर्वोत्तर में शिक्षा
प्रोफेसर के एम बहरूल इस्लाम....... 26

विशेष आलेख

अनुवाद – विश्व को समझने का एक माध्यम
अनुराग बसनेत................................ 31

सुरों की मधुर विविधता
बिजय शंकर बोरा........................... 36

पूर्वोत्तर भारत में सिनेमा
मंजू बोरा.. 42

कपड़े और डिज़ाइन
सोनम दूबल.................................... 48

नेक्टर: पूर्वोत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मजबूत आधार
निमिष कपूर...51

बांस: आजीविका का महत्वपूर्ण संसाधन
अंकिता शर्मा..56

खेलों में तेज़ी से आगे बढ़ता पूर्वोत्तर
राजेश राय..59

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पुस्तक चर्चा - पूर्वोत्तर भारत के स्वातंत्र्य वीर..................... कवर-3

नियमित स्तंभ

विकास पथ
ऊर्जा दक्षता उपाय.................... कवर-2

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 24

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय

क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम होगा – एक राष्ट्र, एक चुनाव

योजना 'मई' अंक अपने में एक विशेष अंक था। जिसके अंतर्गत कई आकर्षित करने वाले तत्व थे। उसमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला विषय; एक राष्ट्र एक चुनाव लगा। देशभर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित करने से न केवल मतदान में वृद्धि होगी, बल्कि बेहतर शासन की सुविधा भी मिलेगी क्योंकि पार्टियां राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर के घोषणापत्रों को जोड़ने के लिए मजबूर होंगी। **'एक राष्ट्र, एक चुनाव'** चुनाव कराने की लागत को कम करेगा, और सभी चुनावों को एक ही सत्र तक सीमित कर देगा। वर्तमान में, चुनाव कहीं न कहीं लगभग हर समय होते हैं, और अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि आदर्श आचार संहिता सरकार द्वारा लोगों के लाभ के लिए परियोजनाओं या नीति योजनाओं की घोषणा के रास्ते में आ जाती है। मुझे इस अंक से काफी सारी जानकारी एक ही स्थान पर मिल गई। वैसे तो 'योजना' की सारी जानकारियां काफी अच्छी होती हैं। अंक की प्रस्तुति के लिए योजना टीम को धन्यवाद देता हूं।

– ऋशव राज, पटना, बिहार
rishavrajnce@gmail.com

प्रतिस्पर्धी संघवाद की भूमिका

योजना 'मई' विशेषांक अत्यधिक ज्ञानवर्धक रहा, जिसमें सभी प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा भारतीय नव संघवाद की सफलता और चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें नीति आयोग एक 'थिंक टैंक' मात्र न होकर केंद्र राज्यों के बीच सहयोग के जरिए प्रतिस्पर्धी संघवाद की भूमिका में कार्य कर रहा है जो "पुरानी टॉप टू बॉटम" रणनीति त्याग कर 'बॉटम टू टॉप' की अवधारणा के साथ सबका साथ, सबका विकास रणनीति पर कार्यरत हैं। परंतु संघीय व्यवस्था केवल एक संस्थानात्मक प्रबंधन नहीं है बल्कि इनके निर्धारण में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अत्यधिक महत्व है जिसके कारण ही सहयोग और संघर्ष निर्धारित होते हैं।

वर्तमान कोरोना महामारी में राजकोषीय संघवाद की सुदृढ़ता से ही राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू किया गया। जिससे ये स्पष्ट हो गया कि संघ व राज्यों के बीच परस्पर सहयोग के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

संघवाद की चुनौतियों को केवल शक्ति सन्तुलन के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, क्योंकि राज्यों की अत्यधिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा हो सकती है।

– विनीत कुमार
शामली, उत्तर प्रदेश

योजना के आगामी अंक

अगस्त 2021–'लोक प्रशासन'

आज ही अपनी प्रति निकटतम पुस्तक विक्रेता के पास सुरक्षित कराएं।

शीघ्र आ रहा है– 'नारी शक्ति' पर केंद्रित अंक

पत्रिका न मिलने की शिकायत अथवा
योजना की सदस्यता लेने या
पुराने अंक मंगाने के लिए
pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें।
या संपर्क करें– दूरभाषः 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

विविधता का अद्‌भुत संगम

पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के लिए दिल्ली में अपना पारंपरिक व्यंजन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? इसकी बानगी पिछले वर्ष ही आई इस व्यंजन- 'अखनी' पर बनी फिल्म 'Axone' में देखी जा सकती है। अखनी की गंध अलग तरीके की होती है। इस वजह से फिल्म के नायक को भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हालांकि, फिल्म के आखिर में दिल्ली को ऐसे केंद्र के रूप में दिखाया जाता है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाया जाता है। सिक्किम में शमनवाद पर हाल में आई ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही हुई है। इसमें कई स्थानीय प्रतिभाओं के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवन शैली और चुनौतियों के बारे में बताया गया है। पूर्वोत्तर भारत को 'मुख्यधारा' से जोड़ने का मौजूदा नज़रिया अदूरदर्शी और अनुचित है। यह कुछ ऐसा है मानो आप किसी दिल्ली या मुंबई वाले को कह रहे हों कि उनकी पहचान तभी है, जब कोई आम अमेरिकी इसे मान्यता दे। दरअसल, यह कुछ ऐसा है कि हम अपनी अज्ञानता को कुछ ऐसी चीज पर थोप रहे हैं जिसका अस्तित्व लंबे समय से सफलतापूर्वक कायम है।

पूर्वोत्तर राज्यों में कई तरह की खूबियां मौजूद हैं- उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधन, हरियाली और जंगल, वर्षा, व्यापक जैव-विविधता, वनस्पति व जीव और सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता का अद्‌भुत संगम। योजना के इस अंक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में समग्र तौर पर जानने की कोशिश की गई है। इस क्षेत्र के पास अलग तरह की चुनौतियां और अवसर हैं। आज जहां पूरी दुनिया प्राकृतिक जीवनशैली की तरफ बढ़ रही है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का जीवन सहज रूप से प्रकृति से जुड़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनोखी देशी संस्कृति है और इसे बचाना होगा। साथ ही, इस क्षेत्र के लोगों को आधुनिक समय के हिसाब से प्रासंगिक भी बनाना होगा।

इस अंक के लिए आलेख/सामग्री तैयार करना मुश्किल, लेकिन दिलचस्प काम था। इसमें संगीत, नृत्य, अलग-अलग कलाओं, साहित्य, फिल्म से लेकर शासन प्रणाली, विकास, रोज़गार और शैक्षणिक अवसर जैसे विविध विषयों पर आलेख दिए गए हैं। हम विनम्रतापूर्वक यह स्वीकार करना चाहते हैं कि 8 राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को कुछ पन्नों में समेटना असंभव है। हालांकि, हमने इस क्षेत्र की अलग-अलग झलकियों, विचारों और शोध को पेश करने की कोशिश की है। हमें लगता है कि इन राज्यों से जुड़ी अलग-अलग तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर-संकाय शोध समुदाय, नीति निर्माताओं, नीतियों को लागू करने वालों और सिविल सोसायटी को समन्वित आधार पर काम करने की ज़रूरत है। आम धारणा यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों की संभावनाओं का अब तक तक सही तरीके से दोहन नहीं किया गया है, जिसका लाभ यहां के लोगों को मिलता। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि यह क्षेत्र भी विकास के मामले में देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल सके।

हम अपने लेखकों के आभारी हैं जिन्होंने महामारी और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई समस्याओं और दुःख के दौर में भी इस अंक के लिए अपना योगदान दिया। धैर्य बनाए रखने और लगातार सहयोग प्रदान करने के लिए हम अपने पाठकों का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। अपने पाठकों के सुझावों के माध्यम से ही हम उन विषयों की पहचान कर पाते हैं जो लोगों की पसंद और जरूरतों के मुताबिक होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह अंक ज्ञानवर्द्धक और बेहतर होगा। सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें! ■

विशेष फोकस : मिज़ोरम

प्रमुख आलेख

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासन

पी एस श्रीधरन पिल्लई

मिज़ोरम का शाब्दिक अर्थ है मिज़ो लोगों की भूमि। 'मिज़ो' एक व्यापक शब्द है जो ल्युसेई (पहले यह ल्युशाई कहलाती थी) लई, मारा, ह्मार, पैले जैसे अनेक जनजातियों और कबीलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्रिटिश शासन से पहले विभिन्न मिज़ो जनजातियां कबीलों के स्वतंत्र सरदारों के अधीन रहती थीं। ब्रिटिश लोग इस इलाके को ''ल्युशाई हिल्स'' नाम से जानते थे और यह 1895 में विधिवत ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया था। भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद ल्युशाई हिल्स (जो बाद में मिज़ो जिला बना) असम राज्य का जिला बन गया। 1972 में इसे केंद्रशासित प्रदेश मिज़ोरम बना दिया गया। फिर लगभग दो दशकों तक विद्रोह के बाद 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा पाकर मिज़ोरम भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र - एक नज़र में

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य आते हैं और इस क्षेत्र में अपार प्राकृतिक संपदा और व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाजों वाले अनेक समुदाय रहते हैं। यहां भौगोलिक दृष्टि से कठिनाई भरा भूभाग है, पिछड़े इलाके हैं और कनेक्टिविटी भी सीमित है। अभी हाल तक इस क्षेत्र में कई उग्रवादी ग्रुप (संगठन) सक्रिय थे। लेकिन, केंद्र की मौजूदा सरकार के अंतर्गत हुए नगालैंड शांति समझौते और बोडो शांति समझौते के बाद वहां अब काफी हद तक शांति स्थापित हो चुकी है।

यह क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि से सिर्फ करीब 22 किलोमीटर चौड़े गलियारे से जुड़ा हुआ है जिसे सिलिगुड़ी गलियारा कहा जाता है (इसे पहले चिकेन्स नैक यानी मुर्गे की गर्दन कहा जाता था)। इस तंग गलियारे को छोड़कर देश का समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इस भौगोलिक स्थिति के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसी कारण इस समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर दायित्व प्रशासन को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए।

पूर्वोत्तर भारत के लिए संस्थागत सहायता

वर्ष 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इसे 2004 में पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर भाग के सभी आठ राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों और समस्याओं से निपटने के उपाय करता है। यह मंत्रालय समयातीत न होने वाले संसाधनों के केंद्रीय पूल का प्रबंधन करता था और अब पूर्वोत्तर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना चला रहा है।

पूर्वोत्तर परिषद भारत की क्षेत्रीय योजना बनाने वाली संवैधानिक संस्था है जिसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत

लेखक मिज़ोरम के राज्यपाल हैं। ईमेल: governor-m2@gov.in

किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठों राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य होते हैं। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री और उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री होते हैं।

मिज़ोरम परिचय

मिज़ोरम का शाब्दिक अर्थ है मिज़ो लोगों की भूमि। 'मिज़ो' एक व्यापक शब्द है जो ल्युसेई (पहले यह ल्युशाई कहलाती थी) लई, मारा, ह्मार, पैले जैसे अनेक जनजातियों और कबीलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्रिटिश शासन से पहले विभिन्न मिज़ो जनजातियां कबीलों के स्वतंत्र सरदारों के अधीन रहती थीं। ब्रिटिश लोग इस इलाके को ''ल्युशाई हिल्स'' नाम से जानते थे और यह 1895 में विधिवत ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया था। भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद ल्युशाई हिल्स (जो बाद में मिज़ो जिला बना) असम राज्य का जिला बन गया। 1972 में इसे केंद्रशासित प्रदेश मिज़ोरम बना दिया गया। फिर लगभग दो दशकों तक विद्रोह के बाद 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा पाकर मिज़ोरम भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया।

संस्कृति और धर्म

ब्रिटिश लोगों के आने से पहले यहां के जनजातीय लोग जीववादी (एनिमिस्टि) थे। वे लोग पुराने ढंग की खेती करते थे, वन्य पशुओं का शिकार करते थे और ग्रामीण लोग अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। उस दौर के लोकगीतों में मुख्य रूप से तीन विषय शामिल रहते थे- 'प्रेम', 'शिकार', और 'योद्धा'। उनके कोई लिखित आलेख नहीं होते थे। कुछ जनजातीय नृत्य भी थे, जैसे : चेरॉव (बैम्बू डांस), सरलमकई, छेईहलम, खुवाल्लंम इत्यादि। वे तीन मुख्य त्यौहार मनाते थे- पाउल कुट, चपचार कुट और मिम कुट।

ब्रिटेन का शासन आने के साथ ही ईसाई मिशनरियां भी आईं जिन्होंने मिज़ो भाषा की लिपि खोजी और उसकी वर्णमाला का विकास किया। आज मिज़ोरम के लगभग सभी गैर-यहूदी लोग क्रिश्चयन धर्म अपनाकर ईसाई बन चुके हैं, राज्य की जनसंख्या के 87 प्रतिशत लोग ऐसा कर चुके हैं। उनके जीवन का हर पहलू और उनका रहन-सहन पूरी तरह क्रिश्चयन लोगों जैसा बन चुका है और पुरानी देशीय मान्याताएं और परम्पराएं अब कहीं नहीं दिखाई देती। मिज़ोरम की लगभग 8 प्रतिशत जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है जिनमें मुख्य रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे इलाके के चमका जनजातीय लोग शामिल हैं।

मिज़ो विद्रोह (1966-1986)

1959 में मिज़ो हिल्स में 'मौतम' अकाल पड़ा था। उस वक्त यह जिला असम राज्य का भाग था। करीब 48 वर्ष बाद बांस में अंकुर फूटते हैं और तभी कीड़े-मकौड़ों और चूहों के मरने से प्लेग का प्रकोप आता है जिससे कृषि क्षेत्र में अकाल पड़ता है। उस समय केंद्र सरकार और असम सरकार, दोनों की ओर से उपेक्षा किए जाने का अनुमान लगाकर आक्रोश में भरकर लोगों ने मिज़ो नेशनल फैमिन फ्रंट का गठन किया जिसका नेतृत्व ललडेंगा कर रहे थे। 1961 में यही मिज़ो नेशनल फैमिन फ्रंट एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया और इसे मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के नाम से जाना गया। इसके अध्यक्ष ललडेंगा ही बने थे। एमएनएफ ने 28 फरवरी, 1966 की रात में भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया और अगले दिन 1 मार्च, 1966 को उन लोगों ने स्वतंत्र हो जाने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना द्वारा दबा दिए जाने के बाद एमएनएफ पीछे हट गया लेकिन पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा (म्यांमार) से अपनी गतिविधियां चलाता रहा और चीन उसे ट्रेनिंग और समर्थन देता रहा। मिज़ो विद्रोह करीब बीस वर्ष चलता रहा और इस दौरान एमएनएफ और भारत सरकार एक-दूसरे पर ज्यादतियों के आरोप लगाते रहे। आखिरकार 30 जून, 1986 को एमएनएफ के नेता ललडेंगा, केंद्रीय गृह सचिव आरडी प्रधान और मिज़ोरम के मुख्य सचिव ललखामा के बीच भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत मिज़ोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ मिज़ोरम 20 फरवरी, 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बन गया। एमएनएफ राज्य में चुनाव जीत गया और ललडेंगा वहां के पहले मुख्यमंत्री बने।

वर्ष 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इसे 2004 में पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर भाग के सभी आठ राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों और समस्याओं से निपटने के उपाय करता है। यह मंत्रालय समयातीत न होने वाले संसाधनों के केंद्रीय पूल का प्रबंधन करता था और अब पूर्वोत्तर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना चला रहा है।

मिज़ोरम - मूल मापदंड

मिज़ोरम का भौगोलिक क्षेत्र 21,081 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में 11 जिले हैं जिन्हें 23 उप-डिवीजनों में बांटा गया है। राज्य में 26 ग्रामीण विकास खंड बनाए गए हैं। राजधानी आइज़ोल में एक नगर पालिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 830 गांव हैं और राज्य की कुल जनसंख्या 10,97,206 थी। राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 52 लोग रहते हैं। शहरी आबादी 51.11 प्रतिशत है और 47.89 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमाएं

मिज़ोरम के पश्चिम में 318 किलोमीटर लम्बी सीमा बांग्लादेश से लगती है जिसकी रखवाली सीमा सुरक्षा बल करता है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीलें तारों की फेंसिंग (बाड़) लगाई गई है। पूर्वी दिशा में राज्य की 404 किलोमीटर लम्बी सीमा म्यांमार से लगती है जिसकी रखवाली अर्द्धसैनिक बल असम राइफल्स संभालता है। सीमा पर रहने वाले दोनों देशों के बीच भाईचारा और मेलजोल होने के कारण सामान्य समय में भारत म्यांमार से मुक्त आवाजाही की व्यवस्था पर सहमत रहता है जिसके तहत सीमा के दोनों तरफ 16 किलोमीटर के भीतर लोग 72 घंटे के लिए बिना वीज़ा के बेरोकटोक आ-जा सकते हैं।

एक तरफ से म्यांमार और दूसरी तरफ से बांग्लादेश के बीच फंसे होने का यह लाभ भी है कि यह क्षेत्र इन दोनों देशों को जोड़ने वाले सेतु की भूमिका निभाता है। हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत मिज़ोरम का यह क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बन सकता है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।

अल्पसंख्यक और पिछड़े इलाके

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मिज़ोरम में तीन स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी) हैं जिन्हें लई एडीसी, मारा एडीसी और चकमा एडीसी कहते हैं। लई, मारा और चकमा इन परिषदों में पाई जाने वाली बहुसंख्यक जनजातियों के नाम हैं। लई और मारा जनजातियों के बीच आपसी संबंध होते हैं और ये 'मिज़ो' जनजाति के तहत आती हैं जबकि चकमा जनजाति के लोग संस्कृति, भाषा और धर्म के मामलों में मिज़ो लोगों से भिन्न हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मिज़ोरम के राज्यपाल को इन इलाकों के बारे में विशेष अधिकार और दायित्व प्राप्त हैं तथा कई विवेकाधीन शक्तियां भी उनके पास हैं।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मिज़ोरम में तीन स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी) हैं जिन्हें लई एडीसी, मारा एडीसी और चकमा एडीसी कहते हैं। लई, मारा और चकमा इन परिषदों में पाई जाने वाली बहुसंख्यक जनजातियों के नाम हैं। लई और मारा जनजातियों के बीच आपसी संबंध होते हैं और ये 'मिज़ो' जनजाति के तहत आती हैं जबकि चकमा जनजाति के लोग संस्कृति, भाषा और धर्म के मामलों में मिज़ो लोगों से भिन्न हैं।

मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था

कोविड-19 महामारी आने से पहले मिज़ोरम के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो रही थी। वर्तमान मूल्यों के आधार पर 2019-20 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 26,502 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 18.91 प्रतिशत ज्यादा था। 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर 2011-12 से 2019-20 के वित्तीय वर्षों की अवधि में राज्य के सकल मूल्यवर्द्धित उत्पाद में औसतन 12.63 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 43.28 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्रों का इसमें करीब 30.64 प्रतिशत योगदान है जबकि बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग वहां लगभग न के बराबर हैं। आधी से ज्यादा जनसंख्या की आय का साधन खेती ही है परन्तु सकल घरेलू मूल्य संवर्द्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान सिर्फ 26.08 प्रतिशत है।

मिज़ोरम का 2021-22 का बजट 11,148.89 करोड़ का है और 2019-20 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,01,741 रुपये रहने का अनुमान है।

कृषि

मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और राज्य की, विशेषकर ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रहती है। अनुमान है कि 2018-19 में कुल 2,17,000 हैक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई। 2019-20 की मुख्य फसलों का उत्पादन इस प्रकार रहा: तिलहन-8,087 मीट्रिक टन, गन्ना: 46,842 मीट्रिक टन, आलू: 534 मीट्रिक टन, मक्का: 11,668 मीट्रिक टन, धान: 60,239 मीट्रिक टन और दालें: 5,507 मीट्रिक टन।

मिज़ोरम में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2017 से मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओबीसीडीएनआर) योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत 13,000 हैक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले 14,104 किसानों को कवर किया गया है और 9 कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) और 5 कृषि उत्पादक कंपनियां भी स्थापित की गई हैं। इसका मूल उद्देश्य परंपरागत कृषि प्रणालियों की जगह बाजार-अनुकूल क्लस्टर खेती को अपनाना और फिर हल्दी, मिर्च, अदरख और चाय जैसी अधिक मूल्यवान फसलों पर ध्यान केंद्रित करना है।

बीजों और पौध सामग्री के बारे में उप-मिशन का उद्देश्य सभी फसलों के अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कुल 404 हैक्टेयर में जैतून की खेती की गई है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के संकल्प के तहत भी अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाना भी शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र, समेकित कृषि प्रणाली और हरली-आधारित खेती जैसी योजनाएं भी अपनाई जा रही हैं।

बागवानी

मिज़ोरम में कृषि और जलवायु की दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण बागवानी बहुत उपयोगी और लाभप्रद व्यवसाय है। वर्ष 2020 में बिना मौसम के टमाटर की खेती से 240.80 लाख रुपये से अधिक की आमदनी हुई थी और बन्द गोभी की बेमौसम फसल से 330.20 लाख रुपये के करीब आमदनी हुई। ड्रैगन फ्रूट की क्लस्टर खेती का विस्तार किया गया है जिससे 2019-20 के दौरान 300 लाख रुपये के आसपास आय हुई। 2019-20 में मैंडेरिन ऑरेंज (संतरे) की उपज करीब 53984 मीट्रिक टन हुई जिसका मूल्य लगभग 16 करोड़ रुपये था। मिज़ोरम की विश्व प्रसिद्ध लाल मिर्च का तो विशेष स्थान और महत्व है ही।

मिज़ोरम के 85 प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र है और इस दृष्टि से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। राज्य में साक्षरता दर 91.58 प्रतिशत है जो देश में तीसरी सबसे ज्यादा दर है। इससे ज्यादा साक्षरता केरल और लक्षद्वीप में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिज़ोरम में 1000 पुरुषों के मुकाबले 975 महिलाएं हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास नीति (एसईडीपी)

मिज़ोरम में वर्तमान सरकार की प्रमुख नीति है सामाजिक-आर्थिक विकास नीति। इस नीति का उद्देश्य अल्पावधि और दीर्घावधि टिकाऊ विकास लाना है। इस नीति को कई भागों में बांटा गया है जिनमें राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास भी शामिल हैं।

प्रशासनिक नीति का असल मकसद प्रभावी प्रशासन की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल करना है। आर्थिक नीति में शामिल मुख्य मुद्दों में कृषि, बागवानी, बांस की खेती, रबड़ की खेती, बुनियादी सुविधाओं का विकास और प्रबंधन, व्यापार और निवेश का वातावरण विकसित करना, आदि विशेष हैं। सामाजिक विकास नीति में जनशक्ति विकास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा वगैरह पर ध्यान दिया जाता है।

मिज़ोरम-खूबियां

मिज़ोरम के 85 प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र है और इस दृष्टि से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। राज्य में साक्षरता दर 91.58 प्रतिशत है जो देश में तीसरी सबसे ज्यादा दर है। इससे ज्यादा साक्षरता केरल और लक्षद्वीप में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिज़ोरम में 1000 पुरुषों के मुकाबले 975 महिलाएं हैं। राज्य के दक्षिण भाग में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं। यह क्षेत्र म्यांमार के अराकान से लगा हुआ है। मिज़ोरम की सभी नदियों का दोहन किया जाये तो यहां 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित की जा सकती है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के आकलन के अनुसार राज्य में लगभग 9.09 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। देश के बांस भंडार में मिज़ोरम का योगदान 14 प्रतिशत है।

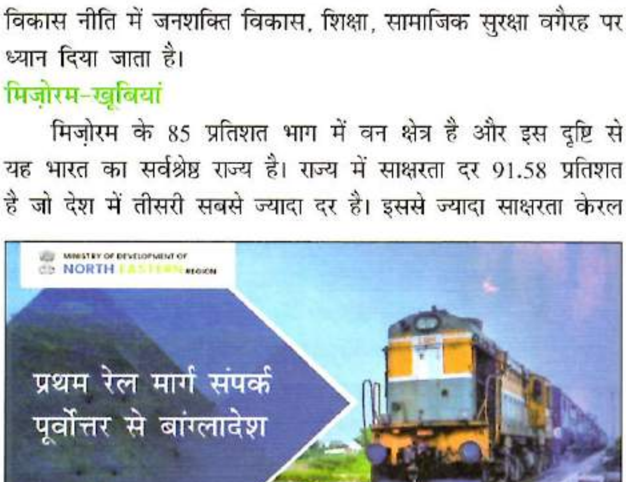

प्रगतिशील समुदाय

मिज़ोरम में वर्गहीन समाज है और समुदाय की बहुत सशक्त भावना है। लोग आमतौर पर मन से अच्छे हैं और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। लोगों के अनुशासित होने का तो इसी बात से पता चलता है कि मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल में कोई भी व्यक्ति हॉर्न नहीं बजाता और ड्राइवर लोग अकारण हॉर्न नहीं दबाते। आम जनता की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि हाईवे के किनारे दुकानें बिना दुकानदार के ही चलती हैं और पूरा कारोबार आपसी विश्वास और भरोसे पर चलता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका साफ दिखाई दी। राज्य सरकार ने राज्य भर में ग्राम/स्थानीय स्तर के अनेक कार्यबल गठित किए जिनका नेतृत्व स्थानीय नेताओं ने ही संभाला था। लॉकडाउन लगाए जाने की स्थिति में मिज़ोरम के स्थानीय लोगों ने पहरा दिया और चौकसी बनाए रखी जिससे राज्य में इस महामारी से बहुत कम मौतें हुईं। स्थानीय स्तर के इन कार्यबलों ने सरकार और विभिन्न धार्मिक संस्थानों के सहयोग से उन गरीब और जरूरतमंद लोगों तक बराबर आर्थिक सहायता और आवश्यक सामान-सामग्री पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई जो लॉकडाउन के कारण परेशानी में हैं।

मिज़ोरम-चुनौतियां

चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य होने के कारण मिज़ोरम के लिए कनेक्टिविटी की समस्या एक बड़ी चनौती है। राज्य में सिर्फ एक ही हवाई अड्डा है- लेंगपुइ हवाई अड्डा। राज्य में एक ही रेल संपर्क है जो असम की सीमा पर स्थित बैराबी में है। अब बैराबी रेल लाइन को सैरंग तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है जो आइज़ोल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है।

मिज़ोरम में कुल दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनमें से एक असम से और दूसरा त्रिपुरा से इसे जोड़ता है। राज्य को असम से जोड़ने वाला राजमार्ग तो वास्तव में मिज़ोरम की जीवनरेखा है। किसी वजह से यह मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो मिज़ोरम का देश के सभी भागों से संपर्क कट जाता है।

दुर्भाग्य ही है कि मिज़ोरम में कैंसर और एचआईवी के रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है और इसकी बड़ी वजह है कि वहां के लोगों की जीवनशैली स्वस्थ नहीं है। राज्य में 67 प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं जबकि धूम्रपान करने वालों का राष्ट्रीय औसत 37

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

मिज़ोरम और मणिपुर में पुनर्विकास परियोजना

- तामेंगलांग-तौसेम-लिसांग-महुर सड़कों (एनएच-37) को 483.87 करोड़ रुपये की लागत से मणिपुर में टू-लेन पक्की सड़क में बदला जाएगा
- भारतमाला परियोजना के तहत मिज़ोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के दुलते-क्वाल्कलह रोड (अंतरराष्ट्रीय गलियारों के खंड को 374.39 करोड़ के बजट के साथ टू-लेन पक्की सड़क का विस्तार

प्रतिशत का है। इस समस्या को देखते हुए यह स्पष्ट है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत कुछ करना जरूरी है।

मिज़ोरम-क्षमता

कृषि, बागवानी और संबद्ध गतिविधियों की दृष्टि से राज्य में अपार संभावनाएं हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान अब भी झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन में ही अटके हुए हैं और पुरानी लीक पर चलकर ही खेती कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र बहुत सी अन्य समस्याओं का भी सामना कर रहा है जिनमें औसत कृषि जोत छोटी होना, किसानों का वृद्ध और अशिक्षित होना, भौगोलिक दृष्टि से जमीन अनुकूल न होना यानी कि जमीन समतल और इकसार न होना, जमीन की उर्वरता घट जाना तथा कृषि मशीनों का अभाव। आज आधुनिक और मशीनों से की जाने वाली खेती बेहद जरूरी है। अभी उत्पादन मुख्य रूप से स्थानीय खपत के हिसाब से किया जाता है जबकि इसे व्यावसायिक स्तर पर लाने की बड़ी जरूरत है। टमाटर, बंद गोभी, ड्रैगन फ्रूट, संतरे, नारियल, लाल मिर्च और केले जैसे बागवानी उत्पादों के मामले में तो मिज़ोरम काफी सफल है। खाद्य प्रसंस्करण अपनाकर इन उत्पादों से और भी ज्यादा आय प्राप्त की जा सकती है। इन सबके लिए, कोल्ड स्टोरेज, कृषि लिंक रोड और आसान पहुंच की भीतर हाट-व्यवस्था उपलब्ध कराने को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पर्यटन और खासकर पर्यावरण पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में भी यहां व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य के स्वच्छ वातावरण, ताजा हवा, आरामदायक जलवायु और घनी हरियाली पर्यटकों के आकर्षण के मुख्य पहलू हैं। यहां की रोमांचक भौगोलिक संरचना साहसिक सैलानियों को मोहने वाली है और ग्रामीण वातावरण में रहने का अनुभव भी बहुत बड़ा आकर्षण है। हैल्थ रिजॉर्ट और वैलनेस केंद्र स्थापित करना भी लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। परन्तु पर्यटन के विकास में एक बड़ी अड़चन है राज्य में लागू इनर लाइन परमिट व्यवस्था जिसके रहते गैर जनजातीय लोगों को राज्य के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। पर्यटन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार पर्यटकों की आवक की दृष्टि से मिज़ोरम सबसे नीचे के स्थान पर है। राज्य में इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

राज्य की विशिष्ट वस्त्र-संस्कृति के बल पर यहां हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में जबरदस्त संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में कुशल और अकुशल, दोनों प्रकार के कारीगरों को रोज़गार मिल रहा है। अगला अनिवार्य कदम होगा राज्य के अनूठे पारंपरिक हस्तशिल्प और आकर्षक रंग-बिरंगी पोशाकों के लिए उपयुक्त बाजार खोजना।

कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना (केएमएमटीटीपी)

भारत सरकार की कलादान मल्टी मोडाल ट्रांजिट परिवहन परियोजना (केएमएमटीटीपी) से पश्चिम बंगाल की हल्दिया बंदरगाह को म्यांमार की सिफ्टले बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है जो बाद में मिज़ोरम के दक्षिण भाग वाली बंदरगाह से होते हुए भारत में पहुंचेगी।

जैसा पहले भी बताया गया है कि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र केवल 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी गलियारे से ही शेष भारत से जुड़ा हुआ है। यह स्थिति सुरक्षा, आवागमन और यातायात सभी प्रकार से खराब है। केएमएमटीटीपी समूचे हालात को बदल देगा क्योंकि इससे नई कनेक्टिविटी बन जाएगी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर लम्बा मार्ग पार करके आने की जरूरत नहीं रह जाएगी। परियोजना का भारत वाला भाग तो लगभग पूरा होने वाला है, परन्तु म्यांमार की तरफ वाले भाग के निर्माण में अभी कुछ अड़चनें हैं जो वहां की मौजूदा राजनीतिक उठापटक के कारण दूर नहीं हो सकी हैं।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी समय से उपेक्षित रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। परन्तु, वर्तमान प्रधानमंत्री की पहल पर अब केंद्रीय मंत्री नियमित रूप से इस क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनसंख्या देश की कुल आबादी का मात्र 3.76 प्रतिशत है (2011 जनगणना) फिर भी केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुल बजट का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता और सामर्थ्य है।

इन आशाओं और सकारात्मक सोच के साथ ही सभी हितार्थियों को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। यह तो सही है कि इस क्षेत्र की अपनी खास चुनौतियां और मुश्किलें हैं लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था- "कठिनाई में ही अवसर छिपा रहता है।" इस क्षेत्र के लोगों को यह अवसर दोनों हाथों से थामना होगा। ■

पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी समय से उपेक्षित रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। परन्तु, वर्तमान प्रधानमंत्री की पहल पर अब केंद्रीय मंत्री नियमित रूप से इस क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनसंख्या देश की कुल आबादी का मात्र 3.76 प्रतिशत है (2011 जनगणना) फिर भी केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुल बजट का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

संस्कृति के माध्यम से विकास

डॉ नरेंद्र जोशी

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर, जल और पवन ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर संभावनाओं के बल पर देश की ऊर्जा राजधानी होने की अपार सामर्थ्य है किंतु अब तक उसका अंश मात्र भी दोहन शायद ही हो पाया है। अपने स्थलों के मनमोहक सौंदर्य तथा जीव-जंतुओं और वनस्पति की विविधता के बावजूद ये क्षेत्र पर्यटन का स्वर्ग नहीं बन पाया है। किंतु इन गुत्थियों को सुलझाने का मुद्दा कुछ नाजुक भी है। हमें आज विकास बनाम संस्कृति नहीं अपितु संस्कृति के माध्यम से विकास की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्य आदि काल से भारत के अखंड और अभिन्न अंग रहे हैं। भारत के साथ-साथ एशिया के लिए भी सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र के चारों तरफ बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, चीन इत्यादि जैसे कई देश हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का 262,230 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत का लगभग 8 प्रतिशत है। यह क्षेत्र, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच का सेतु होने के साथ-साथ तथा चीन के दक्षिणी हिस्से सहित दक्षिण-पूर्व एशिया की जीवंत अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत का प्रवेश द्वार भी है। प्राकृतिक संसाधनों (तेल, गैस, कोयला,जलशक्ति, उपजाऊ भूमि आदि) से समृद्ध यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी बहुत मूल्यवान है क्योंकि इन संसाधनों का दोहन राष्ट्रीय विकास के लिए किया जा सकता है।

सांस्कृतिक संबंध और समृद्ध खज़ाना

अनगिनत प्रमाण बताते हैं कि 10वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वेदों के संकलन काल से लेकर 21वीं शताब्दी तक पूर्वोत्तर भारत के हमारे भाई और बहन भारत माता की अपार संतति में समाहित रहे हैं। युगों युगों से चले आ रहे ऐसे सम्पर्कों और विलय की एक झलक दिखाने का प्रयास इस लेख में किया जा रहा है। पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित आज के बहुत से बुद्धिजीवी जिन्हें मंगोलॉइड (मंगोल प्रजाति) के नाम से पहचानते हैं वे उस काल में किरात कहलाते थे। यजुर्वेद और अथर्वेद दोनों में किरात समुदाय का उल्लेख है। महाभारत में वर्णन किया गया है कि शिव और उमा किरात दंपति का भेष धारण कर अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने आए थे। (वनपर्व का किरात पर्व भाग: उनकी सोने जैसी त्वचा थी)। पूर्व दिशा में अपने सभी विजयी अभियानों में भीम की भेंट विदेह प्रदेश में किरातों से हुई। सभा पर्व में सूर्योदय की आभा से मंडित पर्वतों, लोहित्य नदी और पहाड़ियों से घिरे प्राग्ज्योतिष का वर्णन है। रामायण के किष्किन्धा कांड में किरातों के बारे में लिखा है: वे स्वर्ण, रत्नों से समृद्ध और कपड़ा बुनने में निपुण थे। वे अपने केशों की नुकीली चोटी बांधते थे। श्री एन एन वासु ने अपनी पुस्तक 'सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूप' (कामरूप का सामाजिक इतिहास) में उनकी आदतों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है– सादा जीवन, फल और जडी-बूटियों का भोजन, चर्मछाल पहनना, केशों का जूड़ा बांधना, स्वभाव से मधुर किंतु शस्त्र धारण कर लें तो विकराल स्वरूप, गेहुंआ रंग, बुनाई में निपुण इत्यादि। विष्णु पुराण में किरातों के भारत के पूर्वोत्तर भाग में होने का वर्णन है। यूनानियों ने ईसा पश्चात् पहली शताब्दी में किरातों लोगों के बारे

लेखक विवेकानंद प्रबोधिनी में परियोजना निदेशक हैं।
ईमेल: narendrajoshi1710@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

में सुना था। चीन के एक सेनापति और अन्वेषक केन के अनुसार दूसरी शताब्दी ईस्वी में चीन के साथ व्यापार किरातों के जरिए होता था। उसके बाद सभी नस्लों का विलय पूरा हो गया।

मीननाथ से जुड़ी तंत्र विद्या की एकधारा का संबंध कामरूप जिले से है। 10वीं शताब्दी तक चीन के पास एक सौ तंत्र संहिताएं थीं। सम्माह तंत्र में किरात, भोटा, सिना और महासिना की तांत्रिक संस्कृति का वर्णन है। किंतु यह विलय केवल चित्त यानी विचारों, कल्पना और शब्दों तक सीमित नहीं था। भारत के तत्कालीन शासकों के प्रयासों से इसे मूर्त रूप मिला जो स्वयं को 'धर्म रक्षक' कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करते थे। भारत में राजा ऋषियों के समक्ष शीश झुकाते थे और सांसारिक या शासकीय विषयों में उनसे मार्गदर्शन लेते थे। राजा भास्कर वर्मन ऊर्फ ठगी राजा ऐसे राजाओं में एक प्रसिद्ध नाम है। ठगी राजा को ब्रिटिश शासकों ने बंदी बना लिया था। बंदीगृह में एक संन्यासी ने उनके मन में ब्रिटिश हुकुमत से लोहा लेने की अलख जगाई। इस सृजन युग में, समूचे असम और आसपास के क्षेत्र में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष आज भी मालिनीथान जैसे स्थानों पर सांस ले रहे हैं। वहां पार्वती, इंद्र और नंदी की मनमोहक प्रतिमाएं हैं। सुनपुरा के पास तामरेश्वरी में शैव, शाक्ता और वैष्णव सम्प्रदायों के तीन शिलालेख उपलब्ध हैं। कालिका पुराण में इस क्षेत्र में विष्णुपीठ होने का वर्णन है। कहा जाता है कि मंदिर की खोज में निकले कई बैरागियों ने भूख से या जंगली जानवरों का शिकार होने के कारण अपने प्राण गंवा दिए। 'बुरा बुरी' नामक उपासना की वेदी मिली है जिसे महादेव या आदि बुद्ध की वेदिका माना जाता है। लोहित में ब्रह्मकुंड और परशुराम नाम से तीर्थ स्थल हैं और लोहित जिले के पाया में शिवलिंग स्थल का पता चला है।

12वीं सदी के बाद भी जब सामान्यतः सृजनशीलता के भाव का पतन आरम्भ हो चुका था तब भी भक्ति आंदोलन की सशक्त गूंज इस क्षेत्र में ही नहीं समूचे भारत वर्ष में सुनाई दे रही थी। भारत भूमि पर हर ओर संत ही संत हुए हैं। इस महान देश में संतत्व की प्राप्ति ही महती उद्देश्य रहा है। हालांकि आमजन भी सामान्यतः इस ओर प्रवृत्त था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भला और कहां कबीर, दादु, और तुकाराम जैसे संतों को इस सहजता से स्वीकार किया गया। इन संतों ने इस विशाल भूमि के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करते हुए अपने अनुकरणीय जीवन, प्रेरक उपदेशों और श्रुतिमधुर भक्ति संगीत

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

से वेदों और उपनिषदों का संदेश सभी वर्गों और सम्प्रदायों तक पहुंचाया। उस काल खंड में असम में महान संत शंकरदेव (1449 से लेकर 1669 ईस्वी तक) अवतरित हुए जिन्होंने वैष्णव भक्ति का अनथक प्रसार किया। भारत के अन्य संतों की तरह इन्होंने अधिकांश गूढ़ सत्यों को समझाने के लिए आमजन की भाषा का प्रयोग किया और नामघर, कीर्तन, नाटक जैसी अनेक अवधारणाओं के प्रचलन के साथ भागवत आदि का अनुवाद किया। माधव देव, वामसी गोपाल देव, अनिरुद्ध देव, पुरुषोत्तम ठाकुर आदि इनके अनुयायी थे। इनमें से कुछ ने थोड़ी-बहुत बौद्ध तांत्रिक पद्धतियां भी अपनाईं। गोपाल देव अपनी माता के साथ कालीता से अकामादेश (असम) आए थे। कालीता अकामा देश के पूर्वोत्तर में स्थित था और वहां अबोर (आदि) तथा मिरि रहा करते थे। डॉ ककाती ने इस विचार का समर्थन किया है कि कालीता लोग आर्य या क्षेत्रीय बौद्ध अधिवासी क्षत्रिय थे और पूर्वोत्तर में उनकी वैष्णव बस्ती हुआ करती थी। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में नोक्तियों के मुखिया खुनबाओ, बाली सत्र के राम अटा के अनुयायी हो गए। वे संत नरोत्तम के नाम से विख्यात हैं। भक्ति की सब कुछ समा लेने वाली लहरों की कथा बौद्ध लहर के अध्याय के बिना संपूर्ण नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में बौद्ध अनुयायी रहते हैं। तवांग में मोनपा, शेरदुप्केन महायान बौद्ध मार्ग को मानते हैं तथा दिबांग जिले में खाम्पटि, सिगफोहीनयान बौद्ध मार्ग के अनुयायी हैं। बौद्धों की करीबी जनजातियां भी उनसे प्रभावित हुईं। बौद्ध, शैव, शाक्त और नाथ तंत्रिका को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि मीननाथ ही लुईपा हैं जो अवलोकितेश्वर के समतुल्य हैं। अरुणाचल की सभी बौद्ध जनजातियों में प्रार्थना ध्वज, स्तूप, प्रार्थना-चक्र, पत्थर की दीवारें इत्यादि हैं। ऊं मणि पद्म हमः अर्थात् ओम वह मणि जो कमल पर विराजमान है' का मंत्र पूरे हिमालय में जपा जाता है। यह मंत्र असमिया भाषा में लिखा गया है जो कि लगभग देवनागरी लिपि के समान है, चीनी लिपि के नहीं। ऊं वेदों का मूल तत्व है, उपनिषदों का ब्रह्मनाद है, कई मंत्रों का आदि सूत्र है और जगत के अस्तित्व का आधार है। यह जानना बहुत ही रोचक है कि आदि कथाओं के अनुसार विश्व की रचना 'केयुम' शब्द से हुई। संभवतः दलाई लामा (पद्म मणि) ही संत पद्मसंभव थे। उन्हें उपासना पद्धतियों का जनक माना जाता है जिनका आज भी लद्दाख से ल्हासा तक अनुसरण होता है। 640 ईस्वी में युवराज गोम्पा ने ऊपरी बर्मा और पश्चिमी चीन के हिस्सों तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। उन्होंने चीन की एक राजकुमारी से विवाह किया जिनका उनकी नेपाली पत्नी की तरह ही बौद्ध धर्म की तरफ गहरा रुझान था। दोनों ने उन्हें बौद्ध धर्म अंगीकार करवा दिया। उन्होंने भारत से बौद्ध पुजारी बुलवाए और उन्हें तिब्बती भाषा को भारतीय लिपि में लिखने लायक बनाने को कहा। आज तक तिब्बत भाषा की लिपि वही है। लगभग सभी देवी-देवताओं के नाम संस्कृत में हैं: मंजूश्री, अवलोकित, वज्रपाल, वज्रसत्व, अमितायु आदि। दोरजी नाम का अर्थ होता है वज्र या बिजली और वहां यह सबसे आम नाम है। तिब्बत में कुछ स्थानों पर कई गुफाओं में काली की प्रतिमा देखी गई है जिसे ल्हाबमो कहते हैं। अधिकांश प्रार्थना ध्वजों पर सिंह पर आरुढ़ देवी व्याघ्रेश्वरी की छवि अंकित होती है; ताशी लामा की मुहर पर 'मंगलम' अंकित है। तिब्बत में ताशी का अर्थ मंगलम होता है। देवी मां को तारा या डोल्मा' कहा जाता है।

विकास के मुद्दे को भारतीय संस्कृति और स्थानीय संस्कृतियों, मूल आस्थाओं, जातीय विविधता, जैव विविधता और इस विशाल एवं अद्भुत क्षेत्र की अनूठी किंतु पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के परिपेक्ष्य में देखना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं विकासमूलक पुनर्जागरण हमें पुनः दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व एशिया की प्रबल विनम्र शक्ति बना देगा।

पूर्वोत्तर भारत का वृद्धि संचालक

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर, जल और पवन ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर संभावनाओं के बल पर देश की ऊर्जा राजधानी होने की

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

अपार सामर्थ्य है किंतु अब तक उसका अंश मात्र भी दोहन शायद ही हो पाया है। अपने स्थलों के मनमोहक सौंदर्य तथा जीव-जंतुओं और वनस्पति की विविधता के बावजूद ये क्षेत्र पर्यटन का स्वर्ग नहीं बन पाया है। किंतु इन गुत्थियों को सुलझाने का मुद्दा कुछ नाजुक भी है। हमें आज विकास बनाम संस्कृति नहीं अपितु संस्कृति के माध्यम से विकास की आवश्यकता है।

उद्यमियों की प्रथम-पीढ़ी को मदद देने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम अवसर योजना (एनओएसएसई) बनाई गई है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत सड़कें और राजमार्ग बनाकर, हवाई संपर्क बढ़ाकर, रेल नेटवर्क का विस्तार कर, व्यापार मार्गों को खोलकर तथा सीमा पार व्यापार के लिए ढांचागत सुविधाएं बनाकर क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास पर ज़ोर दिया गया।

विकास के मुद्दे को भारतीय संस्कृति और स्थानीय संस्कृतियों, मूल आस्थाओं, जातीय विविधता, जैव विविधता और इस विशाल एवं अद्भुत क्षेत्र की अनूठी किंतु पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के परिपेक्ष्य में देखना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं विकासमूलक पुनर्जागरण हमें पुनः दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व एशिया की प्रबल विनम्र शक्ति बना देगा। ऐतिहासिक काल में इस क्षेत्र की यही पहचान थी। आधुनिक तरीकों से क्षेत्र का विकास करते हुए भी समृद्ध कला, शिल्प और संस्कृति के साथ गहन एवं सुदृढ़ संबंध रखना और लुप्त हो चुकी पहचान को पुनः प्राप्त करना पूर्वोत्तर भारत की उन्नति का मंत्र हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक भाषण में कहा था, "पूर्वोत्तर भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। दिन-प्रतिदिन मेरा यह विश्वास गहरा होता जा रहा है क्यों कि अब समूचे क्षेत्र में शांति स्थापित हो रही है। शांति, प्रगति और खुशहाली का मंत्र पूर्वोत्तर में गूंज रहा है।" उन्होंने कहा "मणिपुर में नाकेबंदी अब इतिहास की बात हो गई है, असम ने दशकों तक हिंसा का दौर देखा है। त्रिपुरा और मिज़ोरम में भी युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। अब ब्रू-रिआंग शरणार्थी बेहतर जिंदगी का रुख कर रहे हैं।"

लगभग सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों की वृद्धि दर दहाई में पहुंच गई है। जैविक आहार से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक।

जलापूर्ति, बिजली और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए नवीनतम पहल पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (एनईएचआईडीएस) है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। अपने दिव्य नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक दृश्यों और मनमोहक स्थलों तथा अद्भुत पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं, पुरातात्विक स्थलों, स्नेहिल निवासियों, और लुभावने जलवायु के साथ पूर्वोत्तर में पर्यटन की अद्भुत क्षमता है। इसलिए इसका हाल में विशेष संवर्धन किया गया है तथा अब और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए सहायता की गई है। अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। लगभग 885 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 22 परियोजनाएं हाल ही में इन सबके लिए निर्धारित की गई है और अब तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। उपद्रवी गतिविधियां, प्रयासों में कमी और दुर्गम क्षेत्र के कारण लंबे समय तक औद्योगिकीकरण न होना, इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा रहे हैं। लेकिन अब एनईएसआईडी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। उद्यमियों की प्रथम-पीढ़ी को मदद देने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम अवसर योजना (एनओएसएसई) बनाई गई है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत सड़कें और राजमार्ग बनाकर, हवाई संपर्क बढ़ाकर, रेल नेटवर्क का विस्तार कर, व्यापार मार्गों को खोलकर तथा सीमा पार व्यापार के लिए ढांचागत सुविधाएं बनाकर क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास पर ज़ोर दिया गया।

समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के नौ शहरों- अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, नामची, गांगतोक, पासीघाट, ईटानगर और आइज़ोल को 'स्मार्ट सिटी' घोषित किया गया है और पहले चरण में 464 परियोजनाओं के लिए 14,124 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास प्रयासों पर विशुद्ध रूप से बल दिया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 93 प्रशिक्षण केंद्र और 69 कौशल भागीदार काम कर रहे हैं। हाल के एक अध्ययन के अनुसार इनमें 39 कौशल भागीदारों और 48 प्रशिक्षण केंद्रों के साथ असम सबसे ऊपर है, मणिपुर में एक कौशल भागीदार और एक प्रशिक्षण केंद्र है, मिज़ोरम में एक कौशल भागीदार और छह प्रशिक्षण केंद्र हैं, मेघालय में 8 कौशल भागीदार और 10 प्रशिक्षण केंद्र हैं, नगालैंड में पांच कौशल भागीदार और आठ प्रशिक्षण केंद्र हैं, त्रिपुरा में 12 कौशल भागीदार और 16 प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा सिक्किम में तीन कौशल भागीदार और चार प्रशिक्षण केंद्र हैं।

इस क्षेत्र, जनसंख्या और संभावनाओं तथा भारत विरोधी विभाजनकारी ताकतों की तरफ से स्थिति के दुरुपयोग की आशंका, सब बातों को देखते हुए यह प्रयास सराहनीय तो हैं, पर आने वाले समय में इनके संवर्धन एवं नवोन्मेष की जरूरत है। विकास करते समय पर्यावरण एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच सतर्कतापूर्वक संतुलन भी रखना होगा। तथाकथित सभ्य भारत के अन्य भागों तथा विश्वभर में पर्यावरण विनाशक और संस्कृति उन्मूलक आधुनिकीकरण एवं विकास की जो भारी भूलें हुई हैं, उन्हें पूर्वोत्तर में दोहराया नहीं जाना चाहिए। संस्कृति के जरिए विकास ही पूर्वोत्तर के उन्नयन का मूल मंत्र है और यह अवश्य ही हमें लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट संकल्पों में सफलता दिलाएगा। ■

संदर्भ

1. अश्वत्थ, डॉ नरेंद्र जोशी, विवेकानंद केंद्र प्रकाशन
2. डेवलेपमेंट थ्रू कल्चर, एस. गुरुमूर्ति, वीकेआईसी, गुवाहाटी में भाषण
3. नॉर्थईस्ट इंडिया, इंडियाज़ ग्रेटेस्टक एसेट, सेवरल थ्रेट, डॉ नरेंद्र जोशी, एफआईएनएस बुलिटेन
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_India
5. https://in.boell.org/en/2019/03/19/youth-and-infrastructure-development-northeast-india
6. https://www.hindustantimes.com/india-news
7. https://idsa.in/idsacomments/EconomicPotentialofNortheastIndiaAnAssetorThreat_shivanandah_120511
8. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/insurgents-from-other-states-are-considering-arunachal-pradesh-as-a-safe-haven-for-their-hideouts-governor/articleshow/71036802.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि

डॉ एम प्रेमजीत सिंह

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक अनूठी और बेजोड़ विशिष्टताएं हैं। उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधन, सदाबहार घने जंगल, उच्च और विश्वसनीय वर्षा, वृहत जैव विविधता तथा सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, जातीय और सांस्कृतिक विविधताओं का मेल इन विशिष्टताओं में शामिल है। इस क्षेत्र की समशीतोष्ण जलवायु कृषि के लिये अनुकूल है। लिहाजा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों का मुख्य पेशा भी खेती ही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8 राज्य हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इस क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 262230 वर्ग किलोमीटर है। यह समूचे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.12 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल आबादी 4.6 करोड़ से ज्यादा है। क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत भाग मैदानी है। अलबत्ता, असम में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.44 प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लिहाज से असम (34.12 प्रतिशत) पहले और त्रिपुरा (23.48 प्रतिशत) दूसरे स्थान पर है। क्षेत्र में सबसे कम शुद्ध बुवाई क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। फसल तीव्रता पर गौर करें तो त्रिपुरा (156.5 प्रतिशत) पहले, मणिपुर (152.1 प्रतिशत) दूसरे, मिज़ोरम (136.36 प्रतिशत) तीसरे और असम (123.59 प्रतिशत) चौथे स्थान पर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूभाग पर झूम खेती होती है। पूर्वोत्तर का शुद्ध बुवाई क्षेत्र 40 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 13 लाख हेक्टेयर भूभाग भूक्षरण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में सालाना 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है जो देश में कुल बारिश का तकरीबन 10 प्रतिशत है। क्षेत्र की मिट्टी अम्लीय या अत्यंत अम्लीय होने के बावजूद कार्बनिक तत्वों से भरपूर है।

क्षेत्र की आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है। असम को छोड़ दें तो क्षेत्र में बड़े उद्योगों का घोर अभाव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी आजीविका के लिये मुख्य रूप से कृषि और इससे जुड़े उद्यमों पर निर्भर करते हैं। देश के इस भाग के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 56 प्रतिशत हिस्सा कम, 33 प्रतिशत मध्यम और बाकी उच्च ऊंचाई का है। कृषि उपज प्रणाली मुख्यत: सीडीआर किस्म की है। यह प्रणाली आम तौर पर एक फसली होती है। इसमें फसल तीव्रता कम (114 प्रतिशत) और उपज सिर्फ जीवन निर्वाह के लायक होती है। क्षेत्र में जोतों का आकार 1.15 हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1.69 हेक्टेयर है। जोतों का आकार बड़ा भले ही लगता हो मगर भौगोलिक असुविधाओं की वजह से समूची जोत का कृषि के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भूमि के इस्तेमाल का तौर-तरीका अपेक्षाकृत त्रुटिपूर्ण है। इस वजह से ऊपरी मिट्टी का सालाना क्षय 16 टन प्रति हेक्टेयर के अखिल भारतीय औसत से काफी ज्यादा 46 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह जल संचय के समुचित उपायों के अभाव में 42.5 एमएचएम पानी में से सिर्फ 0.88 एमएचएम का इस्तेमाल हो पाता है। कुल सिंचित क्षेत्र का कोई विश्वसनीय आकलन मौजूद नहीं है। विभिन्न स्रोतों से एकत्र जानकारियों से लगभग 20.74 प्रतिशत क्षेत्र के सिंचित होने का संकेत मिलता है। क्षेत्र में उर्वरक का उपयोग भी बहुत ही कम, लगभग 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अरुणाचल प्रदेश में यह सबसे कम (2.7

लेखक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल (मणिपुर) के पूर्व कुलपति हैं। ईमेल: mpremjit55@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

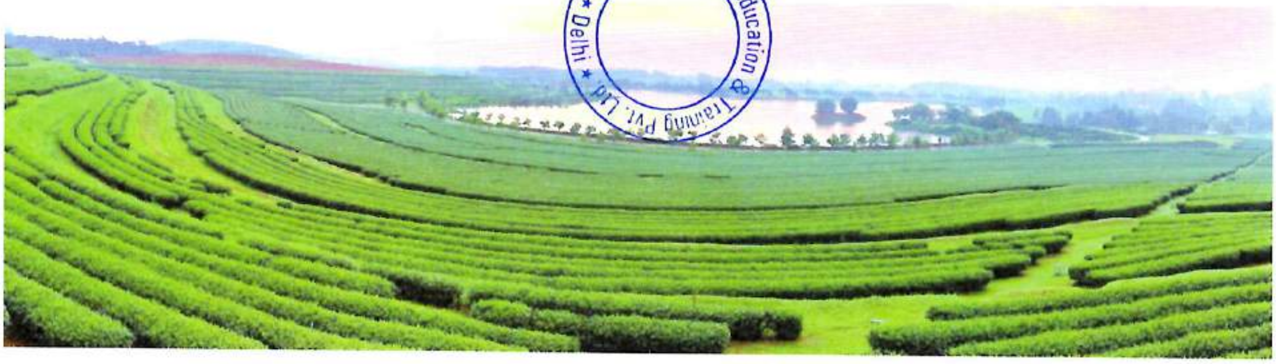

किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) और मणिपुर में सर्वाधिक (72 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) है। कृषि मुख्य रूप से धान पर आधारित है। सिक्किम इसका अपवाद है जहां मुख्य फसल मक्का है। ज्यादातर किसान चाहते हैं कि वे अपने परिवारों की खाद्यान्न और पोषण की जरूरतों को बिना बाहरी स्रोत पर निर्भर हुए खुद पूरा कर सकें। इसलिये वे मिश्रित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं जिसमें बागवानी और भोजन में मांसाहार की प्रमुखता की वजह से पशुपालन भी शामिल है। क्षेत्र में लगभग 85 लाख टन की आवश्यकता की तुलना में कुल 82 लाख टन खाद्यान्न की उपज होती है। इस तरह खाद्यान्न उपज जरूरत की तुलना में 3 लाख टन कम है। पशुपालन की ओर वांछित रुझान के बावजूद दूध की 31.39 लीटर, मांस की 9.36 किलोग्राम, अंडे की 33.50 और मछली की 4.12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्धता ही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां हैं। लिहाजा, गरीबी घटाने और क्षेत्र में प्रगति लाने की कोई भी कोशिश कृषि विकास की सुनियोजित और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्रीय योजना पर आधारित होनी चाहिये। इसके साथ ही क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन और विक्रय प्रबंधन की नीतियों को इसके अनुरूप बनाया जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का कायाकल्प

आर्थिक सुधार की मौजूदा प्रक्रिया ने अनेक अवसरों के साथ ही चुनौतियां भी पेश की हैं। अप्रयुक्त क्षमता के लाभ के दोहन के लिये जरूरी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य समग्र वृहत आर्थिक ढांचे के अंदर विकास की अपनी रणनीति को नयी दिशा दें। मजबूत राज्य ही सशक्त क्षेत्र का निर्माण करते हैं। लिहाजा, व्यापक विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये यह काम जरूरी है। दुर्भाग्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के ज्यादातर राज्य आर्थिक बाध्यताओं और अवसंरचनात्मक सीमाओं की वजह से पिछड़ जाते हैं।

हाल के वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाये हैं। पहले से ही बिगड़ी हुई ग्रामीण आजीविका के मुख्य कारण कम उत्पादकता और कृषि उपज का जोखिम भरा परिवेश हैं। दुर्भाग्य से फलों और सब्जियों, फूलों और जड़ी-बूटियों, मसालों तथा चाय, कॉफी और रबर जैसी बागवानी की फसलों के लिये व्यापक संभावनाओं के बावजूद क्षेत्र में यह स्थिति है। इन उत्पादों में से ज्यादातर का प्रसंस्करण कर देश के बाकी हिस्सों और विदेश में इनका लाभकारी ढंग से व्यापार किया जा सकता है।

कुल खेती योग्य क्षेत्र का छोटा आकार कृषि उत्पादन के तौर-तरीकों के क्षैतिज विस्तार को रोकता है। अरुणाचल प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 2 प्रतिशत हिस्सा शुद्ध बुवाई का क्षेत्र है। मिज़ोरम और मणिपुर में यह 10 प्रतिशत से कम तथा नगालैंड और मेघालय में 13 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 78 प्रतिशत भाग अकेले असम में है। कुल फसल क्षेत्र में से औसतन 74 प्रतिशत में अनाजों की खेती होती है।

ज्यादातर किसान चाहते हैं कि वे अपने परिवारों की खाद्यान्न और पोषण की जरूरतों को बिना बाहरी स्रोत पर निर्भर हुए खुद पूरा कर सकें। इसलिये वे मिश्रित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं जिसमें बागवानी और भोजन में मांसाहार की प्रमुखता की वजह से पशुपालन भी शामिल है।

लेकिन धान आधारित मौजूदा उपज प्रणाली परिवारों के लिये पर्याप्त आमदनी मुहैया कराने में नाकाम रही है। कुल मिला कर देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि का चरित्र कुछ इस प्रकार है -

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र अत्यंत विविधतापूर्ण है। असमतल जमीन, उच्च और परिवर्तनशील वर्षा तथा विभिन्न जातीयताएं इसकी विविधता को बढ़ाती हैं।
2. कृषि पर धान का वर्चस्व है। लेकिन इसकी उत्पादकता कम और उपज अनिश्चित है।
3. भू-भौतिक सीमाओं की वजह से खेती की जमीन का विस्तार मुश्किल है। क्षेत्र के 7 में से 5 राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से खेती की जमीन का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है।
4. क्षेत्र में खेती-पशुपालन-मछली पालन-रेशम पालन के विभिन्न संयोजनों को अपनाये जाने के बावजूद इस विविधीकरण का योगदान नगण्य है।
5. छोटे और सीमांत किसानों की प्रधानता इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। भारत में कुल कृषकों में छोटे और सीमांत किसानों का हिस्सा 59 प्रतिशत है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह अरुणाचल प्रदेश में 65 प्रतिशत से लेकर मणिपुर और नगालैंड में 84 प्रतिशत तक है।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

6. कृषि पर पूर्ण निर्भरता के कारण क्षेत्र में ग्रामीण जनजीवन बाढ़, जलप्लावन और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। इससे गांवों में जीवन स्तर में गिरावट आने के अलावा गरीबी का प्रसार हुआ है।

धान और खाद्यान्न की उपज में आत्मनिर्भरता के लिये रणनीतियां

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्न और खास तौर से चावल की कमी पिछले वर्षों में आबादी में वृद्धि के साथ ही बढ़ती जा रही है। धान की उपज में कमी का एक प्रमुख कारण कृषि के कम उत्पादन वाले स्थानीय तौर-तरीकों का इस्तेमाल है। इस स्थिति के लिये जिम्मेदार अन्य वजहों में बीज और नस्ल की अदला-बदली की न्यून दर, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल, उर्वरक उपयोग की कम कुशलता और आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाये जाने का अभाव शामिल हैं।

नीचे वर्णित रणनीतियों से क्षेत्र में चावल उत्पादन में इजाफा किया जा सकता है –

1. बीज अदला-बदली की दर को बढ़ाया जाये।
2. नस्लों की अदला-बदली की दर में वृद्धि की जाये।
3. सिंचाई सुनिश्चित कर फसल तीव्रता में इजाफा किया जाये।
4. प्रभावी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाये।
5. एसआरआई, आईसीएम और पंक्तिबद्ध रोपण जैसी ज्यादा सघन बुवाई प्रथाओं को अपनाया जाये।
6. मृदा पोषकों के तर्कसंगत इस्तेमाल से मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रखा जाये।
7. विस्तार की प्रणाली पर फिर से विचार किया जाये।
8. ऋण, वित्त और फसल बीमा की सुविधाएं प्रदान की जायें।
9. विपणन सुविधाओं और भंडारण की ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण किया जाये।
10. कृषि का मशीनीकरण किया जाये।

पूर्वोत्तर में बागवानी और पशुपालन क्षेत्र

क्षेत्र में हाल के बरसों में कीवी, कृष्णा फल (पैशन फ्रूट), गैर-मौसमी सब्जियों, एंथूरियम, गुलाब, सुगंधरा (पैचौली) और जेरेनियम की संगठित ढंग से बागवानी शुरू की गयी है। खाद्यान्नों की खेती घाटियों के समतल और कम ढलान वाले इलाकों में की जाती है। दूसरी ओर बागवानी फसलों को ऊंची पर्वतीय ढलानों में उपजाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार क्षेत्र में फलों की 11.20 प्रतिशत और सब्जियों की 14.81 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गयी है। वर्ष 2012 की 19वीं मवेशी गणना के अनुसार पूर्वोत्तर में 132.90 लाख पशु हैं। क्षेत्र में सर्वाधिक 77.56 प्रतिशत मवेशी सबसे बड़े राज्य असम में हैं। उसके बाद त्रिपुरा (7.14 प्रतिशत) और मेघालय (6.74 प्रतिशत) का स्थान है। मवेशियों में सबसे ज्यादा संख्या स्थानीय गायों की है। संकर गायों की संख्या 21 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम सिर्फ 7 प्रतिशत है। सिक्किम (90 प्रतिशत), मिज़ोरम (33 प्रतिशत) और नगालैंड (55 प्रतिशत) में संकर मवेशियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है।

आर्थिक सुधार की मौजूदा प्रक्रिया ने अनेक अवसरों के साथ ही चुनौतियां भी पेश की हैं। अप्रयुक्त क्षमता के लाभ के दोहन के लिये जरूरी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य समग्र वृहत आर्थिक ढांचे के अंदर विकास की अपनी रणनीति को नयी दिशा दें। मजबूत राज्य ही सशक्त क्षेत्र का निर्माण करते हैं। लिहाजा, व्यापक विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये यह काम जरूरी है। दुर्भाग्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के ज्यादातर राज्य आर्थिक बाध्यताओं और अवसंरचनात्मक सीमाओं की वजह से पिछड़ जाते हैं।

पूर्वोत्तर में 1999-2000 और 2012-2013 के बीच मान्यताप्राप्त क्षेत्र में मांस उत्पादन में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह वृद्धि 29 प्रतिशत के राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ क्षेत्र के सभी राज्यों में मांस उत्पादन में वृद्धि हुई है। नगालैंड और मेघालय में संभवत: मवेशियों के बड़े आधार और मांसाहारी भोजन की लोकप्रियता के कारण मांस उत्पादन में बढ़ोतरी काफी रही है।

क्षेत्र में दूध का उत्पादन 1999-2000 में 1021 हजार टन था जो 17 प्रतिशत बढ़ कर 2012-2013 में 1236 हजार टन हो गया। लेकिन इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर दूध उत्पादन में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को छोड़ क्षेत्र के सभी राज्यों में इस काल में दूध उत्पादन में इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्र में मवेशियों की सबसे बड़ी आबादी वाले असम में दूध उत्पादन में वृद्धि की दर धीमी रही। इसकी वजह शायद यह हो कि राज्य में मवेशियों की कुल आबादी का ज्यादातर हिस्सा स्वदेशी नस्लों का है। वर्ष 2012-13 में पूर्वोत्तर में दूध का कुल उत्पादन देश में उत्पादन का महज 0.93 प्रतिशत रहा। क्षेत्र में हरेक व्यक्ति के लिये दूध की उपलब्धता प्रति दिन 86 ग्राम है। यह 299 ग्राम प्रति दिन के राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 29 प्रतिशत है। गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने प्रति व्यक्ति रोज़ाना 220 ग्राम दूध के उपभोग की सिफारिश की है। क्षेत्र में इस दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में गिरावट आयी जबकि राष्ट्रीय

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

औसत में 27 प्रतिशत का सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कम हुई मगर क्षेत्र के बाकी राज्यों में इसमें इजाफा हुआ। पूर्वोत्तर में संकर नस्ल के मवेशियों का औसत दूध उत्पादन प्रतिदिन 6.26 लीटर है। यह 7.02 लीटर प्रति दिन के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भैंसें बहुत कम दूध देती हैं।

नीति परिदृश्य

प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल मौसम और संपन्न मानव पूंजी के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र सामाजिक कल्याण के विशाल अवसरों का फायदा उठा पाने में नाकाम रहा है। इसके परिणामस्वरूप कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं कम उत्पादकता, बेरोज़गारी, न्यून आय और गरीबी के चक्रव्यूह में फंसती जा रही हैं। इससे सामाजिक संकट की आशंका बढ़ गयी है। इस बहुआयामी संकट से निपटने के लिये अंतर-विषयक अनुसंधान समुदाय, नीति निर्माताओं, क्रियान्वयनकर्ताओं, और नागरिक समाज के बीच तालमेल की जरूरत है। क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये समुचित नीति और निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र एक पूरी तरह से वर्षा आधारित उत्पादन प्रणाली का प्रतीक है। यह प्रणाली क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विविधताओं को देखते हुए कृषि और इससे संबंधित उद्यमों के विकास के लिये अलग-अलग तरह की रणनीतियां अपनाये जाने की जरूरत है। कई राज्यों में भू-भौतिक सीमाओं के कारण जोतों का विस्तार मुश्किल होता है। इस तरह के राज्यों में कृषि प्रणाली का उर्ध्व विस्तार उपयोगी होगा। चावल के प्रभुत्व वाले इलाकों में उन्नत 'राइस प्लस' रणनीति अपनाना बेहतर होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोरो धान की फसल की अच्छी संभावना हो सकती है। लेकिन इसके लिये ऐसी उत्पादन प्रणाली की दरकार होगी जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हो। बढ़ती स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिये किफायती और संसाधनों की बचत वाले उपायों के साथ काला जोहा, पचौली और पैशन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों तथा सुगंध और चिकित्सीय उपयोग वाले पौधों को उपजाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में जोतों के छोटे आकार के कारण फसल की उपज सीमित होने के बावजूद संबंधित गतिविधियों के लिये काफी गुंजाइश है उनमें 'कृषि प्लस' की रणनीति की जरूरत होगी। कृषि प्लस का मतलब खेती के साथ ही पशुपालन, बागवानी, फूलों और चिकित्सकीय पौधों की उपज तथा रेशम पालन को अपनाना है। पर्वतीय इलाके उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के साथ ही पशुपालन और रेशम पालन को अपनाये जाने के अनुकूल हैं। इन क्षेत्रों में झूम खेती एक अरसे से की जा रही है। इसमें धान और अन्य फसलों, ऑर्किड जैसे फूलों तथा मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये नवाचारी रणनीति की जरूरत है।
2. मौजूदा कम खर्च वाली खेती को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिये। यह पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी है इसलिये इसे अवसर में तब्दील किया जाना चाहिये। इस संबंध में ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार की संभावना की तलाश करने की आवश्यकता है।
3. पूर्वोत्तर में कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की अब तक घोर उपेक्षा की गयी है। इसमें मूल्य संवर्द्धन और कटाई के बाद नुकसान घटाने की व्यापक संभावनाएं हैं। कृषि प्रसंस्करण और पैकेजिंग में नयी पहलकदमियों को बढ़ावा देने के साथ ही विपणन के नए अवसरों की तलाश की जानी चाहिये। इस संबंध में पड़ोसी देशों के साथ सीमा के आर-पार व्यापार की अच्छी संभावनाओं का उपयोग किया जा सकता है।
4. ग्रामीण संस्थानों को मजबूत और संवेदनशील बनाने के लिये नवाचार पर जोर दिया जाना चाहिये। ज्ञान की व्यापक पहलकदमियों के जरिये क्षमता निर्माण, अनुबंध खेती तथा क्षेत्रीय प्रबंधन समितियों और ग्राम पंचायतों या परिषदों को पुनर्जीवित या मजबूत करना महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएं मूल्यवान सामाजिक पूंजी हैं तथा इनमें ज्ञान के प्रसार का वाहक बनने और ग्रामीण नेतृत्व में सुधार करने की क्षमता है। यह इसलिये भी प्रासंगिक है कि नाबार्ड, नेडफी, सिडबी और आईडीबीआई जैसे वित्तीय संस्थान ऋण की प्रभावी डिलीवरी के लिये समुदाय आधारित संस्थाओं के रेहन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
5. छोटे और सीमांत किसानों के लिये मददगार नयी कृषि प्रौद्योगिकी बनाने के लिये लगातार अनुसंधान और विकास की प्रणाली होनी चाहिये। क्षेत्र में कृषि से संबंधित अनुसंधान और विकास में निवेश पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसे अब बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है।
6. क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था के प्रभावी नीतिगत विश्लेषण के लिये आंकड़ों का अभाव एक गंभीर समस्या है। इसलिये कृषि से संबंधित आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की मदद से प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित किया जाना चाहिये। इस सिलसिले में ई-शासन का बुनियादी औजार आवश्यक है। ■

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्न और खास तौर से चावल की कमी पिछले वर्षों में आबादी में वृद्धि के साथ ही बढ़ती जा रही है। धान की उपज में कमी का एक प्रमुख कारण कृषि के कम उत्पादन वाले स्थानीय तौर-तरीकों का इस्तेमाल है। इस स्थिति के लिये जिम्मेदार अन्य वजहों में बीज और नस्ल की अदला-बदली की न्यून दर, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल, उर्वरक उपयोग की कम कुशलता और आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाये जाने का अभाव शामिल हैं।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

दीर्घावधि शांति और विकास

मृणाल तालुकदार

पिछले दशक में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लम्बे समय तक शांति रही जिससे नए विचार सामने आए और निवेश भी हुआ। अब यह चुनौती सामने आ रही है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाने की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और विकास के प्रमुख क्षेत्रों में उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के नए तरीके खोजे जाएं।

जब नगालैंड के शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप - NagaEd (नागाएड) को मुम्बई के सोशल इम्पेक्ट इनक्यूबेटर अलसिसार इम्पेक्ट में आयोजित इनक्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो नगालैंड के एक अखबार में प्रमुखता से खबर छपी थी। दीमापुर स्थित नागाएड के संस्थापकों : केविसातो सान्युत और शिरोइ लिलिशेज़ा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को सीखने-पढ़ने के अच्छी किस्म के तरीकों के लिए जूझते देखा तो उन्होंने नागाएड बनाने की ठान ली।

कोविड संक्रमण के कारण स्कूल बंद हो जाने के दौर में केविसातो सान्यु और शिरोइ शैजा ने डिजिटल शिक्षण अनुभव के इच्छुक विद्यार्थियों, अध्यापकों और संस्थानों को सीखने और पढ़ाने की यह प्रणाली उपलब्ध कराई।

नागाएड से 'वांडर नगालैंड' तक की यात्रा 4 नवम्बर, 2019 को शुरू की गई थी। 'वांडर नगालैंड' यात्रा के बारे में राज्य का पहला सोशल उद्यम है जो पर्यटन के माध्यम से नगालैंड के आम लोगों को रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास में लगा है।

वांडर नगालैंड के संस्थापकों के अनुसार 'पर्यटन उद्योग' उभर रहा है और अभी नया है। हमें पता नहीं है कि अपने मूल्यों को कैसे प्रदर्शित करें और अभी तक हम पर्यटकों को यह भी

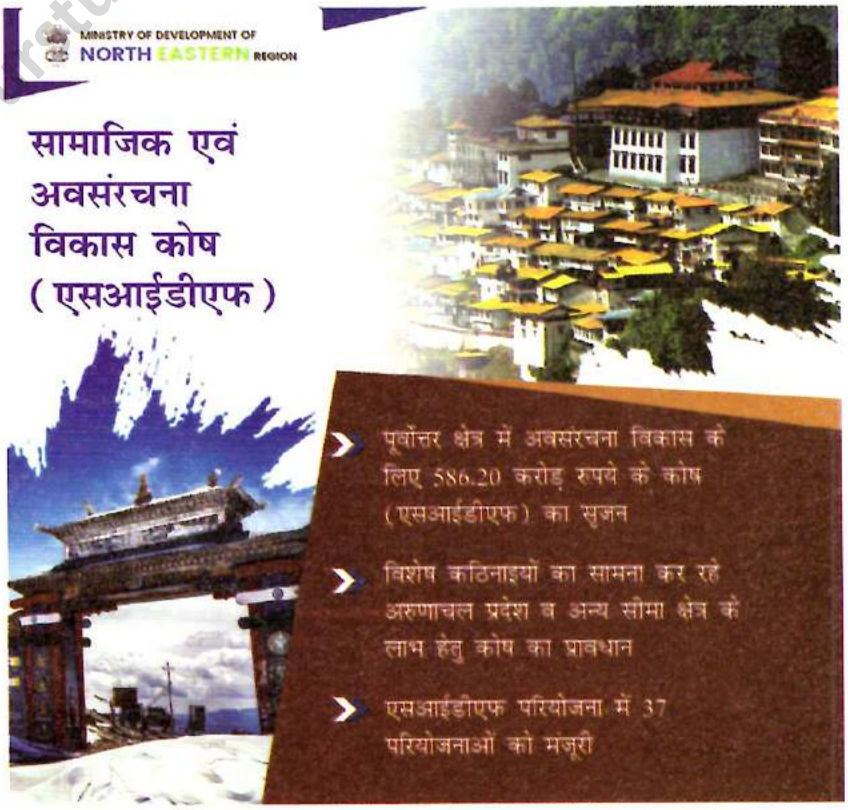

लेखक असम के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ईमेल: mrinal.talukdar@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

नहीं समझ पाए हैं कि हमारे पास उन्हें देने या पेश करने यानी ऑफर करने के वास्ते क्या कुछ है?

आपस में पूरे विश्वास से चल रहे ये दोनों शिक्षित युवा उद्यमी अरुणाचल प्रदेश की मिशिमि हिल्स से मिज़ो हिल्स तथा असम की दो घाटियों तक इम्फाल घाटी और खुले विस्तृत मैदानी क्षेत्र सहित असम का पूरा लैंडस्केप ही बदलने में लगे हैं।

परम्परागत उद्यमों की सीमाओं का विस्तार करके ये लोग ऐसी दुनिया की कल्पना में लगे हैं जिसके बारे में दस साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इसका मुख्य आधार है इस क्षेत्र में लम्बे समय से शांति कायम रहना।

असम के वैंटेज सर्कल की ही बात लें। 2010 में स्टार्ट-अप विचारों पर चर्चा के दौरान दो मित्र अंजन पाठक और पार्था न्याग कर्मचारियों को भागीदार बनाने का कार्यक्रम चलाने की अवधारणा तक पहुंच गए।

पार्था को विभिन्न टेक कम्पनियों में काम करने का दस साल का अनुभव था। उसने कंपनियों की बड़े खर्च करने की प्रवृत्ति से अन्य ब्रांडों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा-समझा। फिर इन दोनों ने 2011 में 30 लाख रुपये की मूल पूंजी से वैंटेज सर्किल शुरू करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत कर्मचारियों के लिए 'डील और डिस्काउंट' कार्यक्रम के तौर पर की गई थी।

आज वैंटेज सर्किल कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने और उन्हें शामिल करने का क्लाउड आधारित व्यापक प्लेटफार्म है जो कॉरपोरेट ऑफर, रिवार्ड एंगेजमेंट कार्यक्रमों के जरिए कंपनी कर्मचारियों को लाभ-पैकेज उपलब्ध करा रहा है।

पिछले वर्ष अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल एक कंपनी ने वैंटेज सर्किल को एम्पलॉई रिवाड्र्स एंड रिकॉगनिशन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा ठेका दिया था। इसके तहत वैंटेज सर्किल का प्लेटफॉर्म अमेरिका और भारत में इन कंपनियों के 90,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अपने रिवार्ड का लाभ आसानी से लेने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप वैंटेज सर्किल को न्यूयॉर्क में भी अपना कार्यालय खोलना पड़ा।

आपस में पूरे विश्वास से चल रहे ये दोनों शिक्षित युवा उद्यमी अरुणाचल प्रदेश की मिशिमि हिल्स से मिज़ो हिल्स तथा असम की दो घाटियों तक इम्फाल घाटी और खुले विस्तृत मैदानी क्षेत्र सहित असम का पूरा लैंडस्केप ही बदलने में लगे हैं। परम्परागत उद्यमों की सीमाओं का विस्तार करके ये लोग ऐसी दुनिया की कल्पना में लगे हैं जिसके बारे में दस साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इसका मुख्य आधार है इस क्षेत्र में लम्बे समय से शांति कायम रहना।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं और पूर्वोत्तर में बदलाव आता जा रहा है क्योंकि नई पीढ़ी अनछुए क्षेत्रों में जाकर चुनौतियों के बीच नए अवसर खोज रही है।

पिछले दस वर्षों के दौरान विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नगा युवा अपने मूल राज्य में ही लौटकर नई संभावनाएं तलाशने की चाहत रखता है।

छिटपुट घटनाएं होती हैं, नगा समस्या के समाधान की प्रगति धीमी है लेकिन शांति अब भंग नहीं हो सकती क्योंकि इस क्षेत्र के सभी लोग सच्चे मन से और पक्के तौर पर चाहते हैं कि वहां शांति बनी रहे। तभी तो कट्टर से कट्टर उग्रवादी भी अब शांति चाहने लगे हैं।

अब नई चुनौती यह है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और प्रमुख विकास क्षेत्रों में इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के नए तरीके खोजे जाएं।

बीती बातें भुला दें – प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सहकार और स्पर्धा पर आधारित संघवाद की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है और 'सभी के लिए एक समाधान' का दृष्टिकोण छोड़कर विभिन्न राज्यों की विविध परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग समाधान अपनाने को कहा है।

सहकारी संघवाद की धारणा के पीछे मूल सोच सरकार के तीन स्तरों के बीच अधिकारों और दायित्वों का विभाजन करना है ताकि योजना निर्माण सबकी भागीदारी बनी रहे। इसी क्रम में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित परिषद को अधिकार देना और राज्यों के बीच समन्वय रखते हुए संगठनात्मक बदलाव लागू करने का जिम्मा भी सौंपना शामिल है।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने पर राज्यों को कुल निधि की 10 प्रतिशत ज्यादा राशि मिलने लगेगी जिससे उन्हें अधिक राजस्व स्वायत्ता प्राप्त होगी। वास्तव में यही केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों और दायित्वों के आवंटन की व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत का संकेत भी है।

यह दायित्व अब राज्यों को सौंप दिया गया है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करें।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

सामाजिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ बने रहने के लिए देश की प्रगति समग्र होनी चाहिए। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी है और सामाजिक-आर्थिक विकास भी धीमा है। यद्यपि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनसे औद्योगीकरण और सामाजिक विकास बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इस क्षेत्र के कई प्राकृतिक पहलू भी हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण परम्परागत घरेलू बाजार तो इस क्षेत्र की पहुंच में हैं ही, कई पूर्वी राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार भी इसकी पहुंच के दायरे में आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों में जाने के लिए यह प्रवेश द्वार है।

पर, अब स्थिति तेजी से बदल रही है, भूतल परिवहन में बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से यह संभव हो रहा है। इस क्षेत्र की दो सबसे तेजी से बन रही सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक 1500 किलोमीटर लम्बी ट्रांस अरुणाचल हाइवे है जो तेजपुर के उत्तर में सेसा से नगालैंड के नज़दीक नाहरकटिया तक जाता है। यह हाइवे अरुणाचल प्रदेश से होकर जाएगा।

दूसरी परियोजना है जिरबाम-इम्फाल रेल-लाइन का निर्माण जिससे मणिपुर को भारत के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 13,809 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कम से कम पांच बड़े पुल बनाए जा रहे हैं जिनमें धुबरी-फुलबारी में विश्व का सबसे बड़ा पुल भी शामिल है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरी तरह से अन्य सभी क्षेत्रों के लिए खुल जाएगा। ये सभी योजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है और विस्तृत कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है तथा जबरदस्त प्रतिभा भी है और इसीलिए यह भारत सबसे समृद्ध क्षेत्र बन सकता है।

पूर्वोत्तर क्रियान्वयन एजेंसी

इस क्षेत्र के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और इसीलिए क्षेत्र के कई इलाकों में काफी प्रगति दिखाई देने लगी है। अपेक्षित सफलता इसलिए नहीं प्राप्त की जा सकी क्योंकि क्रियान्वयन एजेंसियों का योजनाओं में पूरी तरह तालमेल नहीं था। इसीलिए जरूरी है कि क्रियान्वयन क्षमता को अधिक मजबूत करने की योजना बनाई जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन का गठन करना जरूरी है जो परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली निधि की व्यवस्था संभालने के साथ ही प्रत्येक परियोजना के काम की प्रगति आंकने के लिए मॉनीटर दल भी गठित करेगा जो निजी क्षेत्र के चुने हुए भागीदारों के सहयोग से हर योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी निभाएगा और राज्य सरकारों तथा अन्य संबंद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय बनाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में न केवल भारत की आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनने की भरपूर क्षमता है बल्कि देश की बड़ी उपलब्धियों में अहम योगदान करने का सामर्थ्य भी है और यही तथ्य इस क्षेत्र के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष ध्यान केन्द्रित करने से भी उजागर होता है।

इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि और जल स्रोत हैं जिससे यह बागवानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है तथा यहां की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक संपदा का उपयुक्त दोहन करके विकास की गति में और तेजी लाई जा सकती है।

बागवानी, हथकरघा और हस्तशिल्प के अपेक्षाकृत लाभों पर जोर देना तो ठीक है पर ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान देते समय शहरों में रोज़गार मुहैया कराने वाले विनिर्माण उद्योग की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए।

इस क्षेत्र के कई प्राकृतिक पहलू भी हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण परम्परागत घरेलू बाजार तो इस क्षेत्र की पहुंच में हैं ही, कई पूर्वी राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार भी इसकी पहुंच के दायरे में आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों में जाने के लिए यह प्रवेश द्वार है।

वास्तव में 'मेक इन नॉर्थ-ईस्ट' अर्थात दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ व्यापार में कच्चे माल का कारोबार मुख्य है। उदाहरण के तौर पर, मेघालय बांग्लादेश को स्टोन बोल्डर्स, लाइमस्टोन (चूना-पत्थर) और बागवानी उत्पाद निर्यात करता है।

इन्हें प्रोसेस करके चिप्स और सीमेंट बनाकर वापिस भारत को भेज दिया जाता है। इससे मूल्य संवर्द्धन और सीमापार सहयोग को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। बागवानी का भी

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

विस्तार और विकास करने की भी संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में बढ़िया किस्म की हल्दी और अदरख पैदा की जाती है और आसानी से उगने वाले किवी और पैशन-फ्रूट का भी खूब उत्पादन होता है।

परन्तु हाट व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण बागवानी उत्पाद पिछड़े हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन की कमी के कारण भी बागवानी में लगे उत्पादकों को बाजार के उतार-चढ़ाव झेलने पड़ते हैं।

बुनियादी सुविधाओं का विकास न हो पाने के कारण पर्यटन उद्योग खास प्रगति नहीं कर सका। राज्य आपस में तालमेल रखे बिना अपने स्तर पर अलग-थलग प्रयास कर रहे हैं। समन्वित प्रयासों के लिए पूर्वोत्तर प्लेटफार्म (मंच) स्थापित करने, गंतव्य स्थलों का विकास करने, पर्यटन क्षेत्र निर्धारित करने, स्थानीय लोगों को और निजी क्षेत्र को भी शामिल करने जैसे साधारण उपाय तेज गति से लागू करके पर्यटन क्षेत्र के विकास का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास न हो पाने के कारण पर्यटन उद्योग खास प्रगति नहीं कर सका। राज्य आपस में तालमेल रखे बिना अपने स्तर पर अलग-थलग प्रयास कर रहे हैं। समन्वित प्रयासों के लिए पूर्वोत्तर प्लेटफार्म (मंच) स्थापित करने, गंतव्य स्थलों का विकास करने, पर्यटन क्षेत्र निर्धारित करने, स्थानीय लोगों को और निजी क्षेत्र को भी शामिल करने जैसे साधारण उपाय तेज गति से लागू करके पर्यटन क्षेत्र के विकास का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करना पड़ता है। पर, अभी तक बिना खर्च की गई राशि का बड़ा पूल जमा हो चुका है क्योंकि खर्च करने योग्य प्रस्ताव ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की कोई भी नीति लाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि निर्धारित धनराशि खर्च क्यों नहीं की जा सकी। कोई भी दोहरी परियोजना तैयार करने के लिए विभिन्न संस्थानों की विशेषज्ञता का भी लाभ लेना चाहिए।

आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्रोह और घुसपैठ की समस्या से मुक्त हो चुका है। इस सुखद स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में होने वाली छिटपुट घटनाओं की कोई अहमियत नहीं है। देर-सवेर आखिरी बचे 'नगा समझौते' पर भी हस्ताक्षर हो ही जाएंगे।

नगालैंड विधानसभा ने 18 फरवरी, 2021 को ही दशकों पुराने नगा राजनीतिक विवाद को निपटाने के बारे में चार सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें 60 सदस्यों के सदन ने केंद्र और नगा राजनैतिक समूहों के बीच अंतिम समाधान के लिए चल रहे विचार-विमर्श में एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया है।

स्थानीय जलवायु की परिस्थितियां; सुरक्षित और स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण।

केंद्र सरकार नगा-वार्ताकारों के साथ अलग- अलग दो विचार-विमर्श जारी रखे हुए हैं, पहली वार्ता 1997 से एनएससीएन (आईएम) के साथ चल रही है और दूसरी वार्ता राजनीतिक ग्रुपों (एनएनपीजी) के साथ 2017 से जारी है जिसमें सात ग्रुप शामिल हैं। इन क्षेत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और कौशल विकास सुविधाएं बढ़ाने के वास्ते काफी निवेश की जरूरत पड़ेगी, और यह सभी कार्य इस क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता संरक्षण संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर करने होंगे। फिर, योजनाएं क्रियान्वित करके ही विकास संभव हो सकेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय की ओर से शुरू की गई नई पहलों से यह प्रक्रिया और सशक्तर होगी। राज्यों की प्रो-एक्टिव भूमिका पर भी काफी कुछ निर्भर है।

खूबियां

- ब्ल्यू माउंटेन (फवागपुई-मिज़ोरम), पलक लेक (मिज़ोरम), कांगला फोर्ट (मणिपुर), माजुली नदी (असम) जैसे आकर्षक पर्यटक स्थुल;
- अनूठे रिवाज और परम्पराओं वाली जनजाति संस्कृति;
- अनेक टी एस्टेट (चाय बागान);
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी अच्छा स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक,
- बांस के अपार भंडार;
- स्थानीय लोगों ने हथकरघा और बुनकरी का हुनर अपना लिया है;
- पनबिजली परियोजनाओं के लिए लाइमस्टोन (चूना पत्थर) और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि;
- स्थानीय जलवायु की परिस्थितियां; और
- सुरक्षित और स्वच्छ तथा प्रदूषण-मुक्त वातावरण।

खामियां

- समुचित कनेक्टिविटी का अभाव : इस क्षेत्र का बड़ा भाग पर्वतीय है जिससे यहां के राज्यों को सड़क मार्ग पर ही निर्भर रहना पड़ता है और फिर सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। हवाई अड्डों की संख्या कम होने से भी यहां कनेक्टिविटी कम है।
- पर्यटन संबंधी मूलभूत सुविधाएं बहुत सीमित हैं। पर्यटकों के लिए रहने-ठहरने की सुविधा भी मांग के मुकाबले काफी कम है और है भी निम्न स्तर की।
- कुशल और अकुशल श्रमिकों का अभाव
- मानसून के दौरान बाढ़ और भू-स्खलन के कारण इस क्षेत्र में पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

- राज्य में भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण संबंधी कानूनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को ध्यान में रखकर उन परियोजनाओं में निवेश के लिए अनुकूल हालात बनाने होंगे।
- परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण विकास प्रक्रियाएं पिछड़ जाती हैं।
- राज्यों तक पहुंचने के मार्ग अवरुद्ध रहते हैं।

अवसर

- हथकरघा उद्योग का विकास।
- वर्षा के मौसम में राज्य के उन भागों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था करना जिन्हें पर्यटन-स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- मौजूदा पर्यटन सर्किटों से संपर्क विकसित करना और नए सर्किट विकसित करना।
- बुनियादी सुविधाएं और आने-जाने की व्यवस्था में सुधार करके व्यापार में जबरदस्ती वृद्धि की जा सकती है।

खतरे

- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में संसाधनों के बेहद ज्यादा इस्तेमाल और व्यापारिक रवैया अपनाने से संसाधन बर्बाद होते जाएंगे और यहां पर्यटकों के लिए आकर्षण भी नहीं रह जाएगा।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ी चिन्ताएं।
- यदि भूमि बैंक और भूमि उपलब्ध पर ध्यान न दिया गया तो निजी क्षेत्र का विकास रुकने लगेगा।
- स्थानीय लोगों का रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन।

पिछले वर्ष कई पहल की गई हैं और सफलता भी मिली है। उदाहरण के लिए, सरकार ने सड़कों और रेलों के निर्माण के लिए 92,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।

'पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' (एसएआरडीपीएनई) के अंतर्गत ट्रांस अरुणाचल हाइवे विकसित किया जा रहा है। भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच समझौते के तहत शुरू में बसों को और बाद में निजी वाहनों को इन चारों देशों के परमिट पर एक-दूसरे के यहां आने-जाने की सुविधा दी गई है। इसी तरह बांग्लादेश के साथ बस सुविधाएं भी सुधरी हैं।

थोड़े और प्रयास करने और स्थानीय तथा केंद्र सरकार के समर्थन से और लम्बे समय तक शांति बनी रहने पर भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र का जबरदस्त विकास हो सकेगा। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्च्यून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
एडमिशन लेने से पहले जान लें कि आपको कौन पढ़ाएगा!
शिक्षक, जो सुनिश्चित करेंगे आपकी सफलता
श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति
श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स
श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था
श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन
श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे
सामान्य अध्ययन
प्रथम एवं द्वितीय बैच फुल
तृतीय बैच
में नामांकन जारी
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा -
अखिल मूर्ति
भूगोल
द्वारा -
कुमार गौरव
राजनीति विज्ञान
द्वारा -
राजेश मिश्रा
7428085757
7428085758
मिस्ड-कॉल करें:
9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

YH-1592/2021

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

पूर्वोत्तर में शिक्षा

प्रोफेसर के एम बहरूल इस्लाम

दुनिया भर में शिक्षा नीतियों को लोगों की आर्थिक समृद्धि, गतिशीलता और सामाजिक विकास के हिसाब से बदला जा रहा है जानकार लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि किसी भी संगठन या समाज में उपयोगी मानव पूंजी तैयार करने के लिए निवेश की जरूरत होती है। राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई हमारी शिक्षा नीतियां आ[illegible]र पर बेहद जरूरी लक्ष्यों से संचालित होती हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर इन लक्ष्यों को लागू करने के [illegible] (खास तौर पर पूर्वोत्तर में) बारीकी से काम करना होगा। हमारी शिक्षा नीतियों में क्षेत्रीय स्तर पर [illegible] की सख्त जरूरत है, ताकि ऐसा माहौल तैयार हो सके जहां छात्र-छात्राएं रोज़गार हासिल करने [illegible]शिक्षा और प्रशिक्षण का उपयोग कर सकें, अपना जीवन स्तर सुधार सकें और इस इलाके के साम[illegible]ास में अपना योगदान दें।

www.ourstudycircle.in/upscpdf

राष्ट्रीय शि[illegible]20 (एनईपी) का मकसद 21वीं सदी के [illegible]रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में [illegible]ने पर बदलाव करना है। हालांकि, क्या हम क्षेत्रीय स्तर पर अपना शिक्षा प्रणाली और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं? साथ ही, क्या हम तेजी से बदलते समय और कामकाज स्थल पर उभरते तरीकों के हिसाब से अपनी प्रणाली में बदलाव करने के लिए तैयार हैं (विश्व विकास रिपोर्ट, 2019)? अगर ऐसा है, तो भौगोलिक-रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण इस पूर्वोत्तर क्षेत्र को अगले कुछ साल में मानव पूंजी का केंद्र बनाने के लिए कौन से रणनीतिक बदलाव करने होंगे? इस लेख में हम इन मुद्दों की पड़ताल करेंगे। साथ ही, भविष्य की उन गतिविधियों के बारे में जानेंगे जो शिक्षा नीतियों को इस क्षेत्र की वृहतर चुनौतियों से जोड़ती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रणनीतिक योजना बनाते समय हमें इस क्षेत्र की कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा।

यहां सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि पूर्वोत्तर में उद्योगों की मौजूदगी काफी कम है। इस वजह से पूर्वोत्तर के नौजवानों को रोज़गार के लिए पलायन करना पड़ता है। हमारे छात्र-छात्राएं लंबे समय तक 'स्थायी' सरकारी नौकरी पर निर्भर रहे। हालांकि, अब 'पढ़े-लिखे' लोगों की बड़ी तादाद है, जबकि इस तरह की नौकरियों की भारी कमी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में (खास तौर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर) में अब भी पारंपरिक विषयों पर जोर है और संस्थानों से पारंपरिक शिक्षा आधारित डिग्री ही मुहैया कराई जा रही हैं। इसका मोटे तौर पर राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर के उद्योग से कोई संबंध नहीं है, जबकि रोज़गार हासिल करने के लिए किसी खास कौशल से जुड़ी डिग्री जरूरी हो गई है। यह एक तरह से प्रतिस्पर्धी रोज़गार बाजार में 'प्रवेश का जरिया' भी है।

अतः, जब कोई औसत विद्यार्थी किसी स्नातक कोर्स में प्रवेश लेता है, तो न तो विद्यार्थी और न ही किसी शैक्षणिक प्रशासन के पास ऐसी कोई योजना होती है जिससे विद्यार्थी को रोज़गार के आधुनिक ठिकानों में जगह मिल सके। पूरा जोर किसी खास विषय में डिग्री हासिल करने पर है जो एक आदर्श मिशन हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर निकट भविष्य में रोज़गार हासिल करना है, तो इस तरह का एकतरफा रवैया कारगर नहीं होगा। बेशक हमें किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जानकार और बुनियादी शोध करने वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन हमें उस व्यावहारिक जरूरत के बारे में भी सोचना होगा जिसके तहत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के लिए किसी तरह के कौशल या प्रशिक्षण जरूरी है, ताकि बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में उन्हें रोज़गार मिल सके। पूर्वोत्तर

लेखक भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में प्रोफेसर और संस्थान के 'सार्वजनिक नीति तथा सरकार के उत्कृष्टता केंद्र' (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के अध्यक्ष हैं। ईमेल: drbahar@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

क्षेत्र के लिए हमारी शिक्षा नीति के ढांचे में बदलाव इसी सोच के आधार पर होना चाहिए।

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अपनी किताब "रीथिंकिंग द एमबीए: बिजनेस एजुकेशन एट ए क्रॉसरोड्स" में कहा है कि शिक्षा में 'जानने' के बजाय 'करने' और 'होने' पर फोकस होना चाहिए। इसका आशय यह है कि शिक्षा में सिर्फ यह अहम नहीं है कि आप क्या जानते हैं, रोज़गार के संदर्भ में भी इसकी उपयोगिता जरूरी है। पूर्वोत्तर के शिक्षा नीति निर्माताओं को भी इस पर विचार करने की जरूरत है, ताकि हमारी सरकारें, संस्थाएं, प्रशासक और शिक्षक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में इन तीन अहम चीजों को शामिल कर सकें- वैश्वीकरण, नेतृत्व और एकीकरण। हालांकि, इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी नहीं कि मौजूदा प्रणालियों को पूरी तरह उलट दिया जाए पर इन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, शैक्षणिक नियामक इकाइयों, संस्थागत नेतृत्व और शिक्षकों के सहयोग के मामले में रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। अब हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति के स्तर पर इन तीनों बदलावों की संभावना पर बात करते हैं।

विश्व विकास रिपोर्ट 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण की रणनीति के तहत तीन सुझाव दिए गए हैं। पहला हमें ऐसे कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है जिनकी मांग ज्यादा है। साथ ही, ग्रामीण इलाकों और वंचित समुदायों में निवेश करना चाहिए और हमें अपने कार्यक्रमों में ऊंचे स्तर की बौद्धिक और सामाजिक-व्यावहारिक सामग्री को शामिल किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्नातक और परा-स्नातक पाठ्यक्रमों को बनाने वालों को राज्यवार या कम से कम क्षेत्रीय स्तर (इस क्षेत्र के सभी राज्यों की कमोबेश एक जैसी चुनौतियां हैं) पर मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही, अंतर-विभागीय समूह बनाकर यह विचार करना चाहिए कि किस तरह से पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शिक्षा का अटूट हिस्सा बनाया जा सकता है जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था वैश्विक हो सकेगी। यहां वैश्विक होने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य सामग्री को शामिल करना है, ताकि हमारे छात्र-छात्राएं देश के वृहतर आर्थिक संदर्भ के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के रुझानों और बाजार की मांग को समझ सकें। आसान शब्दों में कहें, तो मिज़ोरम या त्रिपुरा के किसी गांव के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को रोज़गार व कामकाज की मौजूदा स्थितियों, देश और दुनिया के बाकी हिस्से के सांस्कृतिक ढांचे आदि से परिचित होना चाहिए।

हमारे अकादमिक कोर्स में पारंपरिक तौर पर किसी विषय से जुड़ी 'ज्ञान' सामग्री, मूल विषय और सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, ताकि उस विषय की मजबूत बुनियाद तैयार हो सके। यह एक बेहतर तरीका है और शायद यही वजह है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को दुनिया भर में इस मजबूत 'बुनियाद' के लिए जाना जाता है जिसे हमारे संस्थानों द्वारा कई

वर्षों में तैयार किया गया है। हालांकि, बदलते वक्त के साथ इसमें बदलाव की जरूरत है। इसके तहत 'नेतृत्व क्षमता संबंधी कौशल' को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राओं को समस्या को हल करने वाले तौर-तरीके सीखने के साथ-साथ अलग-अलग माहौल में काम करने की समझ विकसित हो सके। इस तरह, अलग-अलग लोगों के साथ काम करने की क्षमता और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही की भावना विकसित हो सकेगी। ये तमाम गुण एक दिन में या नौकरी के लिए होने वाले साक्षात्कार से ठीक पहले हासिल नहीं किए जा सकते। इसके लिए हर कोर्स में सत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में शिक्षकों को छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। फिलहाल, यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा छात्र-छात्राओं को इसके लिए खुद पहल करनी पड़ती है। इससे ज्यादातर छात्र-छात्राएं इस कौशल से वंचित रह जाते हैं और नौकरी पाने में भी पिछड़ जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सभी तरह के कोर्स में 'नेतृत्व विकास' को अहम हिस्से के तौर पर शामिल करना चाहिए।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली में 'एकीकरण' से जुड़े कौशल को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह क्षेत्र भारत के मुख्य हिस्से से थोड़ा कटा हुआ है। साथ ही, इसकी अलग और विविधतापूर्ण संस्कृति की वजह से यहां के लोग विकास में थोड़ा अलग-थलग पड़ जाते हैं। हालांकि, इस क्षेत्र के छात्र-छात्राएं भारत के अन्य हिस्सों या विदेश में पढ़ाई करते हैं, तो वे काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अतः हमारी शिक्षा नीति के तहत यहां रहने वालों के लिए ऐसे शैक्षिणक कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि उनके पास चीजों को देखन का समग्र नजरिया हासिल हो सके और ज्ञान के अलग-अलग स्रोत भी उपलब्ध हो सकें। इस लिहाज से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कारगर है, क्योंकि इसमें कोर्स के तहत अलग-अलग तरह की जानकारी का समावेश करने का सुझाव दिया गया है। आज राजनीति शास्त्र के छात्र-छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान का कोर्स भी जरूरी है, ताकि उन्हें सोशल मीडिया राजनीति के

हमारे अकादमिक कोर्स में पारंपरिक तौर पर किसी विषय से जुड़ी 'ज्ञान' सामग्री, मूल विषय और सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, ताकि उस विषय की मजबूत बुनियाद तैयार हो सके। यह एक बेहतर तरीका है और शायद यही वजह है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को दुनिया भर में इस मजबूत 'बुनियाद' के लिए जाना जाता है।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

बारे में बेहतर समझ हासिल हो सके। इससे छात्र-छात्राओं को राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिलेगी और वे राजनीति में तकनीक के मायने समझ सकेंगे। आने वाले समय में हमें राजनीतिक कैंपेन या सोशल मीडिया प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए इसी तरह के पेशेवरों की जरूरत होगी। अगर इसी विषय के छात्रों को सांख्यिकी का कोर्स पढ़ाए जाए तो वे चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी के काम से जुड़ सकेंगे। एकीकरण की प्रक्रिया मौजूदा वक्त की जरूरत है और हमारे शिक्षा नीति निर्माता बेहतर ढंग से इस दिशा में शुरुआत कर सकते हैं।

अगर हम इस क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली को देखें, तो यह कहा जा सकता है कि स्थानीय जगह को ध्यान में रखते हुए भी कुछ पहल की जा सकती है, खास तौर पर 'लुक ईस्ट' तथा 'एक्ट ईस्ट' की सरकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की जा सकती है। बेशक इन नीतियों को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया गया है, लेकिन इस क्षेत्र के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नाम मात्र जगह दी गई है। इस क्षेत्र के एक औसत छात्र-छात्रा को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि वह पूर्व एशिया के देशों में उद्यम, पेशेवर करियर या अन्य रोज़गार पाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह कर सकता है। खास तौर पर, आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों के बीच यह बात और अहम है। इस क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाएं पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक और अन्य संबंधों को और मजबूत कर सकती हैं। साथ ही, साझा सांस्कृतिक इतिहास और व्यापारिक मार्गों के आधार पर भी कोर्स में जरूरी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। अगर इस क्षेत्र के हमारे कैंपस का संवाद आसियान देशों के विश्वविद्यालयों और संयुक्त कार्यक्रमों से बढ़ता है, तो हमारे छात्र-छात्राओं को ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। लिहाजा, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को इस तरह का अकादमिक संपर्क बनाने की दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए।

दो दशक से भी पहले, यूनेस्को ने जैक डेलर्स की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसका शीर्षक था: *'लर्निंग: द ट्रेजर विदइन फॉर द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी* (शिक्षा: 21वीं सदी के लिए शिक्षा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय आयोग के कीमती सुझाव।' इस रिपोर्ट में दुनिया भर में शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई थी। पिछले कई वर्षों से हमारी शिक्षा नीति का आधार यही है। साल 1990 के बाद हुए मुक्त बाजार संबंधी आर्थिक सुधारों और सामाजिक-आर्थिक बदलाव के साथ ही इस रिपोर्ट पर एक बार फिर से गौर करना जरूरी है। साथ ही, हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा नीतियों की भी समीक्षा करनी होगी।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम सुझाव यह है कि छात्र-छात्राओं को अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए, मसलन अगर किसी की दिलचस्पी किसी खास विषय या क्षेत्र में है, तो उसके पास उसका चुनाव करने और सपनों को पूरा करने का विकल्प होना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे नीति निर्माताओं को आने वाले वर्षों में इस बिंदु पर फिर से जोर देने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यह बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'लचीलापन' का प्रमुखता से जिक्र किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ाई के अपने लक्ष्य तय कर अपनी प्रतिभा और दिलचस्पी के हिसाब से जीवन में आगे बढ़ सकें। अतः, अब शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में सभी स्तरों, विषयों और संकायों में अहम बदलाव करने की जरूरत है, ताकि छात्र-छात्राओं को इस 'लचीलेपन' का लाभ मिल सके। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जरूरी बदलाव के बाद राजनीतिक शास्त्र का एक छात्र भी कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जीव विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा। इसके लिए हमारे शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं और संबंधित सरकारी संस्थानों को विषय आधारित मौजूदा ढांचे से अलग हटकर अलग-अलग जरूरी विषयों को एक साथ पढ़ाने का विकल्प मुहैया कराना होगा। इसके तहत, अंतर-संकाय कार्यक्रमों के लिए सामूहिक केंद्र स्थापित करने होंगे, जहां छात्र-छात्राओं को अपनी दिलचस्पी के हिसाब से तमाम विभागों के कोर्स का विकल्प चुनने की सुविधा होगी।

मशहूर अमेरिकी लेखक एल्विन टॉफलर ने अपनी किताब *'पावर शिफ्ट'* (1990) में बताया है कि पैसे और हिंसा की ताकत से निपटने का सबसे सुलभ, सस्ता और लोकतांत्रिक साधन ज्ञान की ताकत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्ञान (संस्थानों में पारंपरिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा) को वास्तविक ताकत में बदलने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके। युवाओं को शिक्षित करने के लिए सिर्फ डिग्री मुहैया कराने वाले कोर्स जैसे पारंपरिक रास्तों का विकल्प पर्याप्त नहीं है। ऊंचे स्तर पर शोध का विकल्प सिर्फ चुनिंदा छात्र-छात्राओं के लिए होना चाहिए, जबकि ज्यादातर छात्र-छात्राओं को शुरुआती दौर में ही करियर या पेशा चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए, ताकि वे जरूरी कौशल सीख सकें। संस्थानों में प्रशिक्षित काउंसलर, कोर्स की योजना बनाने वाले और मार्गदर्शकों के बिना इस तरह की नीति लागू नहीं की जा सकती। अतः, हमें शिक्षकों और प्रशासकों के भीतर ऐसे कुशल लोगों की पहचान कर उन्हें बदलती भूमिका के मुताबिक तैयार कर मार्गदर्शक बनाना होगा। इस तरह के बदलाव का शायद हमें लंबे अर्से से इंतजार है। ■

संदर्भ

1. डाटर, श्रीकांत एम., डेविड ए. गार्विन और पैट्रिक कलेन (201)। रीथिंकिंग द एमबीए: बिजनेस एजुकेशन एट ए क्रॉसरोड्स। बोस्टन: हार्वर्ड बिजनेस प्रेस।
2. डेलर्स, जे (1996)। लर्निंग: द ट्रेजर विदइन। पेरिस: यूनेस्को।
3. टॉफलर, ए. (1990)। पावरशिफ्ट। न्यूयॉर्क: बंटन।
4. विश्व विकास रिपोर्ट (2019): द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। वॉशिंगटन डीसी, द वर्ल्ड बैंक।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

सही दिशा में

Xplore IAS

IAS ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध PCS

वैकल्पिक विषय

राजनीति विज्ञान

व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित, आसानी से तैयार किया जाने वाला, लोकप्रिय एंव अंकदायी विषय

सामान्य अध्ययन, निबंध एवं साक्षात्कार की तैयारी में सर्वाधिक सहायक विषय

डा. जितेन्द्र श्रीवास्तव

दिल्ली–इलाहाबाद के अग्रणी संस्थानों में 20 से अधिक वर्षो से अध्यापनरत

राजनीति विज्ञान ऑनलाइन कोर्स की विशेषता

Fee ~~₹ 27500~~ ₹ 9500

★ सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समकालीन प्रासंगिक मुददो व परीक्षा में पूछे गये प्रश्नो की प्रकृति को ध्यान में रखकर अध्यापन ★ प्रत्येक कक्षा को पूरे कोर्स के दौरान अनगिनत बार देखने की सुविधा ★ नियमित लाइव डाउट क्लासेज व व्यक्तिगत ऑनलाइन परामर्श ★ Concept, Approach & Answer writing पर विशेष बल ★ पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गये व भविष्य के संभावित प्रश्नों की चर्चा व लेखन अभ्यास ★ प्रत्येक टॉपिक की समाप्ति पर Updated Notes ★ पूरे पाठ्यक्रम के दौरान 9 टेस्ट, मूल्यांकन व फीडबैक ★ मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए निशुल्क Revision व Practice batch

A Quality Batch for
G.S Pre
डा. जितेन्द्र श्रीवास्तव व अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा
Fee ~~₹ 12500~~ ₹ 4500

A Special Batch for
Polity, I.R. Governance
(G.S Paper-II)
डा. जितेन्द्र श्रीवास्तव
Fee ~~₹ 10500~~ ₹ 5500

Online Test Series
Prelims 2021
Test 1 to 10
हिन्दी माध्यम
Fee ~~₹ 1500~~ ₹ 499

Visit- Xplore IAS Youtube Channel

9076720077
9315683899

Download Mob. App - Xplore IAS From Google Play Store

YH-1606/2021

www.ourstudycircle.in/upscpdf

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

अब उपलब्ध है...

प्रकाशन विभाग
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)
तथा
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
का प्रकाशन

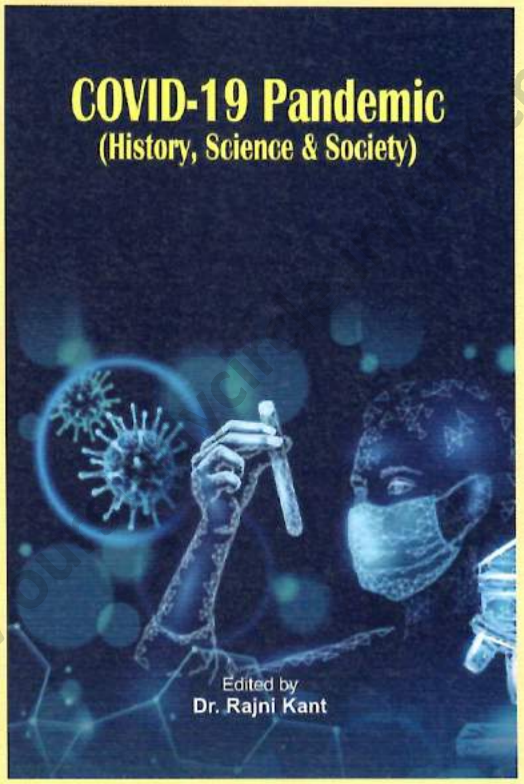

मूल्य - ₹ 215/-

कोविड-19 पेंडेमिक
(हिस्ट्री, साइंस एंड सोसाइटी)

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

अनुवाद – विश्व को समझने का एक माध्यम

अनुराग बसनेत

अनुवाद दुनिया के लिए खिड़कियां खोलता है, जो अन्यथा हमेशा बंद रहेंगी। यह संस्कृतियों और लोगों के बीच समझ का सेतु बनाने के अवसर प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहां कई संस्कृतियों का संगम है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोकप्रिय मुख्यधारा की कल्पना में, पूर्वोत्तर भारत एक एकाश्म (मोनोलिथ) है। फिर भी इस निकटवर्ती क्षेत्र के भीतर कई उप-राष्ट्रीयताएं पनपती हैं। ऐतिहासिक रूप से, पूर्वोत्तर के लोगों की यह शिकायत रही है कि 'मुख्य भूमि' का भारत उन्हें समझता नहीं है। उनकी इस शिकायत को दूर करने का एक तरीका पूर्वोत्तर की भाषाओं से अधिक से अधिक अनुवाद करना है। विशेष रूप से उन भाषाओं से अधिक अनुवाद होना चाहिए जिनका अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है जैसे कि नेपाली, बोडो, कुकी, मिज़ो, कोकबोरोक, मेतेई और अन्य। इसी तरह, अन्य भाषाओं की अधिक से अधिक सामग्री का इन भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए।

भारत के मैदानी इलाकों से लेकर कई पहाड़ी राज्यों तक के राजमार्गों पर, सबको सामान्य यातायात बाधाओं का सामना करना पड़ता है। धीमी गति से चलने वाले ट्रक सामग्री को घाटियों में नदी किनारों से पहाड़ियों पर तेजी से फैले निर्माण स्थलों तक ले जाते हैं। जैसे ही ट्रक पहाड़ी क्षेत्रों में रेंगते हैं और सड़क पर गांवों से गुजरते हैं तो कुछ रेत हवा से उड़ जाती है या सड़क किनारे गिर जाती है या यदि गीली हो तो स्थिर ड्रिप में बह जाती है। रेत धूल से आवास में बदल जाती है, लेकिन नदी के तल से निकलने वाली समूची रेत ठोस नहीं बन पाती है।

लेखक एसआरएम विश्वविद्यालय (सिक्किम) में पत्रकारिता व जन संचार संकाय के विभागाध्यक्ष हैं। ईमेल: anuragbasnet@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

अनुवाद बहुत कुछ ऐसा ही है। मूल पाठ एक भाषा, एक रूप से दूसरी भाषा में रूपांतरित होता है, लेकिन पाठक के लिए यह जानना असंभव है कि इस प्रक्रिया में लेखक का अर्थ, सुझाव और इरादा उस तक कितना पहुंच पाया।

हमारी भाषाएं कई स्रोतों से निकली हैं। ये हैं- संस्कृति, इतिहास, धर्म, आस्था, भूगोल, स्थलाकृति और अन्य। जो तीन भाषाएं मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनमें से जब मैं हिंदी और नेपाली से अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं तो मुझे इस नुकसान का गहरा अनुभव होता है। इस रूपांतरण के सूत्रधार के रूप में, मुझे अच्छी तरह पता है कि कितनी रेत उड़ गई है।

सीढ़ियों की तरह दिखने वाले रास्ते या सीढ़ियां बनाने के लिए हम अपनी पहाड़ियों को काटते हैं। इसे 'वेदिका कृषि या सीढ़ीदार खेती' कहते हैं। मैंने हमेशा कल्पना की है कि जिस व्यक्ति ने इसे यह नाम दिया है, उसने इसे दूर से देखा और इस प्रकार का नाम दे दिया। करीब से जानें तो ये जीवनदायी क्षेत्र हैं जहां हम चावल, मक्का, दालें, सब्जियां, फूल आदि उगाते हैं। नेपाली में, प्रत्येक सीढ़ी के लिए एक नाम है, 'गड़ा'। सीढ़ी के बाहरी किनारे को 'कनला' कहते हैं और उसका भीतरी छोर 'भिट्टा' कहलाता है, दीवार जो अगले चरण के कनला का आधार बनाती है। चावल की खेती के लिए बहुत अधिक बहते पानी की आवश्यकता होती है और हर कुछ वर्षों में सीढ़ी के अंदरूनी छोर को पहाड़ी की ढाल की तरह काटना पड़ता है। इस प्रक्रिया को 'भिट्ठाछिलनु' कहा जाता है, जो कटाव की भरपाई करने तथा रोपण के लिए और अधिक जगह बनाने के लिए है। वे सिंचाई चैनल जो पहाड़ियों से नीचे की ओर बहते हैं, छोटी नदियों से पौधों की जड़ों तक पानी लाते हैं, कुलो कहलाते हैं। अंग्रेजी में बहुत कम या बिना किसी शब्द लहर के साथ, इन शब्दों की व्याख्या करने में अर्थ को सटीक रूप से बताए बिना मूल पाठ को बेरहमी से बड़ा कर दिया जाता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर ग्रामीण परिवार बड़े होते हैं। इसका एक कारण साक्षरता की कमी है, इसलिए उनका सरल आर्थिक तर्क है- ज्यादा बच्चों का मतलब है जमीन की जुताई में ज्यादा हाथ। हालांकि अब जैसे-जैसे कृषि से इतर आजीविका के अधिक आकर्षक साधनों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, यह सोच भी बदल रही है। आमतौर पर, प्रत्येक बच्चे को घरों में जातिगत नाम से बुलाया जाता है। जन्म के क्रम में बेटों के लिए 'जेठा, मैला, सैनला, कैनला तथा कांछा' और बेटियों के लिए 'जेठी, मैली, सैनली, कैनली और कांछी'। जिनके पांच से अधिक बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए और भी नाम हैं। जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, ये नाम पक्के हो जाते हैं और वे अपने समुदायों में अपने कुल या कबीले के नाम और अपने जन्म के क्रम से जाने जाते हैं। वास्तव में, यह सामान्य है कि किसी का पहला नाम उसकी मृत्यु के दिन तक कभी नहीं जाना जाना। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को 'बसनेत जेठा' कहा जाता है, तो इसका शाब्दिक अनुवाद होगा पैदा हुआ पहला बेटा या यहां तक कि पहला भाई बेसनेत जो हास्यास्पद लगता है। इस प्रकार बसनेत जेठा का किरदार बना रहता है। लेकिन अंग्रेजी में ये नाम पाठक के सामने कभी भी उस समाज की भावना को व्यक्त नहीं कर पाएंगे जिसमें व्यक्ति पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं के भीतर समाया हुआ है, या कई संतानों का पालन करने वाले परेशान माता-पिता द्वारा उसकी इतनी उपेक्षा की जाती है कि उसे यहां तक कि पहले नाम की साधारण विलासिता भी नहीं मिल पाती है। टेढ़े थामी नाम को भेंगा थामी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन एक इंसान को संबोधित करने के लिए उसकी शारीरिक विकृति का उपयोग करने में निहित लापरवाह, अर्ध-स्नेही अवमानना की परतें ज्यादातर धीरे-धीरे हट गई हैं। इसी तरह की समस्या 'बास्तेय' नामक चरित्र के साथ उत्पन्न होती है, जो स्वयं 'बासत्ते' का संकुचन है या उसके लिए है जो वर्ष 1962 में पैदा हुआ था। अनुवादक के रूप में, मेरे पास 'बास्तेय' को बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इससे किसी समाज में प्रचलन के अनुरूप यदि किसी परिवार में इतने अधिक बच्चे हों कि उनकी पहचान उनके जन्म के वर्ष से ही होती हो तो यह अर्थ पूरी तरह खो जाता है।

इन समस्याओं से निपटने के लिए एक स्वीकार्य रणनीति यह हो सकती है कि संदर्भ का अर्थ स्पष्ट किया जाए। लेखक, लिखने की भाषा चुनते समय, अपने पाठकों के बारे में स्वाभाविक धारणाएं बनाता है। वे क्या जानते हैं, वे क्या समझते हैं, और वे पाठ, उपपाठ और अर्थ को कितनी अच्छी तरह समझेंगे। किसी श्रोता विशेष के लिए जो पूरी तरह से स्पष्ट है वह दूसरे के लिए अभेद्य हो सकता है। बेशक, लेखक और पाठक के बीच एकसमान अनुभव और संस्कृति भी हैं। ये पारस्परिक रूप से साझा किए गए अनुभव गहरा अर्थ बनाते हैं जो अनकहा रहता है और समझा दिया जाता है। अनुवादक कितना भी कुशल क्यों न हो, संदर्भ के लिए पूरी तरह से लेखक पर निर्भर होता है।

लेखक, लिखने की भाषा चुनते समय, अपने पाठकों के बारे में स्वाभाविक धारणाएं बनाता है। वे क्या जानते हैं, वे क्या समझते हैं, और वे पाठ, उपपाठ और अर्थ को कितनी अच्छी तरह समझेंगे। किसी श्रोता विशेष के लिए जो पूरी तरह से स्पष्ट है वह दूसरे के लिए अभेद्य हो सकता है। बेशक, लेखक और पाठक के बीच एकसमान अनुभव और संस्कृति भी हैं। ये पारस्परिक रूप से साझा किए गए अनुभव गहरा अर्थ बनाते हैं जो अनकहा रहता है और समझा दिया जाता है। अनुवादक कितना भी कुशल क्यों न हो, संदर्भ के लिए पूरी तरह से लेखक पर निर्भर होता है।

दार्जिलिंग के प्रत्येक नागरिक के लिए तुरंत पहचाना जाने वाला 'सिआर्पी' शब्द जिले के बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए अस्पष्ट है। यह समझाने के लिए फुटनोट का सहारा लेना चाहिए कि यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए स्थानीय भाषा है। यदि धमकी का अनुवाद लें जिसे दार्जिलिंग के ठग इस्तेमाल करते हैं- भुगतान करें, वे कह सकते हैं, या मैं तुम्हें छह इंच कम कर दूंगा। यहां, गलत व्याख्या को रोकने के लिए एक फुटनोट की आवश्यकता है। छह इंच कम करना, सिर काटने के लिए बोलचाल की अभिव्यक्ति है।

www.ourstudycircle.in/upscpdf/

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

मैं जब भी अनुवाद करने के लिए बैठता हूं तो इस तरह की कुछ समस्याएं सामने आती हैं। मुझे लगता है कि सभी अनुवादकों के लिए ऐसा ही होता होगा और हमें उनसे निपटने के तरीके ढूंढने होंगे।

भारत में पुस्तक प्रकाशन उद्योग, विशेष रूप से व्यापार प्रकाशन, अपारदर्शी है। पश्चिम में मजबूत बुक एजेंटिंग का उप-उद्योग भारत में बहुत छोटा है। जब प्रकाशन कंपनियां अपनी वेबसाइटों के माध्यम से प्रस्तुतियां आमंत्रित करती हैं, तो उन्हें अपना काम भेजकर पांडुलिपि को एक तेज़ बहती नदी में फेंकने जैसा महसूस हो सकता है। यह पूरी तरह से उनकी भी गलती नहीं है। भारत में अधिकांश प्रकाशन कंपनियों, खासकर उनके संपादकीय विभाग में कम कर्मचारी होते हैं। यह सबसे बड़ी कंपनियों के लिए भी सच है। लेकिन यह जानने से किसी नए लेखक या अनुवादक को जरा भी मदद नहीं मिलती।

किसी भी अन्य कारोबार की तरह प्रकाशन भी एक व्यवसाय है। निवल लाभ के दबाव का मतलब है कि जोखिम की भूख, जो पहले ही बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम हो गई है। प्रकाशक लगातार अगली सबसे अच्छी चीज की तलाश में रहते हैं। बड़ा विक्रेता व्यवसाय को अधिक लाभ कमाने की ओर ले जाएगा और अगली बड़ी चीज सेलिब्रिटी आत्मकथाएं होंगी, वर्तमान और अतीत दोनों।

अधिक से अधिक संस्थानों को इसमें शामिल होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी, दोनों विश्वविद्यालयों में भाषा विभाग के साथ अनुबद्ध अनुवाद विभाग होने चाहिएं जो ग्रंथों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। साथ ही, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है। डिजिटल स्पेस का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पोर्टल, अनुवाद प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। www.rekhta.org उर्दू लेखन के लिए इसे बखूबी प्रदर्शित करता है।

हमारे जैसे महत्वाकांक्षी देश में, पुस्तकें जो हमें दुबला, मोटा, होशियार, तेज, मजबूत, शांत, अधिक आध्यात्मिक तथा गर्व करने योग्य स्थान यानी शीर्ष पर किसी और से पहले पहुंचना सिखाती हैं। यह एक बाजार है, जिसमें एक उच्च प्रोफाइल और एक उभरती हुई आवाज को एक बड़ा गुण माना जाता हैं। विशेष रूप से साहित्यिक प्रकार की कथाओं पर ध्यान जाना मुश्किल है। अनुवाद, किसी कारण से, साहित्यिक होने का पूर्वाभास दिलाता है। ऐसे में उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अनुवाद प्रकाशित नहीं होते हैं। वो प्रकाशित होते हैं। बड़े प्रकाशक के पास अनुवाद की बड़ी सूची रहती है, हालांकि उसका बाजार भी कम हो रहा है। इस सिकुड़ते बाजार को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अन्य प्रश्न पुस्तक प्रकाशन के अर्थशास्त्र का है। अपने पश्चिमी समकक्षों के विपरीत, भारतीय प्रकाशक शायद ही कभी अनुवादकों को उनके काम के लिए एकमुश्त शुल्क देते हैं। ज्यादातर मामलों में, रॉयल्टी प्रणाली अनुवाद के मामले में उसी प्रकार काम करती है जैसे कि यह किसी अन्य प्रकार की पुस्तकों

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

में। रॉयल्टी प्रणाली के तहत, कवर मूल्य का प्रतिशत - 8 से 10 प्रतिशत के बीच होता है जो इस पर निर्भर करता है कि पुस्तक पेपरबैक या हार्डबैक के रूप में प्रकाशित हुई है। प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या कम यानी 1,500 से 3,000 प्रतियों के बीच रहती है और कीमतें भी कम होती हैं। एमेज़ॉन पर देखें तो शायद ही आपको 899 रुपये से अधिक कीमत की किताबें मिलेंगी, बशर्ते कि वह कोई अकादमिक पुस्तक न हो। लिफाफे के पीछे की गणना आपको बताएगी कि एक लेखक अपनी पुस्तक पर कितना कमाता है। यदि कोई पुस्तक बेस्टसेलर नहीं बन पाती तो वह मामूली रकम ही कमा पाता है। अनुवाद के मामले में, लेखक और अनुवादक के बीच रॉयल्टी साझा की जाती है, जिससे यह राशि और भी कम हो जाती है।

भारत में अधिकांश प्रकाशन कंपनियों खासकर उनके संपादकीय विभाग में कम कर्मचारियों होते हैं। यह सबसे बड़ी कंपनियों के लिए भी सच है। लेकिन यह जानने से किसी नए लेखक या अनुवादक को जरा भी मदद नहीं मिलती।

तो अनुवाद क्यों करें?

ऐसी निराशा के सामने इस प्रश्न का विशेष महत्व है।

मैं अनुवाद को अंतिम पाठक की अनुशंसा के रूप में सोचना पसंद करता हूं। पढ़ना एक एकांतवासी गतिविधि है लेकिन एक बार जब हम किसी पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं, और अगर हमें यह पसंद आती है, तो सबसे पहले अपने मित्र को इसे पढ़ने की सिफारिश करते हैं। अनुवाद भी बस यही है। यह दुनिया से यह कहने का एक तरीका है कि मुझे यह किताब उस भाषा में मिली जिसे मैं जानता हूं और आप भी इसका उतना ही आनंद लें जितना मैंने लिया।

एक एकांतवासी अभ्यास, अनुवाद बेहद संतोषजनक भी है। जब मैं लेखक के इरादे, लय और विभक्ति के सबसे करीब आने का प्रयास करता हूं, तो मैं वैसा ही महसूस करता हूं जैसा कि एक गणितज्ञ किसी जटिल समस्या का समाधान करते समय करता होगा।

हमें अनुवाद अवश्य करना चाहिए। अनुवाद दुनिया के लिए खिड़कियां खोलता है, जो अन्यथा हमेशा बंद रहेंगी। यह संस्कृतियों और लोगों के बीच समझ का सेतु बनाने के अवसर प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहां कई संस्कृतियों का संगम है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोकप्रिय मुख्यधारा की कल्पना में, पूर्वोत्तर भारत एक एकाश्म है। फिर भी इस निकटवर्ती क्षेत्र के भीतर कई उप-राष्ट्रीयताएं पनपती हैं। ऐतिहासिक रूप से, पूर्वोत्तर के लोगों की यह शिकायत रही है कि 'मुख्य भूमि' का भारत उन्हें समझता नहीं है। उनकी इस शिकायत को दूर करने का एक तरीका पूर्वोत्तर की भाषाओं से अधिक से अधिक अनुवाद करना है। विशेष रूप से उन भाषाओं से अधिक अनुवाद करना है जिनका अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है जैसे कि नेपाली, बोडो, कुकी, मिज़ो, कोकबोरोक, मेइती और अन्य। इसी तरह, अन्य भाषाओं की अधिक से अधिक सामग्री का इन भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए।

तो आगे का रास्ता क्या है? मुझे नहीं लगता कि अनुवाद के अनुकूल व्यवस्था को विकसित करने के लिए केवल प्रकाशन बाजार पर निर्भर होना एक व्यावहारिक योजना है। अधिक से अधिक संस्थानों को इसमें शामिल होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी दोनों विश्वविद्यालयों में भाषा विभाग के साथ अनुबद्ध अनुवाद विभाग होने चाहिएं जो ग्रंथों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। साथ ही, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है। डिजिटल स्पेस का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पोर्टल, अनुवाद प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। www.rekhta.org उर्दू लेखन के लिए इसे बखूबी प्रदर्शित करता है। ग्रोव अटलांटिक के अध्यक्ष और प्रकाशक मॉर्गन एंट्रेकिन द्वारा 2015 में शुरू की गई एक दैनिक साहित्यिक वेबसाइट लिटरेरी हब भी एक उत्कृष्ट मॉडल है। महत्वपूर्ण रूप से, अनूदित पुस्तकों को स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में अधिक व्यापक रूप से शुरू किया जाना चाहिए।

द मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अनुवाद कार्य देने तथा उसे प्रकाशित करने का काम करती है। संभवत: इस तरह की और कॉरपोरेट संस्थाओं को निवेश के रूप में नहीं, बल्कि अनुदान के रूप में पूंजी लगाने के लिए राजी किया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि अनुवादकों को उनके प्रयासों के लिए समुचित भुगतान किया जाए तो हमें विभिन्न भाषाओं से और भी अधिक तथा ज्यादा गुणवत्तापूर्ण अनूदित रचनाएं मिल सकती हैं।

साहित्य अकादमी ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी के साथ-साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच व्यापक अनुवाद कार्यों को प्रोत्साहित किया है। 24 भाषाओं में दिया जाने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसका भारत-व्यापी नेटवर्क है और इसका इतिहास 1954 से है। अकादमी विशाल परिमाण में रचना करने वाली संस्था भी है। इसकी वेबसाइट बताती है कि यह हर 19 घंटे में एक पुस्तक प्रकाशित करती है। हालांकि ये किताबें बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती हैं। इस तरह के नेटवर्क और समर्थन वाली एजेंसी निश्चित रूप से अपनी पुस्तकों को प्रभावी ढंग से पैकेज और विपणन करने के लिए और बहुत कुछ कर सकती है। अनुवाद और अनुवादकों को बढ़ावा देने का एक अन्य तरीका भारत की विभिन्न भाषाओं में वार्षिक अनुदान की स्थापना करना है, जो किसी बड़ी परियोजना के लिए वित्तीय अनिश्चितताओं को दूर कर सकता है।

सबसे बढ़कर, हमें जो करना चाहिए वह है जिज्ञासु बनना। अपनी दुनिया के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, उन साथी-नागरिकों के बारे में जानने की जिज्ञासा होना जरूरी है जिनके साथ हम अपने देश में रहते हैं। इन वर्षों में, हमने बहुत कुछ सोचा है कि भारत भाषाओं, संस्कृतियों और लोगों के बारे में हम भिन्न-भिन्न विचारों पर चर्चा की स्थिति में हैं। यदि हम अनुवाद द्वारा प्रदान की जाने वाली खिड़कियों को देखने में रुचि नहीं रखते यानी विश्व को समझने के माध्यम के रूप में इसे नहीं देखते तो हम वास्तव में एक नहीं बन सकते हैं। ■

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

सुरों की मधुर विविधता

बिजय शंकर बोरा

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सैकड़ों जातीय समूहों का मिलन-स्थल है, सांस्कृतिक फुलवारी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों वाले इस क्षेत्र को अनेक विधाओं और रंगतों वाली संगीत-लहरियां एकजुट करती हैं। इस संगीत में धुनों, लय-ताल और गीतों की विविधता है। यहां का कृषि-प्रधान जनजातीय जीवन नीलाभ पहाड़ियों और चंचल नदियों की हरी-भरी वादियों के बीच बसता है।

पूर्वोत्तर भारत के लोक, शास्त्रीय, रॉक और समकालीन संगीत की अनूठी शैलियों ने भारत के संगीत परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

असम

असम इस क्षेत्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अपने समृद्ध इतिहास, एक हज़ार साल पुरानी लोक संगीत परंपरा, पांच सौ साल पुरानी लिखित गीत-नाट्य परंपरा और तीन सौ साल पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा के साथ असम पूर्वोत्तर भारत की संगीत परंपरा में अग्रणी है।

असम की आधुनिक संगीत परंपरा 1883 से शुरू होती है जब सत्यनाथ बोरा ने असमिया गीतों की पहली पुस्तक 'गीतावली' प्रकाशित की। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंबिका गिरि रायचौधुरी (जन्म: 1885) ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत संगीत-रचनाओं से असम के आधुनिक संगीत में क्रांतिकारी रुझान का प्रारम्भ किया। ज्योतिप्रसाद अगरवाला (1903-1951), पार्वती प्रसाद बरुआ (1904-1964) और बिष्णु प्रसाद राभा (1909-1969) जैसी विभूतियों ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आधुनिक संगीत का अपना विशिष्ट घराना प्रारम्भ किया। ज्योतिप्रसाद जी ने ही इस क्षेत्र में आधुनिक संगीत की नींव रखी और फिल्मों को एक उद्योग की तरह चलाने की शुरुआत की।

अद्भुत प्रतिभाशाली डॉ भूपेन हजारिका (जन्म:1926) के आगमन के साथ ही असम के संगीत उद्योग का सबसे गौरवशाली अध्याय प्रारम्भ हुआ। 1980 के दशक तक वह असम के संगीत-क्षितिज पर छाए रहे और उनके गीत असम के पहाड़ों-घाटियों में गूंजते हुए सब का मन मोहते रहे। डॉ हजारिका के संगीत की नूतन शैली और राष्ट्रीय भावनाओं तथा पाश्चात्य धुनों सहित आधुनिक संगीत में रचे-बसे उनके गीतों ने असम के संगीत को राज्य की सीमा से बाहर निकाल कर देश-विदेश तक पहुंचा दिया। डॉ हजारिका के गीत-संगीत ने फिल्मों और रेडियो के जरिये असम के संगीत-उद्योग का विस्तार किया। उनके छोटे भाई जयंत हजारिका ने 1970 के दशक में असम के संगीत को पूरी तरह पाश्चात्य धुनों में ढालने में अग्रणी भूमिका निभाई।

इस दौर के अन्य श्रेष्ठ संगीतकारों में खगेन महंता, ब्रजेन बरुआ, दीपाली बोड़ठाकुर, हेमंत दत्ता, ज्योतिष भट्टाचार्य, पुलोक बनर्जी, कुला बरुआ और जीतू-तपन आदि शामिल हैं।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, संगीत के परिदृश्य में ताजगी भरा एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर में, इस क्षेत्र में उच्च टेक्नोलॉजी और डिजिटल संगीत की शुरुआत हुई। प्रतिष्ठित गायक और संगीतकार जीतूल सोनोवल ने इस रुझान को दिशा दी। 1990 के दशक में बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न जुबीन गर्ग के एलबम 'अनामिका' ने असम

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ईमेल: bijaysankar.bora@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

के संगीत-क्षेत्र में धूम मचा दी। 1992 से आज तक जुबीन संगीत-प्रेमियों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। उन्होंने न केवल पाश्चात्य और स्थानीय संगीत का फ्यूजन किया, बल्कि असम के परंपरागत गीत-संगीत को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया।

जुबीन के समकालीन लोकप्रिय गायक-संगीतकारों में तराली शर्मा और अंगराग (पेपोन) महंता शामिल हैं। पेपोन संगीत-जगत के तेजी से उभरते कलाकार हैं। उन्होंने, नया प्रयोग करते हुए, लोक संगीत और इलेक्ट्रॉनिक संगीत को मिला कर एक नई शैली- 'फोक्ट्रोनिका' विकसित की। संगीत का यह चरण वैश्वीकरण से प्रभावित है। लोकप्रिय असमी गायक- संगीतकार जॉय बरुआ के संगीत को कान्स फिल्म समारोह में 'सर्वश्रेष्ठ साउंडट्रैक' के पुरस्कार से सम्मानित एनिमेशन फिल्म 'फेंटेसी ऑफ कंपेनियनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इनानिमेट' के संगीत में शामिल किया गया।

इस बीच, राज्य में कुछ रॉक बैंड भी लोकप्रिय हो रहे हैं। 'ल्यूसिड रीसेस' गुवाहाटी का एक आल्टरनेटिव मैटल रॉक बैंड है। दो भाइयों – सिद्धार्थ और अमिताभ बरुआ द्वारा 2004 में बनाया गया यह बैंड भारत के सबसे अच्छे मैटल बैंडों में माना जाता है। गुवाहाटी का यह सबसे शानदार मैटल बैंड है। इसने 2011 में 'टोटो अवार्ड फॉर म्यूजिक' जीता। असम के अन्य प्रमुख रॉक बैंड हैं – एस्केप वेलोसिटी, हुवोरोनी, सेलेस्टियल डूम, तिपरासा और रंपाज़ी।

बैंड ऑफ हरीकेन गाल्स गुवाहाटी का एक आल्टरनेटिव/ब्लूज़/बॉलीवुड/फ्यूजन/इंडी/जाज़/मैटल/रॉक बैंड है। ममोनी कालिता (प्रमुख गायक, संगीतकार और निर्देशक) और आरजू बेगम (ड्रमर) के प्रयासों से 2010 में इस बैंड की स्थापना हुई। यह बैंड पारंपरिक असमी वाद्यों जैसे नगाड़ा, ढोल और डोतारा के साथ गिटार, कीबोर्ड्स, ड्रम सेट्स और कुछ आधुनिक तालवाद्यों का इस्तेमाल करते हैं।

सिबसागर के 19-वर्षीय संगीतकार तन्मय क्रिष्टोन क्षेत्र के रिद्म एंड ब्लूज़ (आरएंडबी) संगीत के साथ प्रयोग करने वाले प्रारम्भिक संगीतकारों में एक हैं। उनकी एक ताज़ा रचना 'अलकनंदा' को यू ट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा 'व्यू' मिले हैं। उनकी अन्य संगीत-रचनाएं भी अनेक प्लेटफॉर्मों पर बहुत लोकप्रिय हैं। शंकुराज कुंवर और मैत्रेयी पातर की रचना 'प्रोजेक्ट बार्तालाप' को भी अच्छी सफलता मिली है।

कुलदीप, जिनका मंचीय नाम 'कूल-डी' है, चर्चित रैप आर्टिस्ट हैं। उनके ट्रैक 'ज़ोरू मनुह' को 50 लाख 'व्यू' मिले हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है।

गायक शंकुराज कुंवर को थाइलैंड, नेपाल, जर्मनी, अमेरिका, बांग्लादेश, इन्डोनेशिया और चीन से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भी वह लोकप्रिय हैं। उन्हें अपने संगीत को अंग्रेजी भाषा में ढालने के भी अनुरोध मिल रहे हैं।

असम इस क्षेत्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अपने समृद्ध इतिहास, एक हज़ार साल पुरानी लोक संगीत परंपरा, पांच सौ साल पुरानी लिखित गीत-नाट्य परंपरा और तीन सौ साल पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा के साथ असम पूर्वोत्तर भारत की संगीत परंपरा में अग्रणी है।

असम ने भारतीय फिल्म उद्योग को श्रेष्ठ साउंड इंजीनियर अमृत प्रीतम को दिया है। श्रेष्ठ फिल्म संगीत स्कोरर और निर्देशक अनुराग सैकिया भी असम से ही हैं।

45 वर्षीय अमृत प्रीतम गुवाहाटी के डॉ भूपेन हजारिका फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर, कल हो ना हो, लव सोनिया, काबिल, विलेज रॉकस्टार्स, ब्यूटीफुल टाइम्स, इशू, मैन विद दि बाइनोकुलर, रेनबो और कोर्ट फिल्मों का साउंडस्केप तैयार करके उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है। अमृत प्रीतम ने रसूल पूकुट्टी के साथ काम किया है और वह अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइन्सेज के सदस्य हैं।

अनुराग सैकिया (उम्र: 32 वर्ष) ने चेन्नई की स्वर्णभूमि अकेडमी ऑफ म्यूज़िक से प्रशिक्षित हैं। इस समय वह असम और बॉलीवुड के सम्मानित संगीतकार माने जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार -रजत कमल पाने वाले वह सबसे कम उम्र के संगीतकार हैं जो उन्हें गैर-फीचर फिल्म 'युगदृष्टा' के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने अनेक फिल्मों के लिए संगीत दिया है। असम के शास्त्रीय भक्ति-गीतों- 'बोरगीत' को सिंफोनिक ऑर्केस्ट्रा से जोड़ने के प्रयास के लिए उन्हें बड़ी प्रशंसा मिली।

मेघालय

मेघालय में बहुसंख्यक आबादी ईसाई है और गोस्पेल गायन वहां हमेशा से जीवन का हिस्सा है। धीरे-धीरे यह संगीत गिरजाघरों से संगीत के मंचों तक आ गया। इस सुंदर पहाड़ी राज्य में संगीत के मंच के बादशाह रहे हैं लोउ माजाव, जो अब एक किंवदती बन गए हैं और कई पीढ़ियों का मनोरंजन करते रहे हैं।

शिलांग चेम्बर कॉयर (एससीसी) 2001 में नील नोंगकिनरिह द्वारा स्थापित किया गया। विविधतापूर्ण गायन-वादन वाले इस ग्रुप को 2010 में 'इंडियाज़ गॉट टेलेंट' रियलिटी टीवी शो में पुरस्कार मिला। इसी वर्ष इस कॉयर को छटे वर्ल्ड कॉयर गेम्स में म्यूजिका साक्रा, गोस्पेल और लोकप्रिय संगीत वर्गों में स्वर्ण पदक मिले।

इस ग्रुप ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भवन में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया।

इस मंडली के गायन-वादन में बड़ी विविधता है। जहां इन्होंने विएना चेम्बर ऑर्केस्ट्रा और फिट्ज़ विलियम क्वार्टेट के साथ प्रस्तुतियां दी हैं, वहीं 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 6 में उद्घाटन समारोह में अमिताभ बच्चन के साथ भी अपना जलवा दिखाया। शंकर एहशान लोय और उषा उत्थप के साथ भी इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। इनका 2011 का क्रिसमस एल्बम गैर-सिनेमाई संगीत में देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था।

शिलांग को भारत की 'रॉक कैपिटल' कहा जाता है। यहां भारत का सबसे सफल ब्लू बैंड -सोलमेट भी है। यह भारत का एकमात्र ब्लू बैंड है जिसने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। पूर्वोत्तर के इस बैंड का नेतृत्व जाने-माने गिटार-वादक, गायक और गीतकार रूडी वालांग और गायिका तिपरीति खरबंगार करते हैं। शिलांग का एक अन्य रॉक बैंड 'एबेरेंट' है। इसे मेघालय में रॉक संगीत प्रतियोगिता में 'मेघालय आइकॉन III' प्रदान किया गया।

शिलांग का 'फोर्थ एलीमेंट' बैंड ब्लैंड्स फंक, जाज, आर'एन'बी और सोल - चारों शैलियों का मिला-जुला गीत-संगीत प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने देश-विदेश में अनेक प्रस्तुतियां दी हैं। इस बैंड ने निशविले जाज फेस्टिवल-2019 (सर्बिया), बेलीज इन्टरनेशनल जाज फेस्टिवल-2018, फिलिपीन इन्टरनेशनल जाज फेस्टिवल-2015 (मनीला), जाजमांडू फेस्टिवल-2013 (काठमांडू), नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल-2019 (बेंकाक), दिल्ली इन्टरनेशनल जाज फेस्टिवल-2016, हैदराबाद इन्टरनेशनल जाज फेस्टिवल-2019 तथा साउथ एशियन बैंड्स फेस्टिवल-2010 (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन - 'सार्क' द्वारा आयोजित) में हिस्सा लिया। इस बैंड ने सिंग जाज क्लब (सिंगापुर) में 2015 में और तुलुम (मैक्सिको) में 2018 में भी हिस्सा लिया।

शिलांग को भारत की 'रॉक कैपिटल' कहा जाता है। यहां भारत का सबसे सफल ब्लू बैंड-सोलमेट भी है। यह भारत का एकमात्र ब्लू बैंड है जिसने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। पूर्वोत्तर के इस बैंड का नेतृत्व जाने-माने गिटार-वादक, गायक और गीतकार रूडी वालांग और गायिका तिपरीति खरबंगार करते हैं। शिलांग का एक अन्य रॉक बैंड 'एबेरेंट' है। इसे मेघालय में रॉक संगीत प्रतियोगिता में 'मेघालय आइकॉन III' प्रदान किया गया। मेघालय के प्रमुख रॉक बैंडों में प्लेग थ्रोट, मेस्त्रो, एबेरेंट, दि जार्स, आई 2 आई, वर्ब्स, डोसर्स अर्ज, एप्लाटस आदि हैं। एप्लाटस केवल लड़कियों वाला एकमात्र बैंड है।

नगालैंड

नगालैंड में 2020 में आलोबो नगा बैंड शुरू हुआ। राज्य के अन्य प्रमुख बैंडों में मेलोड्रामा, सुनेप, असेंबल बैंड, इन्सीपिट, क्रोनिक, ईस्टर्न हाट्ज, ट्रोजन्स, ब्लू क्लोवर बैंड और डिवाइन कनेक्सन शामिल हैं।

टेत्सिओ सिस्टर्स नगा हिल्स की चार संगीतकार बहनों - मुत्सेवेलु (मर्सी), अजीन वेजिवोलु (आज़ी), कुवेलु (कूकू) और अलीन टेत्सिओ (लुलू) का बैंड है। इन्हें लोकगीत गाने में महारत हासिल है। ये प्रायः एक तार वाला पारंपरिक नगा वाद्य - ताटी/हेका लिबुह बजाती हैं। इन बहनों ने पिछले दिनों दिल्ली में 'मिक्स दि सिटी' साउंडफ़ेस्ट में प्रस्तुति दी। इसका आयोजन ब्रिटिश काउंसिल ने किया था। टेत्सिओ बहनों ने बहुत कम उम्र में संगीत की प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी थीं। गोस्पेल, रॉक और पॉप की लोकप्रियता के दौर में, इन बहनों ने लोक संगीत को अपनाया।

मणिपुर

मणिपुर के 'क्लीव' रॉक बैंड के प्रतिभाशाली सदस्य पूरी दुनिया के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे आधुनिक समाज की बुराइयों को नष्ट (अंग्रेजी शब्द 'क्लीव' का अर्थ) कर दें और इस बैंड की मौलिक संगीत-कृतियों का भारी मैटल वाले बुलंद संगीत का आनंद लें। इन प्रतिभाशाली संगीतकारों का दावा है कि यह संगीत आपको मंत्रमुग्ध कर देगा; बार, शर्त यह है कि आप नशीले पदार्थों का सेवन न कर रहे हों और अन्याय की ताकतों के साथ न हों। यह बैंड अपनी मौलिक संगीत-कृतियों को 'प्रोग्रेसिव सेक्लूजन मैटल' कहते हैं।

मणिपुर में श्रेष्ठ संगीत-प्रस्तुतियों वाले अनेक नए बैंड उभर रहे हैं। इनमें स्टैपिंग स्टोन, रिसाइकिल, सिग्नस, डैजल सिटी और अंजेलिका प्रमुख हैं।

मांग्का मयंगलंबाम मणिपुरी लोक, शास्त्रीय और समकालीन संगीत-प्रस्तोता और पेना-वादक हैं। अपनी शानदार प्रस्तुतियों से वह मणिपुरी लोक-संगीत को लोकप्रिय बना रही हैं।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

युमलेमबाम गांभिनीदेवी मणिपुर की चर्चित नृत्यांगना और गायिका हैं। आकाशवाणी की 'सर्वश्रेष्ठ' वर्ग की मान्यता (ग्रेड) पाने वाली वह मणिपुर की प्रथम कलाकार हैं। उन्हें 2008 में नट संकीर्तन संगीत के लिए यह ग्रेड मिला। उन्हें नृत्य और गायन में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2005 में 'पद्मश्री' से सम्मानित किया। नट संकीर्तन संगीत में उनकी उपलब्धियों के लिए, उन्हें 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया।

युमलेमबाम गांभिनीदेवी मणिपुर की चर्चित नृत्यांगना और गायिका हैं। आकाशवाणी की 'सर्वश्रेष्ठ' वर्ग की मान्यता (ग्रेड) पाने वाली वह मणिपुर की प्रथम कलाकार हैं। उन्हें 2008 में नट संकीर्तन संगीत के लिए यह ग्रेड मिला। उन्हें नृत्य और गायन में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2005 में 'पद्मश्री' से सम्मानित किया। नट संकीर्तन संगीत में उनकी उपलब्धियों के लिए, उन्हें 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

मिज़ोरम

आइज़ॉल के पांच बेमिसाल लड़कों का बूमरैंग बैंड शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इनके संगीत के प्रवाह को बढ़ाने वाले सूत्रधार दो ज़िंदादिल लुशान (मिज़ो) वादक हैं जो छह तारों वाले वाद्य से मैटल, हिप-हौप, जाज, फंक, पंक और रॉक धुनें बजाते हैं। ये अपने आप को 'जंक रॉक' कहा जाना पसंद करते हैं। इस बैंड ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ प्रस्तुति दी है जिनमें स्कॉट किन्से बैंड, लैंब ऑफ गॉड, इंट्रोन आउट, फ़ायरहाउस, परिक्रमा, पेंटाग्राम आदि शामिल हैं। इन्हें विजेता अथवा उपविजेता के रूप में अनेक समारोहों में पुरस्कार मिले हैं। इन पुरस्कारों में नोकिया लॉर्ड्स ऑफ म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट रॉक और आईआईटी, मुंबई तथा एनआईटी, सिल्चर में हुए आयोजन शामिल हैं।

आइज़ॉल के पांच लड़कों ने 2005 में 'मैगडालेन' क्रिश्चियन रॉक बैंड बनाया। इस बैंड ने रॉक विधा में काफी नए प्रयोग किए हैं। इन्हें भी अनेक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पहला या दूसरा पुरस्कार मिला है। इन आयोजनों में ग्रेट इंडियन रॉक, होर्नबिल नेशनल रॉक तथा कई आईआईटी तथा एनआईटी में हुए समारोह शामिल हैं। इनका एल्बम 'लाइफ बियोंड डैथ' रॉक संगीत के नए आयाम खोलता है और सभी रॉक संगीत-प्रेमियों को नई दृष्टि देने वाला है।

'दि चोजन' आइज़ॉल की छह प्रतिभाशाली और उत्साही लड़कियों का गोस्पेल बैंड है। अनेक साझा प्रस्तुतियों के बाद इन लड़कियों ने 2009 में यह बैंड बनाया। अपनी पहली दो प्रस्तुतियां – 'ब्रोकन विंग्स' और 'कान फाक आ चे' से यह बैंड चर्चित हो गया। इस बैंड की छह सदस्य हैं – सेनी (गिटार-वादिका), फिओना (गायिका), मावितेई (गायिका), जोई (बासिस्ट), अफेली (ड्रमर), मलसावमी (कीबोर्डिस्ट)।

'दि एपल्स' लड़कियों का धूम-धड़ाके वाला रॉक एंड रॉल बैंड है जो 2007 में बना। रेट्रो रॉक स्टाइल वाली चुलबुली गिटार-वादिका जोड़िन्गालियानी इस बैंड की प्रमुख हैं। बैंड की अन्य सदस्य हैं- जोजो (गायिका), दउम उपेपदह (ड्रमर), अफ़ाकी (बासिस्ट) और डिंगडिंगी (गिटार-वादिका)। उन्होंने 1950 के दशक की लोकप्रिय संगीत-रचना 'स्टुपिड क्यूपिड' का मिज़ो संस्करण भी बनाया जिससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई।

'स्कैवेंजर प्रोजेक्ट' का विचार सबसे पहले विक्टर के मन में आया जो पहले प्रसिद्ध 'मैगडालेन' बैंड में गिटार-वादक थे। इस बैंड में 'थर्ड

सिक्किम

सिक्किम में तीन जातीय समुदाय हैं- लेप्चा, भूटिया और नेपाली। इनके लोकगीत और लोकनृत्य स्थानीय संस्कृति में रचे-बसे हैं। इन नृत्यों और संगीत में प्राकृतिक सौंदर्य और फसल काटने का उल्लास निहित होता है। इस गीत-संगीत में सौभाग्य और समृद्धि की कामना भी होती है। कुछ प्रमुख संगीत और लोक-नृत्य इस प्रकार हैं –

नेपाली लोक-नृत्य 'मरुणी' इस समुदाय के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय समूह-नृत्यों में एक है। यह प्रायः तीन-तीन पुरुष नर्तकों और स्त्री नर्तकियों द्वारा किया जाता है। इनके साथ प्रायः एक विदूषक 'धातू वारे' भी होता है। कभी कभी इस नृत्य में 9 नर्तक-नर्तकी भी होते हैं। इनके साथ के वाद्य-वृंद को 'नौ-मति बाजा' कहते हैं।

तमांग समुदाय का 'तमांगसेलो' लोक-नृत्य 'धम्पू' नाम के बाजे की लय में सम्पन्न किया जाता है। इसलिए इसे 'धम्पू' नृत्य भी कहते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की तरह सिक्किम में भी पाश्चात्य संगीत के विविध रूप - हिपहॉप, के पॉप और रैप आदि बहुत लोकप्रिय हैं।

भूटिया लोक-नृत्य 'ताशीसाब्दो' भी प्राचीन नृत्य है। शुभ अवसरों पर किए जाने वाले इस ललित नृत्य में 'खड़ा' (स्कार्फ) अर्पित किए जाता हैं। यर्खा, ड्रम, बांसुरी और यांगजीवाद्यों के साथ यह मधुर धुनों और संगीत वाला नृत्य किया जाता है।

हीरा देवी वाइबा (1940-2011) नेपाली गीतों और 'तमांगसेलो' नृत्य के साथ गए जाने वाले गीतों की अग्रणी महिला माना जाता है। उनका गाया 'चुरा राह्योइनाअस्तुरा', 'तमांगसेलो' नृत्य से जुड़ा प्रथम रिकॉर्डेड गीत माना जाता है। वह ऐसी पहली नेपाली लोक-गायिका रहीं जिनके संगीत के एल्बम (1974 और 1978 में) एल्बम बने। वह आकाशवाणी की एकमात्र नेपाली ग्रेड ए लोकगायिका थीं। उन्हें भारत में तथा नेपाल सरकार की ओर से भी अनेक पुरस्कार मिले। उनके निधन के बाद उनकी बेटी और बेटे ने उनके कुछ गीतों को दुबारा रिकॉर्ड कर 'आमा लाई श्रद्धांजलि' (मां को श्रद्धांजलि) एल्बम तैयार किया।

सोनमत्शेरिंगलेप्चा (1928-2020) प्रमुख लेप्चा लोक गायक थे। आकाशवाणी के लिए गाने वाले, वह सिक्किम के प्रारंभिक गायकों में एक थे। उन्होंने 400 से अधिक गीत गाए, 102 लोक-नृत्यों और 10 नृत्य-नाटिकाओं का संयोजन किया। उन्हें पद्मश्री अलंकरण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए।

स्रोत : https://www.sikkimtourism.gov.in/, विकीपीडिया

www.ourstudycircle.in/upscpdf/

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

सोवेरन' मिशेल एम. साइलो आए जो संगीत की धुनें बनाने और गीत लिखने में सिद्धहस्त हैं। वह अपने संगीत को 'इलेक्ट्रो-रॉक प्रोग्रेसिव' बनाना चाहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनिक, प्रोग्रेसिव रॉक, हिप हॉप और मेटल का मिश्रण है।

लंदन में जोसेफ और डैनी की 2010 में लंदन में कामडेन टाउन में मुलाक़ात हुई। भारत लौट कर उन्होंने दो बैंडवादकों - अंगू और वेलेंटिनो से बातचीत आगे बढ़ाई। इन सबने मिलकर 'फ़्रिस्की पिंट्स' बैंड की शुरुआत की।

इन्होंने भारत में अनेक आयोजनों में प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें ली रोनाल्डो एंड दि डस्ट (सोनिक यूथ ऑफ यूएसए), दि सेवन सिस्टर्स रॉक फैस्टिवल, दि इंडियन बाइक वीक, न्यू वेव फैस्टिवल गोआ आदि शामिल हैं। इन्होंने 'हार्ड रॉक राइजिंग' जैसी प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता तथा ऑन-लाइन वोटिंग सिस्टम जीतते हुए 'टॉप 25 वर्ल्डवाइड' में जगह पाई। इस स्तर तक पहुंचने वाला यह पहला भारतीय बैंड था। इस बैंड को उदय बेनेगल (इंडस क्रीड) ने एमटीवी पर 'रेवन नेवर हाइड साउंड सीरीज' के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए चुन लिया। इस बैंड ने 'कनवर्स रोड टु रबर' प्रतियोगिता का दिल्ली चरण भी जीता। इस बैंड को 'रोलिंग स्टोन मैगजीन' ने 2013 की सबसे बेहतर उभरती प्रस्तुति के लिए नामांकित किया गया। एमटीवी इंडीज ने इसे 'स्टार होने की संभावना वाले 10 अत्यंत प्रतिभाशाली युवा बैंडों' में शामिल किया।

'जगरनौट' छह सदस्यों वाला प्रोग्रेसिव रॉक बैंड है। 2016 में जारी इनके एल्बम 'सेक्रिफ़ाइस' पर अच्छी प्रतिक्रियाएं आईं।

अरुणाचल प्रदेश

'एलियन गोड्स' इटानगर का डेथ मेटल बैंड है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसके प्रतिभाशाली सदस्य पहले से ही स्थानीय कंसर्टों में गाते थे। अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख रॉक बैंडों में मंगल्ज़, सिमेट्री क्लान और दि विनाइल रेकॉर्ड्स शामिल हैं।

'सोल ऑफ फीनिक्स' 2011 में आलो (पश्चिमी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश) में बना हैवी मैटल/हार्ड रॉक बैंड है। इस समय यह शिलांग से काम कर रहा है। यह बैंड इस क्षेत्र में निरंतर प्रस्तुतियां देता रहा है। इसकी शैली क्लासिक रॉक, हैवी मैटल वाली है। इस बैंड में सदस्य हैं- डेविड (गायक), आनंद (गिटार-वादक), नरमी (बास) और नोआ (ड्रमर)।

'दि विनाइल रेकॉर्ड्स' चार महिलाओं का बैंड है जो नई दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश- दोनों जगह से काम करता है। इसकी प्रमुख गायिका और कीबोर्ड-प्लेयर चेरियन बार्क है। मिथी ताटक ड्रम बजाती हैं। मिनम तेकसेंग बास गिटार बजती हैं और बैंड जिनी गिटार-वादिका और गायिका हैं। इन्होंने फरवरी 2010 में अपना ग्रुप बनाया और मुख्यत: पोस्ट-पंक रॉक संगीत पर ध्यान केन्द्रित किया। इनका पहला एल्बम 'व्हिम्स' था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी इनका पहला गीत 'रेडी, सेट, गो' 2004 में जारी हुआ।

त्रिपुरा

त्रिपुरा के लोग हमेशा से संगीत से आपस में जुड़े होते हैं। हर त्यौहार और आयोजन लोगों को अवसर के अनुरूप गाने-बजाने का मंच प्रदान करते हैं।

सचिन देव बर्मन (1 अक्तूबर 1906 - 31 अक्तूबर 1975) त्रिपुरा के राज-परिवार से थे। उन्होंने 1937 में अपना फिल्मी सफर शुरू किया। बाद में उन्होंने हिन्दी फिल्मों के लिए संगीत देना शुरू किया और बॉलीवुड के सफलतम और सबसे सम्मानित संगीतकारों में शामिल हुए।

1980 और 1990 के दशक में, बिमल देबबर्मा ने स्थानीय युवाओं के जुड़ाव के अनुरूप गीतों और संगीत की रचना की। उन्होंने त्रिपुरा के संगीत को नया रूप दिया। उनके गीतों में रोमांस, देशप्रेम और राजनीति से मोहभंग के स्वर हैं। उनका 14 अप्रैल 2021 को निधन हो गया।

बिमल देबबर्मा ने अपनी संगीत-यात्रा 1980 के दशक में तब शुरू की जब कोकबोराक (त्रिपुरा की मुख्य जनजातीय बोली) का संगीत लोकगीतों तक सीमित था। उन्होंने और उनके सहयोगियों - जयंत जमातिया, क्वाप्लाई जमातिया और गौतम देबबर्मा ने नई धुनों और आधुनिक संगीत-वाद्यों के इस्तेमाल से इस परिदृश्य में नई जान फूंक दी।

होरज्वलाई त्रिपुरा का सबसे उभरता हुआ बैंड है। यह मैटल बैंड 2004 में शुरू हुआ। शैडोज़, स्वैरजक और दबानोल बैंड और ट्विजलांग आल्टरनेट मेटल बैंड अन्य प्रमुख संगीत-समूह हैं। कोलोमा बैंड की शुरुआत 2014 में हुई। 2015 में उन्होंने अपना पहला एल्बम - 'म्वर्वी' निकाला। यह बैंड दूसरी विधाओं- जैसे त्रिपुरा की लोक-धुनों के साथ ब्लूज़ और रॉक का फ्यूज़न करता है जिसके जरिए प्रेम, जीवन के विविध भाव और स्थानीय संघर्षों को अभिव्यक्ति मिलती है। इस बैंड के पांचों सदस्य देबबर्मा परिवार के हैं, जो बांसुरी, गिटार और पारंपरिक लोक-वाद्य जैसे सारिन्दा (वायलिन जैसा वाद्य) और चोंगप्रेंग (एक तार-वाद्य) बजाते हैं। ■

त्रिपुरा के लोग हमेशा से संगीत से आपस में जुड़े होते हैं। हर त्यौहार और आयोजन लोगों को अवसर के अनुरूप गाने-बजाने का मंच प्रदान करते हैं।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

YH-1594/2021

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

पूर्वोत्तर भारत में सिनेमा

मंजू बोरा

असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम को समेटे पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी विविधतापूर्ण जीवन-शैली, भाषाई विविधता, कला और संस्कृति की दृष्टि से अनूठा है। इस क्षेत्र में बनी अनेक फिल्मों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में फिल्म उद्योग की वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की फिल्मों की सीमित संख्या एक जीवंत फिल्म उद्योग की प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं है।

सिनेमा मूलतः एक दृश्य माध्यम है। अच्छा सिनेमा दृश्य चित्रों के जरिए कहानी सुनता है और साथ ही लालित्य के साथ परोसे एक पूर्ण पैकेज में, दृश्य बिंबों का प्रभाव और गहन करती ध्वनियों के साथ दर्शक की आंखों को तृप्त करता है।

भारत का पूर्वोत्तर भाग प्रकृति की स्वाभाविक हरीतिमा, अद्‌भुत जैव-विविधता और अनेक नस्लों और संस्कृतियों की फुलवारी के साथ संवेदनशील फिल्म-निर्माताओं को मनुष्य और प्रकृति के विविध आयामों पर फिल्में अनेक अवसर प्रदान करता है। उत्तर में भव्य हिमालय- शृंखलाओं, अनेक पहाड़ियों और वादियों, नदियों-धाराओं से भरा यह मनोरम क्षेत्र किसी भी सिनेकर्मी को आकर्षित करेगा। यहां के अनेक जातीय और नस्ली समूहों की अपनी बोलियां, व्यवहार और रंगारंग रीति-रिवाज तथा संस्कृतियां हैं। यहां ऐसे लोग भी हैं जो एकदम आदिम परिस्थितियों में रहते हैं; तो दूसरी ओर अति आधुनिक जीवन-शैली वाले लोग भी हैं। यहां की जलवायु सुहावनी है। गर्मियों में भारी बरसात होती है और कुछ उत्तरी इलाकों में हल्का हिमपात भी होता है। यहां के लोग मैत्रीपूर्ण, मददगार और अतिथि प्रेमी होते हैं। वे अतिथियों की हर संभव मदद करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए, इस राज्य में हमेशा वैध-अवैध रूप से बाहरी लोग आते-जाते रहे हैं। यह भी सिनेमा के लिए एक अच्छा विषय है।

इन अवसरों के साथ-साथ, इस क्षेत्र में फिल्म-निर्माताओं के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों, खास तौर से दूर-दराज के इलाकों में अब भी संचार और आवागमन की दिक्कतें है। सड़कें बहुत अच्छी नहीं है और रेल-संपर्क भी बढ़िया नहीं हैं। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी राज्य के बीच में बहती है लेकिन अच्छे जल-मार्ग नहीं हैं। राज्य के सबसे प्रमुख नगर – गुवाहाटी के लिए विमान-सेवाएं भी बहुत अच्छी नहीं हैं। दूसरे शहरों के लिए तो विमान-सेवाएं और भी कम हैं। पेट्रोलियम-पदार्थों पर बहुत अधिक शुल्कों और खराब सड़कों के कारण सड़क परिवहन महंगा है। इस इलाके के बाजार भी ठीक से विकसित नहीं हैं और रोजमर्रा की ज़रूरत की चीजें भी सब जगह आसानी से नहीं मिलतीं। अच्छी क्वालिटी के सिनेमा उपकरण भी सब जगह सुलभ नहीं हैं। इस क्षेत्र में बहुत थिएटर भी नहीं हैं और सिनेमा-दर्शकों को उचित प्रोत्साहन तथा जानकारी नहीं मिलने से अच्छे सिनेमा के लिए दर्शकों की भी कमी है। इस क्षेत्र में जातीय,भाषाई और सांप्रदायिक तनावों की स्थिति भी नाजुक बनी रहती है। विद्रोही गतिविधियां भी चलती रहती हैं। इन कारणों से सामान्य जन-जीवन अस्थिर बना रहता है।

लेकिन हिम्मती फिल्म-निर्माता ऐसे हालात में भी अच्छी फिल्में बनाने के अवसर निकाल ही लेते हैं। इस क्षेत्र के युवा और प्रतिभाशाली फिल्म-निर्माताओं ने ऐसी अनेक श्रेष्ठ फिल्में बनाई हैं जिन्हें अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समारोहों तथा प्रतियोगिताओं में पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। चारों ओर जमीन से घिरे, अक्सर उपेक्षित, अल्पविकसित तथा मनोरम प्रकृति से सम्पन्न इस क्षेत्र के

लेखिका गुवाहाटी में रहती हैं और चर्चित तथा पुरस्कृत फिल्मकार हैं। ईमेलः manjupatraborah@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

लोगों को अपने नेताओं से अक्सर शिकायतें रहती हैं कि वे लोगों की तकलीफ़ों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए, यहां के फ़िल्मकार अपने लोगों और उनकी संस्कृति के प्रति अपने प्रेम और उनके अभावों की अभिव्यक्ति सिनेमा के माध्यम से करते हैं और इसे वैश्विक दर्शकों के सामने रखते हैं। वे इस उक्ति को सार्थक करते हैं कि चुनौतियां अवसरों को जन्म देती हैं। मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा की सफलताओं का यही रहस्य है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का सिनेमा

अपनी विविधतापूर्ण जीवन-शैली, भाषाओं के उद्गम, कला और संस्कृति की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र अनुपम है। यहां 200 से ज्यादा नस्ली समूह हैं जिनकी अपनी विशिष्ट रंगत और पहचान है। यह भी एक विचित्र तथ्य है कि भारतीय सिनेमा के अग्रणी व्यक्तियों में एक – प्रमथेश बरुआ असम के थे। आर्देशिर ईरानी द्वारा 1930 में भारत की प्रथम सवाक (टॉकी) 'आलम आरा' के बनाए जाने के पांच ही वर्ष बाद, असमिया सिनेमा के पिता माने जाने वाले ज्योति प्रसाद अगरवाला ने असमिया की प्रथम फिल्म 'जयमती' बनाई थी। उस जमाने की नकली भावुकता वाली फिल्मों के दौर में अगरवाला यथार्थपरक फिल्में बनाने वाले अग्रणी निर्माता थे। 'जोयमती' 16वीं शताब्दी में असम के अहोम राजवंश के दौर की एक ऐतिहासिक चरित्र है जिसके सबल व्यक्तित्व, वीरता और राजनैतिक दृष्टि की कहानी फिल्म में कही गई है। इस फिल्म में काफी घाटा होने के बावजूद, अगरवाला ने 1937-38 में अपनी दूसरी फिल्म 'इन्द्रमालती' बनाई जो 1939 में प्रदर्शित हो सकी। प्रमथेश बरुआ ने 'देवदास' का असमिया संस्करण 1937 में बनाया।

असमिया सिनेमा के पिता माने जाने वाले ज्योति प्रसाद अगरवाला ने असमिया की प्रथम फिल्म 'जोयमती' बनाई थी। उस जमाने की नकली भावुकता वाली फिल्मों के दौर में अगरवाला यथार्थपरक फिल्में बनाने वाले अग्रणी निर्माता थे। 'जोयमती' 16वीं शताब्दी में असम के अहोम राजवंश के दौर की एक ऐतिहासिक चरित्र है जिसके सबल व्यक्तित्व, वीरता और राजनैतिक दृष्टि की कहानी फिल्म में कही गई है। इस फिल्म में काफी घाटा होने के बावजूद, अगरवाला ने 1937-38 में अपनी दूसरी फिल्म 'इन्द्रमालती' बनाई जो 1939 में प्रदर्शित हो सकी। प्रमथेश बरुआ ने 'देवदास' का असमिया संस्करण 1937 में बनाया।

ज्योति प्रसाद अगरवाला के असमय निधन के बाद, असमिया फिल्मों के निर्माण की गति मंद पड़ गई। 1941 में रोहिणी कुमार बरुआ ने तीसरी असमिया फिल्म 'मनोमती' बनाई। यह भी एक ऐतिहासिक फिल्म थी। इसके बाद आईं फिल्में इस प्रकार हैं– परभाती प्रसाद बरुआ की फिल्म 'रूपाही' (1946), कमल नारायण चौधरी की 'बदन बोरफुकन' (1947), फणि सरमा की 'सिराज', असित सेन की 'बिपलोबी', प्रवीन फुकन की 'पारघाट' और सुरेश गोस्वामी की 'रूनुमी'।

1950 के दशक में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फणि सरमा द्वारा निर्देशित 'पियाली फुकन' थी। इस फिल्म का संगीत युवा संगीतकार भूपेन हजारिका ने दिया था। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली असमिया फिल्म थी। अपने समय की तुलना में यह तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत थी। इस काल के एक अन्य महत्वपूर्ण फिल्म-निर्देशक थे निप बरुआ, जिनकी फिल्म 'रोंगा पुलिस' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में रजत पदक मिला। इसके बाद डॉ भूपेन हजारिका ने अपनी पहली फिल्म 'एरा बतोर सुर' बनाई जिसमें लता मंगेशकर ने प्रसिद्ध 'जोनकोरे आसोमिरे मती जिलिकी जिलिकी उठे' गया। इस फिल्म से असमिया सिनेमा पर देश के दूसरे हिस्सों के दर्शकों की भी नज़र पड़ी। डॉ भूपेन हजारिका को 1965 में बनाई उनकी फिल्म 'प्रतिध्वनि' और 1966 की फिल्म 'लोटीघोटी' के लिए राष्ट्रपति के रजत पदक मिले।

असम के एक प्रमुख फिल्म-निर्माता अब्दुल मजीद ने 1968 में अपनी पहली फिल्म 'मोरोम तृष्णा' बनाई। 1975 में बनी उनकी फिल्म 'चमेली मेमसाब' को श्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक मिला। इस फिल्म में डॉ भूपेन हजारिका ने संगीत दिया था जिसके लिए फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार भी दिया गया। 1969 में ब्रजेन बरुआ की लोकप्रिय फिल्म 'डॉ बेज़बरुआ' क्षेत्रीय फिल्म वर्ग में राष्ट्रपति का रजत पुरस्कार मिला।

1970 से 1982 के बीच असमिया सिनेमा में अनेक नए फिल्म-निर्देशक आए। इनमें प्रमुख हैं – समरेन्द्र नारायण देव, कमल चौधरी जिन्होंने पहली रंगीन फिल्म 'भैती' बनाई, पुलम गोगोई, पदम बरुआ, डॉ भबेन्द्रनाथ सैकिया और अतुल बोरदोलोई।

1976 में बनी पदुम बरुआ की फिल्म 'गंगा सीलोनीर पाखी' ने असमिया सिनेमा को आधुनिक यथार्थपरक सिनेमा की एक नई दिशा दी। 1964 में बनी सर्वेश्वर चक्रवर्ती की फिल्म 'मोनिराम दीवान' को 1964

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म में डॉ भूपेन हजारिका का संगीत था। इस फिल्म में डॉ हजारिका ने 'बुकु होम होम कोरे' मधुर गीत गाया था जिसे बाद में हिन्दी फिल्म 'रुदाली' में लता मंगेशकर ने गा कर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया।

जाहनु बरुआ और डॉ भबेन्द्रनाथ सैकिया ने अपनी फिल्मों से असमिया सिनेमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। डॉ भबेन्द्रनाथ सैकिया असमिया के प्रख्यात लेखक भी थे। उन्होंने आठ फिल्में निर्देशित कीं जिन्हें कांस, कार्लोबो वेरी, नांटेस (फ्रांस), वालडोलिड (स्पेन), अल्जीरिया, प्योंग योंग (उत्तर कोरिया), सिडनी, म्यूनिख, मोंट्रियाल, टोरंटो आदि अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया। दूसरी ओर, जाहनु बरुआ की सभी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और कुछ को तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। सेल्यूलॉइड के उन दिनों में, इन फ़िल्मकारों ने असमिया सिनेमा का परचम विश्व के कोने-कोने में फहराया।

इनके बाद, गौतम बोरा, बिद्युत चक्रवर्ती, डॉ सांत्वना बोरदोलाई, संजीब हजारिका, जंगदेव बदोसा और मंजु बोरा (इस लेख की लेखिका) का दौर आया। इन फिल्मकारों ने असमिया भाषा और इस क्षेत्र की कुछ बोलियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्में बनाई।

इसी क्षेत्र के मणिपुर राज्य की भी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है जो उसके संगीत, नाटक, साहित्य और हस्तशिल्प के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इस राज्य की फिल्मों का भी विशिष्ट स्थान है। देब कुमार बॉस द्वारा 1972 में प्रदर्शित निर्देशित प्रथम मणिपुरी फिल्म 'माताम्का मणिपुर' को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मणिपुरी के श्रेष्ठ फिल्म-निर्देशक अरीबाम श्याम सरमा ने 1974 में अपनी पहली फिल्म 'लम्जा परशुराम' बनाई। उनकी चौथी फिल्म 'इमाकी निंगेथम' को 1982 में नांतेस (फ्रांस) फिल्म समारोह में 'गोल्डन मोंटोगोल्फर' पुरस्कार मिला। इस तरह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 1990 में बनी उनकी फिल्म ,इशानौ' 1991 के कान्स फिल्म समारोह अंसर्टेन रिगार्ड सैक्सन में प्रदर्शित की गई। निश्चय ही वह पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म-निर्देशक हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। मणिपुर के अन्य फिल्म-निर्देशकों, जैसे एम ए सिंह, मखोमोनी मिंकसूबा, ओइनाम गौतम सिंह, एच पवन कुमार आदि ने बढ़िया फिल्में बनाई हैं। इतनी प्रगति के बावजूद, हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन के खिलाफ स्थानीय आंदोलन की वजह से एक समय मणिपुर में फिल्म निर्माण का काम पूरी तरह ठप हो गया था और सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। डिजिटल फिल्मों की शुरुआत के बाद मणिपुर के फिल्म उद्योग का विस्तार हो रहा है, फिल्में व्यावसायिक तरीके से प्रदर्शित हो रही हैं, फिल्मों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है; लेकिन सही मायने में फिल्म उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। इस वर्ष राज्य की फिल्म विकास सोसाइटी और फिल्म समुदाय के लोग मणिपुरी सिनेमा की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर वे उन अग्रणी फ़िल्मकारों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने 1970 के दशक में अनेक चुनौतियों के बीच, बिना किसी सहायक बुनियादी ढांचे के, मणिपुर में फिल्म-निर्माण का काम प्रारम्भ किया।

1950 के दशक में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फणि सरमा द्वारा निर्देशित 'पियाली फुकन' थी। इस फिल्म का संगीत युवा संगीतकार भूपेन हजारिका ने दिया था। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली असमिया फिल्म थी। अपने समय की तुलना में यह तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत थी।

मेघालय के मातृसत्तात्मक समाज की अपनी पहचान है जहां वंश-परंपरा और धरोहर स्त्रियों से होती है। मानव, संस्कृति और परिवेश के बीच संतुलन बनाते अनेक पर्व-उत्सव यहां होते हैं लेकिन फिल्म उद्योग की यहां शुरुआत लंबे समय तक प्रयासों के बाद हुई। 'का सिंजुक री की लाईफ्यू स्येम' मेघालय में खासी भाषा में बनी पहली फिल्म है जिसे 1981 में हामलेट बारे पकयान्ता ने बनाया। इसके बाद, 1984 में अर्धेंदु भट्टाचार्जी ने पहली रंगीन फिल्म – 'माणिक राइतोंग' बनाई।

वर्ष 2000 के बाद, जब मेघालय में उग्रवादी घटनाएं तेजी से कम हुईं तो मनोरंजन तथा फिल्मों के लिए बाज़ार बना। अनेक लघु, बड़ी और वीडियो फिल्में बनानी शुरू हुईं। 2014 में प्रदीप कुरबाह की फिल्म 'री' को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2016 की उनकी फिल्म 'ओनाताह' को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्हीं की 2019 की फिल्म 'ल्युदुह' खासी भाषा की ऐसी पहली फिल्म बनी जिसे दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित बुसान फिल्म समारोह में प्रथम प्रदर्शन (प्रीमियर) और पुरस्कृत होने का गौरव मिला। इस फिल्म को खासी भाषा की फिल्म के रूप में 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और लोकेशन साउंड के लिए भी पुरस्कृत किया गया। मेघालय के फिल्म-निर्माताओं के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी, जहां फिल्मों के लिए निर्माता और धन लगाने वाले बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं।

मेघालय के डोमिनिक संगमा ने गारो भाषा (यह भी मेघालय की राजकीय भाषा है) 2019 'मा अमा' में फिल्म बनाई।

लेकिन प्रश्न यह है कि इन फिल्मों को कहां प्रदर्शित किया जाए? दर्शकों का रुख क्या होगा? प्रदीप जैसे निर्देशकों का मानना है कि फिल्मों को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर दिखाने (ट्रेवलिंग टॉकीज़) के तरीके से इन फिल्मों की लागत निकल सकती है। हालांकि पूरा मेघालय ही इतना सुरम्य है कि वहां किसी भी तरह की फिल्म शूट की जा सकती है, लेकिन महान फिल्म-निर्देशक ऋत्विक घटक ही सही मायने में खासी

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

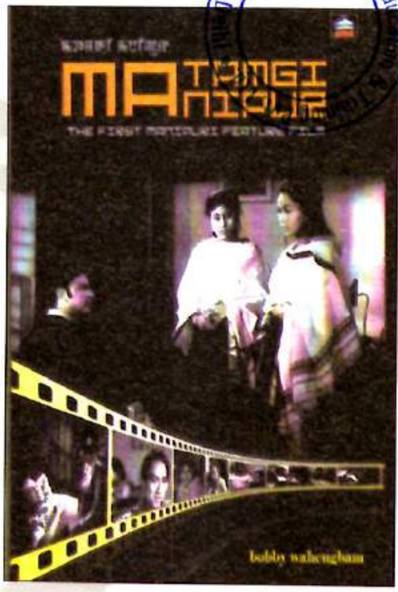

क्षेत्र के सौन्दर्य को पकड़ सके और अपनी चिर-स्मरणीय बांग्ला फिल्म 'मेघे ढाका तारा' में विषाद के क्षणों को चित्रित कर सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश में 20 से अधिक जनजातियों की पहचान है। राज्य के अधिकतर लोग बौद्ध हैं। तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के मोन्पा और शेरदुकपेन लोग महायान बौद्ध मत की लामा परंपरा में विश्वास करते हैं। कुछ अन्य जनजातियों के लोग दोन्यी-पोलो नामों से सूर्य और चन्द्र देवता की पूजा करते हैं। कुछ लोग ईसाई तथा हिन्दू भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में संगीत और नृत्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश अब सिनेमा के विकास पर ध्यान दे रहा है और केंद्र सरकार इस काम में मदद देते हुए इटानगर में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने जा रही है।

पिछले कुछ समय से फिल्म-निर्माण युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इनमें से कुछ की फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित हो रही हैं। शेरदुकपेन बोली में पहली फिल्म 'क्रॉसिंग ब्रिज' थी जो 2013 में सांगे दोरजी थोंगदोक ने बनाई। इसे सर्वप्रथम मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। लेकिन राज्य में 2016 तक भी कोई सिनेमा हॉल नहीं था जहां ये फिल्म दिखाई जा सके। इसलिए, यहां बनी फिल्मों से स्थानीय लोगों का परिचय हो ही नहीं पाता।

अहसान मजीद की बनाई फिल्म 'सोनम' मोन्पा बोली में बनी पहली फिल्म थी। इसे 2020 में 37वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाया गया। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला और इसे विश्व भर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाया गया।

अरुणाचल प्रदेश में बनी तीसरी फिल्म 'हैड हंटर' वांचू बोली में बनाई गई। इसके निर्देशक नीलांजन दत्ता पूने फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में प्राध्यापक हैं। फिल्म में बताया गया है कि वनों की अनियमित कटाई और अनियोजित निर्माण-कार्यों से इस सुंदर राज्य के लिए खतरा हो सकता है। निर्देशक अरुणाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को बचाने के लिए चिंतित हैं जबकि वहां की नई पीढ़ी 'मुख्य धारा' में शामिल होने की होड़ में अपने अतीत से मुंह मोड़ रही है।

अरुणाचल प्रदेश में 2018 में दो और फिल्में बनाई गई। ये मैंने (मंजु बोरा) और बॉबी सरमा बरुआ ने बनाई। दोनों फिल्में अरुणाचल प्रदेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक येशे दोरजी थोंगची के उपन्यासों पर आधारित थीं। इन दो फिल्मों- 'इन दि लैंड ऑफ पॉइज़न वुमन' और 'मिशिंग' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और इन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश में बनी सबसे ताजा फिल्म शांतनु दत्ता की 'वाटर बरियल' है जिसे पर्यावरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है।

राज्य में बनी सभी फिल्में वहां के किसी न किसी महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे को उठाती हैं। लेकिन राज्य को अपने फिल्म उद्योग को खड़ा करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है।

मिज़ोरम राज्य के निवासी मिज़ो लोग मंगोलॉइड नस्ल के हैं। इनमें से अधिकांश ईसाई हैं और एक विशिष्ट नैतिक सिद्धान्त 'त्लावमंगाइना' का पालन करते हैं। इन मान्यताओं ने मिज़ो समाज को घनिष्ठता से एकजुट किया है। ये लोग नृत्य और संगीतप्रेमी हैं। यहां का चेयाव अथवा 'बांस नृत्य' प्रसिद्ध है। स्थानीय वाद्यों के साथ, ये लोग अनेक लोकगीत गाते हैं। यहां हथकरघा और हस्तशिल्पों की भी समृद्ध परंपरा है।

मिज़ो भाषा में अब तक एकमात्र फीचर फिल्म माउपुईया चोंगथन द्वारा निर्देशित 'खाव्नग्लुंग रन' है। यह 1856-59 के दौर में खाव्नग्लुंग में हुए हत्याकांड की घटना से जुड़ी एक्शन और रोमांस वाली फिल्म है। इसे कुछ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाया गया है। फिल्म्स डिवीजन, मुंबई और कुछ निजी निर्माता कुछ डॉक्युमेंट्री फिल्में भी बना रहे हैं। इन दिनों राज्य सरकार, एक फिल्म सोसाइटी के सहयोग से मिज़ो फिल्मों को बढ़ावा देने में लगी है।

नगालैंड राज्य में मुख्य जनसंख्या नगा लोगों की है जिनमें जनजातियों के अनेक समूह शामिल हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर भाग के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम म्यांमार में भी बसे हैं। समान मंगोलॉइड नस्ल परिवार के होने के बावजूद, हर समूह की अपनी विशिष्ट बोली, संस्कृति और परंपराएं हैं। कोई भी समूह दूसरे समूह की भाषा नहीं बोल पाता। इनकी एक समान भाषा नगामीज है और यहां के अधिकांश लोग ईसाई हैं। इनकी संस्कृति बड़ी जीवंत है और नृत्य भी अनूठे हैं। इनका लोक-संगीत भी बहुत विविधतापूर्ण है जिसमें धार्मिक विश्वासों, रोमांस और वीरता के भाव व्यक्त करती परंपरागत सुरीली धुनें होती हैं।

नगालैंड में कई डॉक्युमेंट्री और कुछ वीडियो फिल्में बनाई गई हैं। नगालैंड की पांच प्रतिभाशाली महिला फिल्म निर्देशकों ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। ये हैं-

असम के एक प्रमुख फिल्म-निर्माता अब्दुल मजीद ने 1968 में अपनी पहली फिल्म 'मोरोम तृष्णा' बनाई। 1975 में बनी उनकी फिल्म 'चमेली मेमसाब' को श्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक मिला। इस फिल्म में डॉ भूपेन हजारिका ने संगीत दिया था जिसके लिए फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार भी दिया गया।1969 में ब्रजेन बरुआ की लोकप्रिय फिल्म 'डॉ बेज़बरुआ' क्षेत्रीय फिल्म वर्ग में राष्ट्रपति का रजत पुरस्कार मिला।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

सोफी लसुह, तीयाइनला जमीर, सेसिनो होशु और यापांगनारी लोंगकुमार। सोफी लसुह और सेसिनो होशु 'क्यू हु' फिल्म-निर्माण कंपनी चलते हैं। उनकी पहली फिल्म 'दि स्टोरी ऑफ ए हाउस' काफी चर्चित हुई और अनेक फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की गई। उनकी ग्रेजुएशन फिल्म 'चिल्ड्रन ऑफ साइलेंस' नगालैंड में सेना के कथित दुर्व्यवहार के बारे में है जो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स (बीएएफटीए -बाफ्टा) पुरस्कारों के लिए नामित हुई।

विकेयेनो जाओ नागालैंड की एक और प्रतिष्ठित डॉक्युमेंट्री फिल्म-निर्माता हैं जो पूर्वोत्तर भारत की एसी एकमात्र फिल्म-निर्देशक हैं जिनकी फिल्में कान्स फिल्म समारोह में दिखाई गईं। उनकी फिल्म 'लास्ट ऑफ दि टेटूड हैड हंटर' को 2010 में 63वें और 'दिस लेंड वी कॉल्ड अवर होम' को 2011 में 64वें कान्स फिल्म समारोह में लघु फिल्म वर्ग में चुना गया। फिल्म-निर्माता मा जाओ ने कई डॉक्यूमेंटरी फिल्में, टेली-फिल्में और टेली-सीरियल बनाए जिनके विषय नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश की प्रकृति और यहां की जनजातियों के मानव-विज्ञान तथा सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में हैं।

तीयाइनला जमीर ने नगालैंड में कई डॉक्यूमेंटरी फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्म 'गोइंग दि डिस्टेंस' भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा में (1916 में) चुनी जाने वाली राज्य की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को अनेक फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया और काफी सराहना मिली।

सेसिनो होशु कोहिमा में एक फिल्म-निर्माण कंपनी 'टेक वन' चलाती हैं। उनकी पहली डॉक्यूमेंटरी फिल्म 'अप्फुस्ता' उनके दादाजी के बारे में थी। इसे नेशनल पोर्टेट गैलरी, लंदन; बांग शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, नॉटिंघम; यूनिवर्सिटी ऑफ रोशेस्टर, न्यू यॉर्क तथा रूबिन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यू यॉर्क में दिखाया गया। सोफी लसुह के साथ सह-निर्देशित उनकी फिल्में 'दि इमेजिनरी लाइन' और 'दि स्टोरी ऑफ ए हाउस' अनेक फिल्म समारोहों में दिखाई गईं और पसंद की गईं।

यापांगनारी लोंगकुमार की चर्चित डॉक्यूमेंटरी 'एंड डाउन दि रिवर दे वेंट' इटली में एसियाटिका फिल्म मेडियाले तथा न्यू यॉर्क के रूबिन म्यूजियम में प्रदर्शित की गई। उन्होंने 'दि डायरी ऑफ मिमी', 'टु दि बीट ऑफ देयर ओन ड्रम', 'राइज़ ऑफ जाइंट्स', 'दि लास्ट ऑफ दि ईस्ट'। ए टच ऑफ समथिंग गुड' और 'दि दान ऑफ फेथ' आदि डॉक्यूमेंटरी बनाई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अन्य राज्य -त्रिपुरा के मूल निवासी 'त्रिपुरी' कहे जाते हैं। इनमें सी अधिकतर जनजातीय लोग हैं। यहां 19 जनजातियों के निवासी हैं जिनमें एक बंगाली जनजाति समूह है। दूसरे समूह में भारतीय-मंगोलॉइड जनजातियों के लोग हैं जिनकी अपनी बोलियां तथा विशिष्ट रीति-रिवाज तथा परम्पराएं हैं।

समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद, त्रिपुरा को फिल्म-निर्माण में अपनी यात्रा अभी शुरू करनी है। केरल के फादर जोसेफ पुलथानाथ ने, इस क्षेत्र के निवासी नहीं होने के बावजूद, 2003 में त्रिपुरा की पहली फिल्म – 'मथिया' (चूड़ियां) बनाई जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। कोकबोराक बोली में बनी इस फिल्म में किसी महिला को जादूगरनी करार देने की कथा है। आज भी त्रिपुरा में यह कुप्रथा कहीं-कहीं नज़र आती है। उनकी दूसरी फिल्म 'यारांग' भी कोकबोराक बोली में है जो 2008 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उदघाटन फिल्म के रूप में दिखाई गई। इन दो फिल्मों के जरिए, त्रिपुरा ने फिल्म समारोहों के जरिए फिल्मों की दुनिया में दस्तक दी है लेकिन राज्य को फिल्म उद्योग की स्थापना के लिए अभी लंबा सफर तय करना है।

क्षेत्र के खूबसूरत राज्यों में से एक सिक्किम में सिनेमा अभी भी अपने नवोदित चरण में है। हालांकि सिक्किम सरकार द्वारा स्थानीय और बाहरी लोगों के लिए सिनेमा निर्माण के लिए कुछ सिनेमा अनुकूल योजनाएं शुरू की गई हैं, फिर भी सिक्किम को वहां एक सिनेमा उद्योग स्थापित करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। हालांकि राज्य के सिनेमा प्रेमियों और सिनेमा निर्माताओं के लिए यह बहुत उत्साहजनक है कि इस वर्ष 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सिक्किम को देश का सबसे अधिक सिनेमा अनुकूल राज्य घोषित किया गया। सिक्किम की वर्तमान सरकार राज्य को न केवल पर्यटन स्थल बल्कि फिल्म गंतव्य भी बनाने का प्रयास कर रही है।

यदि हम सिक्किम में सिनेमा निर्माण के इतिहास को देखें, तो हम पाते हैं कि सत्यजीत राय ने वर्ष 1971 में एक वृत्तचित्र "सिक्किम" बनाया था। यह सिक्किम की संप्रभुता के बारे में था।

इस तरह, इस क्षेत्र के आठ राज्यों की फिल्मों ने समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सम्मान हासिल किए हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में फिल्म उद्योग की वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की फिल्मों की सीमित संख्या एक जीवंत और सफल फिल्म उद्योग की प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही, इस क्षेत्र की जनसंख्या जिलों के स्तर तक भी अनेक नसली और भाषाई समुदायों में बंटी है। इसीलिए किसी एक भाषा की फिल्म के चल पाने के लिए पर्याप्त दर्शक ही नहीं मिलते। इससे निर्माताओं की फिल्म में लगी लागत भी वसूल नहीं हो पाती। असम और मणिपुर को छोड़ कर, अन्य राज्यों में सालाना पांच फिल्में भी नहीं बन पातीं। ऐसी स्थिति में, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अथवा कुछ कॉर्पोरेट घराने तथा बड़े स्टूडिओ यहां के फिल्म-निर्माताओं की मदद के लिए आगे आएंगे। तभी यहां पर्याप्त संख्या में अच्छी फिल्में बन सकेंगी और स्थानीय फिल्म उद्योग जड़ें जमा सकेगा। ■

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

MIT-SOG MIT School of Government
Kindling the flame of Democratic Leadership...

Supported by UNESCO
UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace & Tolerance

Join Us
for emerging
Career Opportunities
in Politics

ADMISSION OPEN

MPG Master's Degree Program in Political Leadership & Government

Batch 2021-23

- 1st year on-campus learning
- 2nd year field training & internships

"Only the educated youth of India can bring about the much needed change in Politics"
– Rahul V. Karad, Initiator, MIT-SOG

PROGRAM HIGHLIGHTS:

Interactive sessions with Political leaders.

Visits to Gram Panchayat, Zilla Parishad, Municipal Corporation, State Aassembly.

Study Tour for Campaign & Election Management, National Study Tour to Delhi.

Optional International Study Tour to Europe.

Apply Online
mitsog.org | mitwpu.edu.in
Email: sog@mitwpu.edu.in

CAREER PROSPECTS

RESEARCH ASSOCIATE | POLITICAL ANALYST | POLITICAL STRATEGIST
CAMPAIGN MANAGER | CONSTITUENCY MANAGER
CONTEST ELECTIONS & BE A PART OF ACTIVE POLITICS
OFFICE BEARERS IN PROMINENT POLITICAL PARTIES

MIT-SOG has 450 strong alumni. Many of whom are associated with political parties and political leaders. Some have contested elections from Gram Panchayat to Parliament and some are associated with the offices of Governor, Chief Minister, and Speaker while others are active in youth wings of political parties.

Eligibility: Graduate with min. 50% aggregate

FIRST INSTITUTE OF ITS KIND TO CREATE FUTURE POLITICAL LEADERS

MIT-WPU

Mo.: 98508 97039, 77200 61611 | 91460 38947

- **MIT School of Government is part of MIT World Peace University** *recognised by the UGC under the Govt. of Maharashtra Act XXXV 2017, since 2017*
- **MPG PG Degree is confered as Master of Arts (MA) in Political Leadership & Government**

YH-1601/2021

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

कपड़े और डिज़ाइन

सोनम दूबल

पूर्वोत्तर के कपड़ों और हस्तकलाओं में प्राकृतिक अंदाज की गहरी समझ दिखाई पड़ती है। कपड़े की बुनाई यहां एक तरह से जीवनशैली है। हालांकि, कपड़े की इस संस्कृति को बचाए रखने और इसे बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए सरकार को डिजाइनरों, कारीगरों, बुनकरों के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बाजार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम किया जा सके और इस हस्तकला को बेहतर बनाने के लिए उपाय ढूंढे जा सकें। इस तरह, शोध और अन्य गतिविधियों के जरिये इस उद्योग को फैशन बाजार के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनाया जा सकेगा।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति एशियां के अन्य हिस्से को समझने के लिए पुल की तरह है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (जैसे कि बर्मा (अब म्यांमार), थाइलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और जापान) के बीच मजबूत ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से यह बेहद अहम है। कपड़ा, हस्तकला और संस्कृति के मामले में इन देशों के साथ समानता होने की वजह से यह स्पष्ट है कि भारत के लिए सीमा पार इन देशों में भी बाजार उपलब्ध है।

फैशन की पढ़ाई और शोध के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह (फैशन) गहरे तौर पर इतिहास और संस्कृति से जुड़ा होता है और नए कलेक्शन के उभरने के पीछे ऐसी एक कहानी होती है। मिली-जुली पृष्ठभूमि से होने के कारण मैंने अपनी निजी इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और पाया कि मैं ऐसे उत्पाद तैयार करना चाहता हूं जो समकालीन होने के साथ-साथ परंपराओं से जुड़ा हो। इस सिलसिले में मुझे असम में बुने जाने वाले 'एरी सिल्क' के बारे में पता चला। इस कपड़े की बुनाई धीरे-धीरे होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी बेहतर है और इसमें कई सारी खूबियां होती हैं। एरी सिल्क में औषधीय गुण भी होते हैं।

यह सिल्क (रेशम) कीड़े को मारे बिना तैयार किया जाता है, इसलिए इसे 'अहिंसा सिल्क' कहा जाता है और साधु-संन्यासी इसे ओढ़ते हैं। इसे बुनने की प्रक्रिया अपने-आप में एक यात्रा है। इस हस्तकला से मुख्य तौर पर महिलाएं जुड़ी हैं और इसे जारी रखने के लिए सहयोग की जरूरत है। यह सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाओं से ही संभव हो सकता है। इस क्षेत्र के बुनकरों को भी सहयोग की जरूरत होती है, क्योंकि वे मुख्य तौर पर हथकरघा पर निर्भर हैं जिसका चलन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। पूर्वोत्तर की भौगोलिक संरचना की वजह से बुनकर समुदाय की स्थिति कमजोर

लेखक पूर्वोत्तर क्षेत्र के मशहूर डिजाइनर हैं और अपना फैशन उद्यम चलाते हैं। ईमेल: www.sonamdubal.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

है। उनके उत्पादों के लिए तत्काल बाजार विकसित करने की जरूरत है। खास तौर पर कोविड महामारी के इस दौर में इसकी सख्त जरूरत है। इसमें निवेश को बढ़ावा देकर बुनकरों को पारंपरिक हस्तकला के जरिये आजीविका हासिल करने में मदद मिल सकेगी। इस तरह की कोशिश की जा रही है और बुनकरों की जिंदगी की तकलीफों को समझा जा रहा है। पूर्वोत्तर के बुनकरों के कामकाज के लिए नई शर्तें तय करना सार्थक हो सकता है। बुनाई को घरों में सांस्कृतिक इतिहास से जुड़े रहने के तौर पर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर के कपड़ों और हस्तकलाओं में प्राकृतिक अंदाज की गहरी समझ दिखाई पड़ती है। कपड़े की बुनाई यहां एक तरह से जीवनशैली है। शुरू में इस क्षेत्र में तैयार उत्पाद स्थानीय इस्तेमाल के लिए ही होते थे। उदाहरण के लिए, मणिपुर या नगालैंड या मिज़ोरम में सिल्क या शॉल, असम और मेघालय में एरी या मूगा सिल्क और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय कपास से कपड़े की बुनाई होती थी। इनका उत्पादन त्योहारों, विवाह और अन्य आयोजनों के मकसद से किया जाता था। इस क्षेत्र का कपड़ा उद्योग शुरू में आत्मनिर्भर था और यह अपने लिए बाजार ढूंढ लेता था। हालांकि, आर्थिक विकास के साथ ही बुनकरों को अब मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उद्योग की खास पहचान को बनाए रखना मुश्किल हो गया है और व्यावसायिक बाजारों के लिए भी उपयुक्त डिजाइन तैयार करना चुनौती है।

हालांकि, कपड़े की इस संस्कृति को बचाए रखने और इसे बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए सरकार को डिजाइनरों, कारीगरों, बुनकरों के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बाजार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम किया जा सके और इस हस्तकला को बेहतर बनाने के लिए उपाय ढूंढे जा सकें। इस तरह, शोध और अन्य गतिविधियों के जरिये इस उद्योग को फैशन बाजार के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनाया जा सकेगा। घरों से जुड़े उत्पाद हों, फैशन का मामला हो या कोई अन्य उत्पाद, देसी संस्करण का जादू बिखेरा जा सकता है। नगालैंड की जसमिना जेलियांग ने बुनाई के अपने पुश्तैनी काम के जरिये साज-सज्जा, बास्केट बुनाई और नगा कपड़ों से तैयार घरेलू उत्पादों के क्षेत्र में शानदार काम किया है। साथ ही, इन उत्पादों को वैश्विक बाजार के हिसाब से तैयार किया गया है।

रोज़गार के प्राकृतिक तरीके, शिक्षा, डिजाइन के क्षेत्र में नियमित काम और शोध मौजूदा वक्त की जरूरत हैं। पूर्वोत्तर के मूगा, एरी और मटका सिल्क व सूती कपड़ों के अलावा कई और प्रयोग हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बांस और केले के पत्तों के अलावा नेटल फाइबर, कई तरह के सिल्क और ऊनी व अन्य मिले-जुले कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह, डिजाइनर और उपभोक्ताओं की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने की अलग चुनौती है। हालांकि, अब यहां बेहतर कलेक्शन तैयार होकर बड़े बाजारों में पहुंच रहे हैं। मेरे काम का मुख्य आधार यह है कि अतीत को भविष्य से जोड़े रखा जाए। मैंने 1999 में 'संस्कार' नाम

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

से अपना काम शुरू किया था। शुरुआत में मैं बचे-खुचे कपड़ों को रीसाइकल और अपसाइकल कर भारत-एशियाई आकार में कुछ ऐसा बनाता था, जो एक समूह के तौर पर हो। जब मैंने विदेश और भारत में फैशन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया, तो एरी सिल्क मेरे कलेक्शन का अहम हिस्सा बन गया। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। साल 2003 से मेरे कलेक्शन में पूर्वोत्तर के पारंपरिक अंदाज वाले कपड़े शामिल रहे हैं। इसके तहत मैंने मिली-जुली विरासत को ध्यान में रखते विभिन्न तरह की कशीदाकारी और आकारों पर काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया है कि इस तरह के उत्पादों की मांग दुनिया भर में है। मुझे अमेरिका, यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में बुलाया जाता है, जहां मैं फैशन, इतिहास और संस्कृति के बीच संबंधों के बारे में बात करता हूं। कनाडा के वैनकूवर शहर में 2016 में आयोजित 'इको फैशन वीक' में हिस्सा लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन के लिए बुलाया जाने वाला मैं पहला डिजाइनर था। इस कार्यक्रम में मैंने मूगा व एरी सिल्क और सिल्क रूट की कशीदाकारी और प्रिंट के बीच संबंध के बारे में बताने की कोशिश की। उत्तर अमेरिका में मेरी प्रतिनिधि और मानव विज्ञानी गेल पर्सी ने भी इससे सहमति जताई और हमें 2017 में फिर बुलाया गया। लेक्मे फैशन वीक 2018 में असम का प्रतिनिधित्व करने के लिए आईएमजी रिलायंस के क्रिएटिव रणनीतिकार गौतम वजीरानी ने मुझसे संपर्क किया। गौतम इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के कपड़ों, बुनाई और अन्य चीजों को प्रमुखता से पेश करना चाहते थे। मैंने सुआलकुची के बुनकरों द्वारा तैयार कलेक्शन को 'माजुली' के तौर पर पेश किया जो कपड़े और छाया चित्र के रूप में असम की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को पेश करता था। इस कलेक्शन ने मुख्य शो की पृष्ठभूमि में पूर्वोत्तर की समकालीन छवि पेश की और यह कोशिश काफी सफल रही। इसमें जेनजुम गादी जैसे डिजाइनरों की अहम भूमिका रही जिन्होंने नगालैंड के देसी हथकरघों से तैयार कपड़े को पुरुषों के कलेक्शन के तौर पर पेश किया।

- डेनियल सियम ने मेघालय के रिभोई जिले के बुनकरों द्वारा तैयार एरी सिल्क से जुड़े कलेक्शन को पेश किया।
- कर्मा सोनम ने सिक्किम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूती कपड़े और नेट की बुनाई वाले पुरुषों और महिलाओं के कलेक्शन पेश किए।
- रिचाना खुमानथम ने मणिपुर के मेतई समुदाय द्वारा तैयार कपड़ों का कलेक्शन पेश किया।
- अरात्रिक बर्मन ने त्रिपुरा की परंपरागत शैली में अपना कलेक्शन पेश किया, जिसमें स्कार्फ (हेडरैप) और मोतियों वाले हार पर जोर रहा।

पूर्वोत्तर मोजो में डिजाइनरों और लेक्मै फैशन वीक की अहम भूमिका रही। साथ ही, आईएमजी और संयुक्त राष्ट्र के एक संयुक्त कार्यक्रम में हम लोगों ने आजीविका की जरूरत, महिलाओं के सशक्तीकरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र की हस्तकला पर विशेष ध्यान देने को लेकर बात की। इसी तरह के मॉडल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार भी अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम कर सकती है। भारत में कृषि के बाद कपड़ा और फैशन क्षेत्र ही सबसे बड़े रोज़गार प्रदाता की भूमिका में हैं। हमें डिजाइन विशेषज्ञों और फैशन संचारकों के साथ मिलकर काम करना होगा। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर न सिर्फ जागरूकता पैदा कर सकते है, बल्कि देश और दुनिया में हमारे कपड़ों और जीवनशैली के बारे में लोगों को संवेदनशील तरीके से जानकारी भी मुहैया करा सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देसी कपड़ों की अनोखी संस्कृति है और हमें इस संस्कृति को बचाकर रखने के साथ-साथ इसे मौजूदा समय में ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक बनाना है। इस दिशा में मिल-जुलकर काम करने की शुरुआत हो चुकी है। इस दिशा में '7 वीव्स' नाम से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत असम के लोहारघाट वन क्षेत्र पर निर्भर स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कपड़ा-परिधान विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई है। इस उद्यम को मंदाकिनी गोगोई, उमा माधवन और ऋतुराज दीवान ने मिलकर शुरू किया है। हस्तकलाओं और फैशन के बीच इस तरह के और भी सहयोग की जरूरत है। इस तरह के मॉडल के विकास के लिए हमें काम करने का ज्यादा लोकतांत्रिक रवैया अपनाने होगा, ताकि कच्चे माल और तैयार माल के लिए बेहतर आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित सके। पुरानी चीजों को नए रूप में पेश करने वाले डिजाइनर के तौर पर मेरा मानना है कि हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचलन में मौजूद आजीविका के इन प्राकृतिक साधनों को बढ़ावा देना होगा। पूरी दुनिया अब प्राकृतिक जीवनशैली की तरफ बढ़ रही है और पूर्वोत्तर में यह जीवनशैली पहले से मौजूद है। इस बदलते हुए दौर में हमें विकास और प्राकृतिक जीवन को मिलाने की जरूरत है। खास तौर पर महानगरों में यह बेहद जरूरी है। ■

भारत में कृषि के बाद कपड़ा और फैशन क्षेत्र ही सबसे बड़े रोज़गार प्रदाता की भूमिका में हैं। हमें डिजाइन विशेषज्ञों और फैशन संचारकों के साथ मिलकर काम करना होगा। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर न सिर्फ जागरूकता पैदा कर सकते है, बल्कि देश और दुनिया में हमारे कपड़ों और जीवनशैली के बारे में लोगों को संवेदनशील तरीके से जानकारी भी मुहैया करा सकते हैं।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

नेक्टर: पूर्वोत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मजबूत आधार

निमिष कपूर

Elite Academy For Education, Delhi

नेक्टर-नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच अर्थात पूर्वोत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग और उसे लाभार्थियों तक पहुंचाने का केंद्र भारत सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा गठित स्वायत्त संगठन है जो पूर्वोत्तर के लोगों को प्रौद्योगिकी से संबद्ध सहायता और समर्थन उपलब्ध कराने वाली 'वन स्टॉप शॉप' है। नेक्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन किसानों, उद्यमियों तथा ग्रामीण निगमों, निर्माण कार्यों या किसी अन्य उद्योग से जुड़े किसी भी संगठन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और विज्ञान संबंधी समर्थन देता है जिसे जरूरत होती है।

नेक्टर की स्थापना 2012 में तत्कालीन नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशंस (एनएमबीए) और मिशन ऑन जियो-स्पेशियल (एमजीए) का विलय करके की गई थी। इसका मुख्यालय मेघालय के शिलांग में है। नेक्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को टेक्नोलॉजी के लाभ समझाने और पहुंचाने के उद्देश्य से उन तक पहुंचता है ताकि उन्हें टेक्नोलॉजी पर आधारित सर्वोत्तम सेवाएं और समाधान उपलब्ध हो सकें। नेक्टर को पूर्वोत्तर क्षेत्र के समानता पर आधारित समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का दायित्व सौंपा गया है।

कुछ वर्ष पहले तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के बैम्बू (बांस) बोर्ड उद्योग और उससे जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ी रुकावटें थीं। वैज्ञानिक तरीके और संपर्क-साधन न होने और काफी ज्यादा लागत आने के कारण उन्हें बाजार तक पहुंचाने में कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं। नेक्टर ने इन इकाइयों की मदद के लिए दो पहल शुरू कीं - पहली तो यह कि कच्चे माल (बांस की चटाई) तक पहुंच कायम की और दूसरे उन इकाइयों को देश के प्रमुख महानगरों के बाजारों से जोड़ा। उचित मूल्य पर कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर नेक्टर ने विभिन्न जनजातीय समूहों को बांस की चटाई बनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया और नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन के समर्थन वाली उत्पादन इकाइयों से उनका संपर्क स्थापित कराया। इससे बिचौलियों की दलाली पूरी तरह खत्म हो गई और वास्तविक चटाई बुनकरों को अपने माल की सर्वाधिक कीमत मिलने लगी तथा इकाइयों को भी बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलने लगा। बांस बोर्ड उद्योग को नेक्टर का कारोबारी समर्थन मिलने से बांस बोर्ड बनाने वाली 16 इकाइयों का विकास हुआ जिनमें से 9 इकाइयां पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेक्टर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समर्थन से जुड़ी सफलता की अनेक कहानियां हैं। जिन क्षेत्रों में नेक्टर ने प्रमुख भूमिका निभाई है उनमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, निर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में बांस का इस्तेमाल तथा कौशल विकास और रोज़गार पैदा करना शामिल है।

नेक्टर का गठन शिलांग में 2009 में आयोजित 96वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन की ही एक सिफारिश के आधार पर किया गया था जिसमें सुझाव दिया गया था कि इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को लोगों के आर्थिक लाभ और विकास में परिवर्तित करने

लेखक भारत सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग में विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ईमेल: nkapoor@vigyanprasar.gov.in

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

के उद्देश्य से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क कार्यालय खोला जाए। इसीलिए भारत सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने स्वायत्त संगठन नेक्टर के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नोडल सेंटर बनाने का निर्णय लिया।

नेक्टर की अनूठी और विशिष्ट भूमिका यही है कि वह राज्य सरकारों और अन्य संबद्ध संस्थानों के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित करता है और सामाजिक डिजाइनर का दायित्व निभाता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाता है जो कामयाब है और केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं तथा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के स्टॉर्ट-अप्स में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। नेक्टर आंतरिक सुरक्षा, जल संभरण विश्लेषण, फिक्स्ड विंग माइक्रो अन-मैन्ड (मानव रहित) हवाई वाहनों के विकास, सुनामी की आशंका वाले क्षेत्रों के मानचित्रीकरण, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों का मानचित्र तैयार करने तथा भूमि के कटाव का अध्ययन करने में भी इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता है।

जिन क्षेत्रों में नेक्टर ने प्रमुख भूमिका निभाई है उनमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, निर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में बांस का इस्तेमाल तथा कौशल विकास और रोज़गार पैदा करना शामिल है।

नेक्टर ने बांस के उत्पादों की ई-मार्केटिंग पोर्टल के जरिये बिक्री भी शुरू की है जिससे उसके समर्थन वाली इकाइयों और पूर्वोत्तर के स्थानीय लोगों को फायदा मिल सके तथा उत्पादक समूहों और उपभोक्ताओं के बीच की दूरी कम हो सके। यह सेंटर इन क्षेत्रों की जैविक विविधताओं से जुड़ी समस्याओं, बांस, खाद्य प्रसंस्करण, जल संभरण प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, बागवानी और नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरतों को स्थानीय उत्पादों और संसाधनों के हिसाब से पूरा करने का जिम्मा भी निभाता है। अभी तक बांस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कागज बनाने के और हस्तशिल्प उद्योगों में होता है। अब नेक्टर बन जाने से बांस के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी अपनाकर विविध उत्पाद बनाए जाने लगे हैं और बांस की मूल्य-संवर्धन गतिविधियां 10 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई हैं। नेक्टर ने बांस उत्पादों की व्यापक रेंज विकसित कर ली है, इससे अनेक उपकरण तैयार किए हैं और बाजार में बांस के नए उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। खासतौर पर छत और फर्श बनाने में बांस को इस्तेमाल करने की प्रौद्योगिकी का विकास और विस्तार किया है। कचरे और छीजन को इस्तेमाल करने की तकनीक भी विकसित की जा रही है।

लकड़ी के विकल्प तैयार करने की दिशा में अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और इन्हें व्यापारिक तौर पर अपनाया भी जा रहा है, प्लाईवुड की बंद यूनिटों की जगह बांस की प्लाई आ गई है, जूट और प्लास्टिक की जगह भी बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली उत्पादन और थर्मस जैसे उत्पादों में भी बांस का प्रयोग होने लगा है, कचरे और छीजन को काम में लाकर ईंधन जरूरतें पूरी की जा रही हैं, बांस से रेशेदार और कम चिकनाई वाले पदार्थ भी बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के लिए बांस की लुग्दी से साफ-सफाई के सामान भी बन रहे हैं, बांस की उपलब्ध नस्ल (किस्म) के अनुरूप मशीनें विकसित की जा रही हैं, अग्निरोधक, भूकंपरोधी और आसानी

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

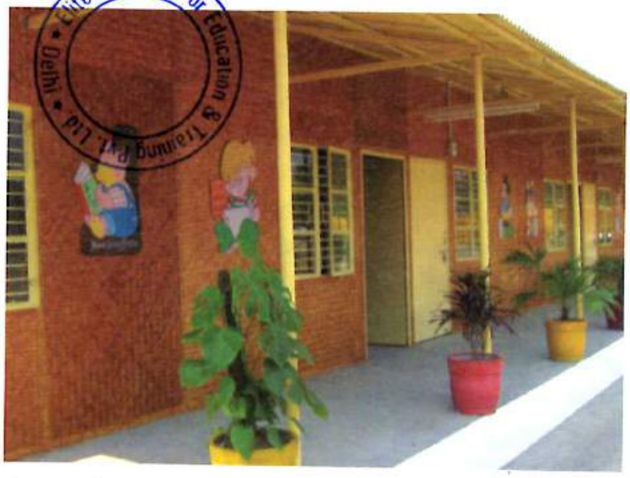

से इंस्टाल किए जाने वाले प्री-फैब्रिकेटेड और स्थायी ढांचे भी अब बांस से बनाए जाने लगे हैं जो ग्रामीण और शहरी मकानों, स्कूलों, अस्पतालों और आपदा-नुकसान कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।

केंद्र ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बांस की टहनी और अन्नानास प्रोसेसिंग तथा बड़ी मिर्च का अचार बनाने की यूनिटें लगाने में सहयोग और समर्थन दिया है। मधुमक्खी पालन गतिविधियों का विस्तार करने और मसालों की प्रोसेसिंग के लिए यूनिटें लगाने के लिए भी केंद्र मदद कर रहा है। शहद जांच प्रयोगशाला, चावल के मांड के फरमेंटेशन से ड्रिंक बनाने और मांस के नॉन-कैर्सिनोजेनिक स्मोकर्स जैसे उद्यमों को भी सहायता दी जा रही है। हल्दी, कालीमिर्च, तेजपत्ता और शहद जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर ने किसानों और प्रमुख महानगरों के बाजारों के बीच संपर्क विकसित किए हैं। जाने-माने ई-मार्केटिंग पोर्टलों के जरिए भी पूर्वोत्तर के इन उत्पादों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा की अपार संभावना है और तभी नेक्टर अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करके इन संसाधनों पर कार्य कर रहा है और इसका इरादा सौर, पवन, बायोमास और हाईब्रिड प्रक्रियाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित टेक्नोलॉजी विकसित करने का है।

हरित सामग्री पहल वाली बांस-आधारित प्रौद्योगिकियां

नेक्टर हरित सामग्री पहल के तहत बांस से बनी निर्माण सामग्री विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके तहत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से जुड़ी परियोजनाओं को मदद दी जा रही है और उच्च-टेनसाइल-स्ट्रेंथ तथा वेट-टु-स्ट्रेंथ - अनुपात के हिसाब से बांस के निर्माण विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के आधार पर ही विभिन्न उपयोगों के लिए भूकंपरोधी, कम भार वाले, टिकाऊ और आकर्षक ढांचे बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे रिहाइशी मकान और विशेष उद्देश्य वाली इमारतें बनाने में सुविधा हो जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस और बांस आधारित सामग्री को विभिन्न निर्माणों में इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नेक्टर की अनूठी और विशिष्ट भूमिका यही है कि वह राज्य सरकारों और अन्य संबद्ध संस्थानों के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित करता है और सामाजिक डिजाइनर का दायित्व निभाता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाता है जो कामयाब है और केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं तथा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के स्टॉर्ट-अप्स में आसानी से उपलब्ध हो सकती है।

लकड़ी के विकल्पों और कम्पोजिट्स के बारे में प्रौद्योगिकियों के विकास के क्षेत्र में बैम्बू कम्पोजिट मैटिरियल और प्री-फैब्रिकेटिड आवासीय यूनिटों का इस्तेमाल करके विभिन्न राहत और पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उद्यम के तौर पर इनकी जांच की जा चुकी है और इन्हें व्यापारिक विस्तार दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रभावित इलाकों में इंजीनियर्ड बांस से स्कूलों के 676 कमरे बनाए गए हैं जिनमें 25 हजार बच्चे बैठते हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में प्रतिगूंजरोधी कम्पोजिट सामग्री से निर्माण बनाए गए हैं जिनके दरवाजे और खिड़कियों में बांस-बोर्ड इस्तेमाल किया गया है। लेह और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने से आने वाली अचानक बाढ़ से होने वाला नुकसान कम से कम करने के उद्देश्य से करीब 55 हजार वर्गफुट क्षेत्र में प्री-फैब्रिकेटेड आवासीय परिसर बनाया गया है जिसमें 10 हजार लोग एक साथ रह सकते हैं।

सिक्किम में राहत और पुनर्वास कार्यों के तहत तीन जगहों पर 10 बड़ी आवासीय यूनिटें बनाई गई थीं। मणिपुर में 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत 'मिड-डे मील योजना' के तहत किचन-सह-स्टोर बनाने के लिए बांस के प्री-फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए गए थे। स्वच्छ और नवीकरणीय बिजली का उत्पादन करने के लिए बांस के बने गैसीफायर्स विकसित किए गए हैं और हाईग्रेड चारकोल जैसे कई उपयोगी सह-उत्पाद भी विकसित किए गए हैं।

बांस की छीजन और कचरे से बढ़िया किस्म का लकड़ी का कोयला और एक्टिवेटिड कार्बन बनाने की प्रक्रिया के तहत अनुसंधान और विकास के लिए बांस के विविध और व्यापक औद्योगिक इस्तेमाल की पहचान की गई है। बांस का प्रयोग दुर्गंधनाशक, कीटाणुनाशक, औषधि, कृषि रसायन और प्रदूषण तथा अत्यधिक नमी को सोखने वाले उत्पाद तैयार करने में किया जाने लगा है। नेक्टर

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

ने प्लास्टिक कम्पोजिट उत्पादों, मेकेनाइज्ड बैम्बू ब्लाइंड्स, एक्रिलिक उत्पादों, फाइबर से बने हाइजिन उत्पादों आदि अनेक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। बांस की कलम की आयु का पता लगाने के लिए केंद्र ने परिपक्वता नापने की प्रणाली भी विकसित की है। इस प्रणाली में बांस की कलम के फूटने (निकलने) का वर्ष पेंट से अंकित किया जाता है। नेक्टर ने फ्लूट टेक्नोलॉजी (बांसुरी प्रौद्योगिकी) विकसित की है जिसे कलम कटाई या स्टेम सैटिंग (डंठल रोपण) तकनीक कहा जाता है जिससे बांस का प्रथम रीजैनरेशन (नवजीवन) होता है।

नेक्टर ने ग्रामीण लोगों को समुचित और टिकाऊ आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। विभिन्न गतिविधियों और खासकर निर्माण और चटाई बनाने के उद्योग में ही नेक्टर ने प्रतिवर्ष करीब 3 करोड़ जनदिनों के रोज़गार के अवसर जुटाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला बुनकर चटाई बनाने की गतिविधियों में लगी हुई हैं और आमदनी करने के साथ ही अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल हो रही हैं।

कौशल आधारित प्रशिक्षण से मानव संसाधनों का विकास

नेक्टर ने ग्रामीण लोगों को समुचित और टिकाऊ आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। विभिन्न गतिविधियों और खासकर निर्माण और चटाई बनाने के उद्योग में ही नेक्टर ने प्रतिवर्ष करीब 3 करोड़ जनदिनों (मैन डेज़) के रोज़गार के अवसर जुटाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला बुनकर चटाई बनाने की गतिविधियों में लगी हुई हैं और आमदनी करने के साथ ही अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल हो रही हैं। गांवों और सामुदायिक स्थलों में बांस की डंडियों का निर्माण करने के लिए नेक्टर और किफायती दरों पर कच्चा माल देने के अलावा कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग भी देता है तथा प्रोसेसिंग के लिए बुनियादी मशीनें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। चटाई बुनने, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, बांस की टहनियों की प्रोसेसिंग, अगरबत्ती बनाने जैसी गतिविधियों में लगे लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। मधुमक्खी पालन, बुनकरी आदि क्षेत्रों में भी व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रोज़गार जुटाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों की योजनाएं

यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो बड़ी योजनाएं चला रहा है। पहली है 'टॉस' अर्थात टेक्नोलॉजी आउटरीच एंड सर्विस स्कीम तथा दूसरी 'बांस' अर्थात बैम्बू एप्लीकेशन्स एंड सपोर्ट स्कीम। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य लोगों, समुदायों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, स्व-सहायता समूहों और अनुसंधान तथा टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी बनाकर इस क्षेत्र का विस्तार करना है।

'टॉस' नेक्टर की प्रमुख योजना है जिसके तहत लोगों और संस्थानों से संपर्क बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान तैयार किए जाते हैं जिनसे इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव हो सकती है। इसके माध्यम से लोगों को अपने उत्पादों और सेवाओं में मूल्यसंवर्धन और सुधार करके अपना जीवन बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। फिर यह कि इसके लिए स्थानीय प्राकृतिक और मानव संसाधन ही पर्याप्त होते हैं।

दूसरी योजना 'बांस' में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था के अंतर्गत रोज़गार जुटाने और आजीविका के टिकाऊ साधन उपलब्ध कराने के लिए बांस के प्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता दी जाती है और यह योजना विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के लोगों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। इस योजना से सामुदायिक समूहों, स्वयं-सहायता समूहों और लोगों के विकेंद्रित संघों को भी बांस उत्पादों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों और मूल्य संवर्धन प्रोसेसिंग के लिए तथा बांस प्रौद्योगिकियों के विस्तार और सशक्तीकरण के उपाय अपनाने के लिए मदद दी जाती है।

नेक्टर ने फरवरी, 2019 के तीसरे सप्ताह में हुई बेमौसम बरसात से आलू की फसल को हुए नुकसान का वैज्ञानिक विश्लेषण करने हेतु 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए टेक्नोलॉजी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था। इसने दो जिलों में करीब 12,035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके 25 दिन के रिकॉर्ड समय में समूचा फील्ड वर्क और विश्लेषण करके अंतरिम और फाइनल रिपोर्ट एनआईसी को सौंप दी।

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों को रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एप्लीकेशन्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करने का अनुभव कराना भी था।

3-डी डिजिटल टेरेन मॉडलों के प्रयोग से आंतरिक सुरक्षा एप्लीकेशन

3-डी डिजिटल टेरेन मॉडलों को राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल घुसपैठ रोकने की और फील्ड ऑपरेशन चलाने की गतिविधियों की योजना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और शेष भारत के लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का डिजिटल नक्शों और उच्च रेजोल्यूशन चित्रों और एलिवेशन डाटा के रूप में करीब 70 टेट्राबाइट्स डिजिटल डाटा की सफलतापूर्वक मैपिंग और प्रोसेसिंग करके 3-डी टेरेन डिजिटल मॉडल तैयार किए गए हैं। इस केन्द्र के अत्यधिक कुशल तकनीकी कर्मियों ने देश के विभिन्न स्थानों और स्टेशनों में विभिन्न अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों को इनके सफलतापूर्वक इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी है।

नेक्टर ने 3-डी टेरेन मॉडल की मदद से विभिन्न श्रेणियां (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्तर) के स्कूलों की नेबरहुड मैपिंग और जीआईएस विश्लेषण किया है। केंद्र ने भारत सरकार के 'शिक्षा के अधिकार' कार्यक्रम के मानकों के आधार पर उन जगहों में स्कूल बनाए हैं जहां अभी तक स्कूल नहीं थे। असम में 66,115 स्कूलों और 81,240 बस्तियों का और मणिपुर में करीब 4,460 स्कूलों का विश्लेषण किया गया है।

मानवरहित फिक्स्डविंग माइक्रो हवाई वाहन

नेक्टर द्वारा विकसित मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) फिक्स्ड विंग किस्म के माइक्रो यूएवी हैं। ये स्वत: निर्देशित विमान हैं जिनमें विभिन्न किस्मों के उपभोक्ता सेंसर भेजे जा सकते हैं और इन-बिल्ट जीपीएस की मदद से भूमि पर भेजे जा सकने वाले चित्र लिए जा सकते हैं। रेडियो नियंत्रण वाले इस ग्लाइडर विमान में एक छोटा जीपीएस, एक अति लघु ऑटो पायलट और कंज्यूमर ग्रेड वाला डिजिटल कैमरा लगा रहता है। इस यूएवी को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 5 पौंड भार वाला यह विमान किसी भी लोकेशन से लांच किया जा सकता है। इसका शक्तिशाली ऑटो पायलट ही इसे पूर्वनिर्धारित ऊंचाई पर चलाता है। उड़ान सत्र के दौरान यूएवी वापिस वहीं लौट आता है और ऑपरेटर इसे हाथ से लैंड कराता है।

नेक्टर के माइक्रो यूएवी से सुनामी की आशंका वाले 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के चित्र खींचकर नक्शा तैयार किया गया था। 3-डी टेरेन मॉडल इस्तेमाल करने से बाढ़ के प्रकोप वाले क्षेत्र और उससे प्रभावित होने वाली इमारतों, ढांचों और आबादी का काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है।

बाढ़ से होने वाले भयंकर नुकसान और उसे कम से कम रखने के तरीकों को दर्शाने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे करीब 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के डिजिटल सर्फेस मॉडल (डीएसएम) और लैंड यूज डाटा की केस स्टडी पूरी की जा चुकी है। इस क्षेत्र के चित्रों से सुरक्षा तटों की स्थिति और भूमि के कटाव की हालत की जानकारी मिली है।

नेक्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रौद्योगिकियों को सामान्य लोगों, विभिन्न संगठनों, उद्यमियों और किसानों से जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि उस टेक्नोलॉजी का मैंडेट सिद्ध हो जाए। पूर्वोत्तर के लोगों को नेक्टर द्वारा विकसित और समर्थित प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिए। नेक्टर की सफलता की कहानियों को पूर्वोत्तर के कृषि विज्ञान केंद्रों, एनजीओ, सामुदायिक केंद्रों, नवाचार केंद्रों और कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में भेजा जाना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग इनका लाभ प्राप्ति कर सकें।

नेक्टर की योजनाओं का विवरण www.nectar.org.in पर उपलब्ध है। ■

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

बांस : आजीविका का महत्वपूर्ण संसाधन

अंकिता शर्मा

एक लोकप्रिय कहावत है कि अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए भीतर देखें। इसी प्रकार जब भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए रास्ते खोलने की बात आती है, तो इसके लिए सामाजिक-आर्थिक संधारणीयता के उत्प्रेरक के रूप में एक प्रमुख संसाधन-बांस का कायाकल्प करना आवश्यक होगा।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक- बांस, कई तरह की जलवायु परिस्थितियों में जीवित रह सकता है और पनप सकता है। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उपयोग किये जाने वाले बांस की अनुकूलन क्षमता, कम लागत और आसान तथा बहु उपयोग इसे संसाधन-कुशल आजीविका के लिए एक आदर्श सामग्री बनाते हैं। बांस का उपयोग जीवन के कई क्षेत्रों में किया जाता है। कई लोग घरों के निर्माण के लिए बांस का उपयोग करते हैं। बांस का उपयोग हस्तशिल्प जैसे चटाई, फर्नीचर और टोकरियां, खिलौने, सजावटी सामान और उपकरण तथा औजार बनाने में किया जा सकता है। गरीब इंसान की लकड़ी के रूप में विख्यात बांस की उपयोगिता और जीवन शक्ति इसे एक अनमोल कृषि-वानिकी संसाधन बनाती है।

वैश्विक उद्योग रिपोर्ट 2019-2025 के अनुसार, बांस का वैश्विक बाजार 2018 में 68.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था और 2019 से 2025 तक इसके 5.0 प्रतिशत की सीएजीआर (वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोत्तरी दर) से बढ़ने की आशा है। आधुनिक प्रौद्योगिकियां बांस को टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता की लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग करने के तरीके उपलब्ध कराती हैं।

भारत में, वन क्षेत्र और विविधता की दृष्टि से बांस एक महत्वपूर्ण पौधा है। यह देश भर में 13.96 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। बांस मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख रूप से फल-फूल रहा है। वास्तव में, अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के कुल बांस का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है और भारत में अनुमानतः बांस की लगभग 125 स्वदेशी और 11 विदेशी किस्में पाई जाती हैं, जिससे देश अंतरराष्ट्रीय बांस निर्यात में एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है।

हालांकि, विश्व में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत में, इस क्षेत्र में वांछित विकास नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों में, भारत बांस उत्पादों के निर्यात की तुलना में अधिक आयात कर रहा है। अनुमानों के अनुसार, भारत में बांस की खेती का केवल 6 प्रतिशत बाजार तक पहुंचता है। घरेलू बांस उद्योग इसकी मूल्य श्रृंखला में कई तरह के मुद्दों के कारण पीछे है, जिनमें बांस की खेती और कटाई के लिए नियामक तथा विधायी बाधाएं, इसकी खरीद में चुनौतियां, बांस के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं में तकनीकी जानकारी की कमी और अपर्याप्त बाजार मांग शामिल हैं।

इस संदर्भ में, कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ, सबका विकास के साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों से, बांस क्षेत्र एक उत्कृष्ट अवसर मिल पाया है।

बांस के बहुउद्देशीय और पर्यावरण के अनुकूल उपयोग ने इसे ग्रामीण आबादी के लिए एक सार्वभौमिक संसाधन बना दिया है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया है। इसका

लेखिका इन्वेस्ट इंडिया की कार्यनीतिक निवेश अनुसंधान इकाई में सहायक उपाध्यक्ष हैं। ईमेल: ankita.sharma@investindia.org.in

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करना, ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देना, खेती में कठिनाइयों को कम करना और किसानों तथा गैर-कृषि व्यवसायों में काम करने वालों की आय के बीच समानता लाना है। इसे संभव बनाने के लिए बांस की खेती को प्रोत्साहित करना और इसकी विपणन क्षमता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

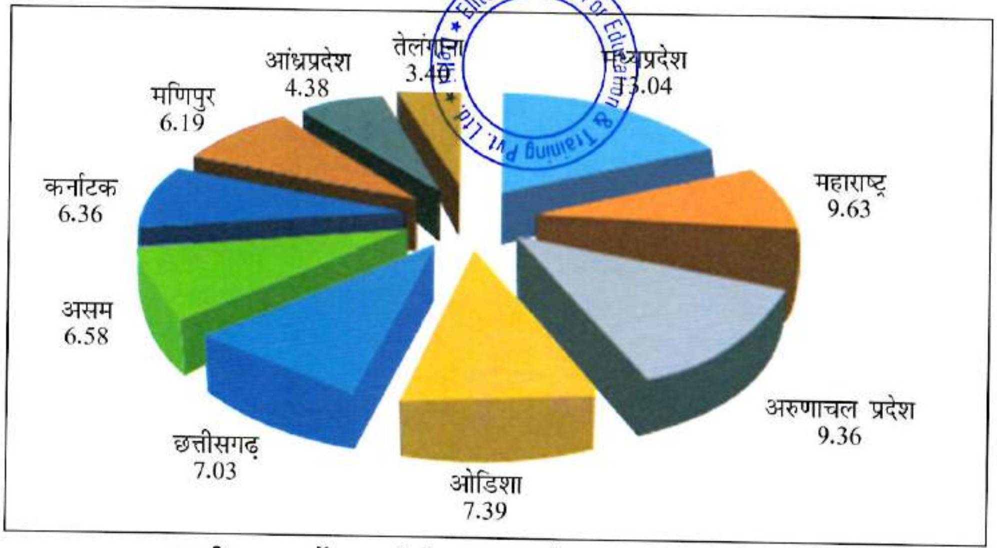

भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2019 के अनुसार राज्यवार वितरण

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

भारत में बांस उद्योग के तहत मांग वृद्धि के कारक

जनसंख्या तथा आय वृद्धि; बढ़ते निर्यात और अनुकूल जनसांख्यिकी; हाइब्रिड तथा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज; कृषि तथा विविध फसलों के अनुकूल जलवायु; मशीनीकृत सिंचाई सुविधाएं; पूर्वी भारत में हरित क्रांति; भारत में मजबूत जनसांख्यिकीय तथा व्यापक श्रम शक्ति की उपलब्धता; संस्थागत ऋण में वृद्धि; न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि; परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी नई परियोजनाओं की शुरुआत; किसान रथ (किसानों, एफपीओ और व्यापारियों के लिए मोबाइल ऐप); 200 से अधिक किसान रेल और उत्पाद परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना तथा खराब होने वाली वस्तुओं के लिए हवाई अड्डों पर कार्गो केंद्र, शीत भंडार और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के साथ-साथ कार्गो टर्मिनल गोदामों की सुविधा जैसी पहल।

भारत में बांस क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक बहु-हितधारक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस दिशा में कार्यनीतिक पहल की हैं।

सितंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नौ राज्यों- गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में वर्चुअल माध्यम से 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए लोगो भी जारी किया गया। बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत में लोगों की आजीविका के स्रोत के लिए बांस उद्योगों के सतत विकास के वास्ते एक परियोजना तैयार की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 4 पी 1000 पहल: सीओपी 14 यूएनसीसीडी 2019 में बंबूनॉमिक्स के माध्यम से जनजातीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की है। नीति आयोग ने उपलब्ध खाली भूमि संसाधनों के उपयोग और किसानों के लिए वित्तीय वहनीयता के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अपनी तरह की पहल के तहत जुलाई 2020 में राज्य सरकारों को बांस और चंदन वृक्षारोपण अभियान चलाने का आग्रह किया।

इस तरह की पहल देश में बांस की संगठित खेती की संरचना ला सकती है और ग्रामीण आबादी के लिए अधिक आय की सुविधा प्रदान कर सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान हो सकता है।

भारत सरकार समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बांस क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें जानकारी के प्रसार और खेती के उत्तम तरीकों के आदान-प्रदान के मजबूत तंत्र का निर्माण, तकनीकी मानकों में सुधार, क्षमता निर्माण और काश्तकारों का कौशल विकास, बांस स्टार्टअप में सहयोग और बांस उत्पादों के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना शामिल हैं। ■

राष्ट्रीय स्तर	
एमओईएफसीसी/पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय बांस मिशन/विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
⇩	
क्षेत्रीय स्तर	
पूर्वोत्तर परिषद/बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीटीसी)	पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी केंद्र (एनईसीटीएआर)/एआरसीबीएआर
⇩	
राज्य स्तर	
राज्य बांस मिशन/राज्य वन विभाग	राज्य उद्योग विभाग/कारोबार विकास एजेंसियां

www.ourstudycircle.in/upscpdf

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार	
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com
हमसे संपर्क करें- **फोन: 011-24367453,** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... जिला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

www.ourstudycircle.in/upscpdf/
Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

खेलों में तेज़ी से आगे बढ़ता पूर्वोत्तर

राजेश राय

आठ राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से मिलकर बना भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 8 फ़ीसदी है लेकिन खेलों के मामले में यह तेज़ी से अग्रसर हो रहा है।

भारत के कई प्रमुख खेलों के खिलाड़ी, पूर्वोत्तर क्षेत्र से निकले हैं और फुटबॉल, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, हॉकी और भारोत्तोलन में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। फुटबाल तो खास तौर पर इस क्षेत्र की जान है। देश के अधिकतर क्लबों में पूर्वोत्तर के खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत, भारत के कुछ जाने माने खिलाड़ियों का घर है जैसे छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम, पूर्व फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की रजत विजेता एल सरिता देवी, स्वर्ण विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता जयंत तालुकदार 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू, और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण विजेता और देश के शीर्ष खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित भारोत्तोलक सैखोम मीरा बाई चानू कुछ ऐसे नाम हैं जो इस समय सबकी जुबान पर हैं और आने वर्षों में भी याद किये जाएंगे।

एक सर्वेक्षण के अनुसार 14 हजार से ज्यादा प्रतिभाशाली पूर्वोत्तर के खिलाड़ी देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनमें 10 हजार लड़के और चार हजार लड़कियां शामिल हैं।

- साई केंद्रों में चार हजार लड़की प्रशिक्षुओं में से 23 फीसदी यानी 910 अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में प्रशिक्षित हो रही हैं। इन्हें 290 साई केंद्रों में आवासीय और गैर आवासीय आधार पर 27 खेलों में ट्रेनिंग दी जा रही है।
- देश में स्थित 14 क्षेत्रीय फुटबॉल अकादमियों में से एक अकादमी इम्फाल में स्थित है। असम और मणिपुर में हर तरह के मौसम के लिए सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बने हुए हैं।

पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों ने वापस अपने समुदाय को भी कुछ न कुछ दिया है।

मैरीकॉम और कुंजरानी देवी ने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय मुक्केबाजी और भारोत्तोलन अकादमियां खोली हैं। ये अकादमियां छात्रों को मुफ्त कोचिंग के अलावा मुफ्त ठहरना और खाना भी उपलब्ध कराती हैं, इसके अलावा वे प्रतियोगिताओं के दौरान अतिरिक्त खर्चे भी कवर करती हैं।

असम राज्य शिक्षा और खेलों पर 35 फीसदी खर्च करता है जो 16 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से दोगुना से भी ज्यादा है।

मिज़ोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा

मिज़ोरम मंत्रिमंडल ने 22 मई 2020 को राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। मिज़ोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मिज़ोरम ने देश से खेल जगत में अपनी पहचान बनाई है। मिज़ोरम ने खासकर फुटबाल में अपनी पहचान बनाई है। राज्य के कई खिलाड़ी देश के अलग-अलग फुटबाल क्लबों में खेल रहे हैं। इस राज्य ने फुटबॉल के अतिरिक्त हॉकी और भारोत्तोलन में भी अच्छा किया है। मिज़ोरम के लगभग 150 खिलाड़ी भारत की शीर्ष फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में खेलते हैं।

143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला

केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए सात राज्यों में कुल 143 'खेलो इंडिया' केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिस पर कुल 14.30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिज़ोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें से तीन राज्य तो पूर्वोत्तर में ही हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'भारत को 2028

लेखक, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। ईमेल: rajeshraivarta@gmail.com

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

पूर्वोत्तर को रोशन करतीं

पूर्वोत्तर में ज्यादातर महिला खिलाड़ी तीन राज्यों मणिपुर, असम और मिज़ोरम से हैं। मणिपुर से लीजेंड मुक्केबाज़ एम सी मैरीकाम, सात बार विश्व चैंपियनशिप की रजत विजेता भारोत्तोलक कुंजरानी देवी, हॉकी खिलाड़ी अनुराधा देवी थोकचोम, फुटबॉलर रतनबाला देवी, फुटबॉलर नंगगोम देवी हैं। असम से मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहैन, तीरंदाज गहेला बोरो, मुक्केबाज जमुना बोरो और मीराबाई चानू हैं। मिज़ोरम से हॉकी खिलाड़ी लालरेमसियामि हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला पर्वतारोही अंशु जामसेनपा अरुणाचल प्रदेश से, दीपा करमाकर त्रिपुरा से तथा तीरंदाज चेक्रोवोलु स्वुरो नगालैंड से हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत के कुछ सबसे अधिक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर हैं। 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता और छह बार की विश्व शौकिया-मुक्केबाजी चैंपियन मैरीकॉम, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता मुक्केबाज एल सरिता देवी, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के. संजीता चानू और मीराबाई चानू, जिन्होंने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीतने के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, कुछ ऐसे नाम हैं। मीराबाई ने टोक्यो ओलम्पिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। मुक्केबाज मैरीकॉम और लवलीना बोर्गोहैन भी टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।

जनसंख्या के अनुसार पूर्वोत्तर भारत कुल भारतीय आबादी का केवल 3.7 प्रतिशत है। वहां के युवा विभिन्न खेलों, विशेष रूप से मणिपुर के लोग खेलों के प्रति अपने झुकाव के लिए जाने जाते हैं।

एमसी मैरीकॉम

पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर की इस महिला बॉक्सर ने अपनी बॉक्सिंग के दम पर पूरी दुनिया में अपना और भारत का नाम रोशन किया है। मैरी 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। उन पर बायोपिक बन चुकी है। राज्यसभा सांसद बन चुकी मैरी को हाल ही में बेस्ट एशियन वूमन एथलीट अवॉर्ड भी दिया गया है। इससे पहले मैरी कॉमनवेल्थ गेम्स सहित कई प्रतियोगिताओं में ढेरों गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हाल में उन्होंने दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी में रजत पदक जीता जो उनका सातवां एशियाई पदक था। उन्होंने देश को टोक्यो ओलम्पिक का कोटा भी दिलाया है।

हिमा दास

असम के धिंग की रहने वाली धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हो चुकी हिमा दास ने हाल ही में विश्वस्तरीय रेसिंग में एक के बाद एक लगातार 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। हिमा को असम सरकार द्वारा राज्य में खेलों की ब्रांड एम्बेसेडर भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उनको यूनिसेफ इंडिया की यूथ एंबेसेडर भी नियुक्ति किया जा चुका है।

दीपा करमाकर

त्रिपुरा की रहने वाली दीपा ने पहली बार 2016 समर ओलंपिक भारतीय जिम्नाष्ट के तौर पर भाग लिया था। इससे पहले उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ओलंपिक खेलों में भारतीय जिम्नास्ट के तौर पर भाग लेने वाली वो

ओलंपिक में शीर्ष दस देशों में शामिल करने का हमारा प्रयास है। इसे हासिल करने के लिए हमें खिलाड़ियों की उनकी छोटी उम्र में ही पहचान करने और उन्हें निखारने की आवश्यकता है। राज्यवार के हिसाब से पूर्वोत्तर में स्थापित होने वाले खेलो इंडिया केंद्रों का विवरण इस प्रकार है-

मिज़ोरम: 20 लाख रुपये के बजट अनुमान के साथ कोलासिब जिले में दो खेलो इंडिया केंद्र।

अरुणाचल प्रदेश: 4.12 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 26 जिलों में 52 खेलो इंडिया केंद्र।

मणिपुर: 1.60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 16 खेलो इंडिया केंद्र।

संबंधित राज्य सरकारों को अब इन सभी केंद्रों के लिए पूर्व चैंपियन एथलीटों को नियुक्त करना होगा। जमीनी स्तर पर देश में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, एक कम लागत वाला, प्रभावी खेल प्रशिक्षण ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें पूर्व चैंपियन एथलीट युवाओं के लिए प्रशिक्षक और सलाहकार बनेंगे।

मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोम्बम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। हॉकी के शासी निकाय, हॉकी इंडिया ने 6 नवंबर, 2020 को अपनी 10वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस और चुनाव आयोजित किए, जहां ज्ञानेंद्र निंगोम्बम, निर्विरोध चुने जाने पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। निंगोम्बम पिछले 40 वर्षों से राज्य में हॉकी के खेल से जुड़े हैं। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हॉकी के खेल के विकास में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

मुक्केबाजी के पहले सुपरस्टार डिंको सिंह

मणिपुर के इम्फाल के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज नगंगोम डिंको सिंह का कैंसर और कोरोना से जूझने के बाद जून 2021 में निधन हो गया। वह मात्र 42 वर्ष के थे। डिंको की लोकप्रियता का आलम यह था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में स्टार मुक्केबाज के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, "डिंको

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

महिला खिलाड़ी

पहली महिला खिलाड़ी भी बनी हैं। 2016 के रियो ओलम्पिक में दीपा ने ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था जिसके कारण दीपा को 2016 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड और 2017 में पद्मश्री पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है।

शैखोम मीराबाई चानू

मणिपुर की रहने वाली शैखोम मीराबाई चानू भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं जो अब तक कई विश्व चैंपियनशिप्स में कई सारे मेडल्स जीत चुकी हैं। उनको अपनी इस उपलब्धि पर पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। चानू ने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा उन्होंने विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपना व देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आइ डब्ल्यू यू एस) ने मीराबाई चानू के महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की पुष्टि कर दी है। चानू ने अप्रैल में ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित किया था, जिसकी अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। चानू ने आइ डब्ल्यू यू एस की रैंकिंग सूची के आधार पर कोटा हासिल किया। वह भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर हैं।

कुंजरानी देवी

कुंजरानी ने 1985 से राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर स्वर्ण पदक जीतने शुरू कर दिए। 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम और 48 किलोग्राम में भारोत्तोलन चैंपियनशिप, बाद में उसका यह अंतिम भार वर्ग रहा। उन्होंने 1987 में तिरुअनंतपुरम में दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। 46 किलोग्राम भार वर्ग में अपने वजन में बदलाव करते हुए उन्होंने 1994 में पुणे में एक स्वर्ण जीता, लेकिन मणिपुर में चार साल बाद 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने पर उन्हें रजत मिला।

उनकी पहली विश्व महिला भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 1989 में मैनचेस्टर संस्करण थी और उन्होंने तीन रजत पदक जीते। तब से उन्होंने लगातार सात विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया और 1993 में मेलबर्न संस्करण के अपवाद के साथ, उन्होंने उन सभी प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में रजत पदक जीता।

कुंजरानी का एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन रहा है, जिसके लिए वह एक नियमित हिस्सेदार रही हैं। 1989 के शंघाई में एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ शुरुआत करते हुए, उन्होंने इंडोनेशिया में 1991 के संस्करण में 44 किलोग्राम वर्ग में तीन रजत पदक हासिल किए। 1992 में थाईलैंड में अगले में पहला और 1993 में चीन में उन्होंने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1995 में दक्षिण कोरिया में प्रतियोगिता में आया जहां उन्होंने 46 किलोग्राम वर्ग में दो स्वर्ण और एक कांस्य जीता।

1996 में उन्हें जापान में आयोजित चैंपियनशिप में दो रजत और एक कांस्य मिला। उन्हें 1990 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न को लिएंडर पेस के साथ वर्ष 1996-1997 में बांटा। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उनके पास पचास से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक हैं। उन्होंने 38 साल की रिटायरमेन्ट लेने वाली उम्र में 48 किग्रा वर्ग में 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, जो कि मेलबर्न में आयोजित किया गया, जिसमें 166 किलोग्राम की कुल लिफ्ट के साथ खेलों का रिकॉर्ड था जिसमें स्नैच में 72 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 94 किग्रा भार शामिल था।

सिंह एक खेल सुपरस्टार और एक उत्कृष्ट मुक्केबाज थे, जिन्होंने कई पुरस्कार जीते और मुक्केबाजी की लोकप्रियता को आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया। डिंको सिंह ने 13वें एशियाई खेलों में बैंकॉक में 54 किग्रा वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय नौसेना में सेवा की थी। उन्होंने 1997 में बैंकॉक में किंग्स कप भी जीता था। मुक्केबाजी में देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

शिव थापा : असम के गुवाहाटी के रहने वाले और पांच बार एशियन मेडल जीतने वाले शिव थापा पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट्स कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा वो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी के तौर पर 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी भाग ले चुके हैं। थापा तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है।

बाईचुंग भूटिया : मणिपुर के भूटिया देश के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर, 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, पूर्व कप्तान रह चुके हैं।

पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

मणिपुर में इम्फाल में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के देशभर में 'दूरस्थ परिसर' (आउटलाइंग कैंपस) खोले जाएंगे जो एनएसयू के उद्देश्य को हासिल करने में मदद करेंगे। इस पहले खेल विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण जैसे विषयों पर अध्ययन-अध्यापन और शोध आदि किया जाएगा। विश्वविद्यालय अपने तरह का इकलौता होगा और यहां अंतराष्ट्रीय मानक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय नामक इसी तरह के तीन राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं जबकि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान नामक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले से खेलकूद के क्षेत्र में संचालित है। ■

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

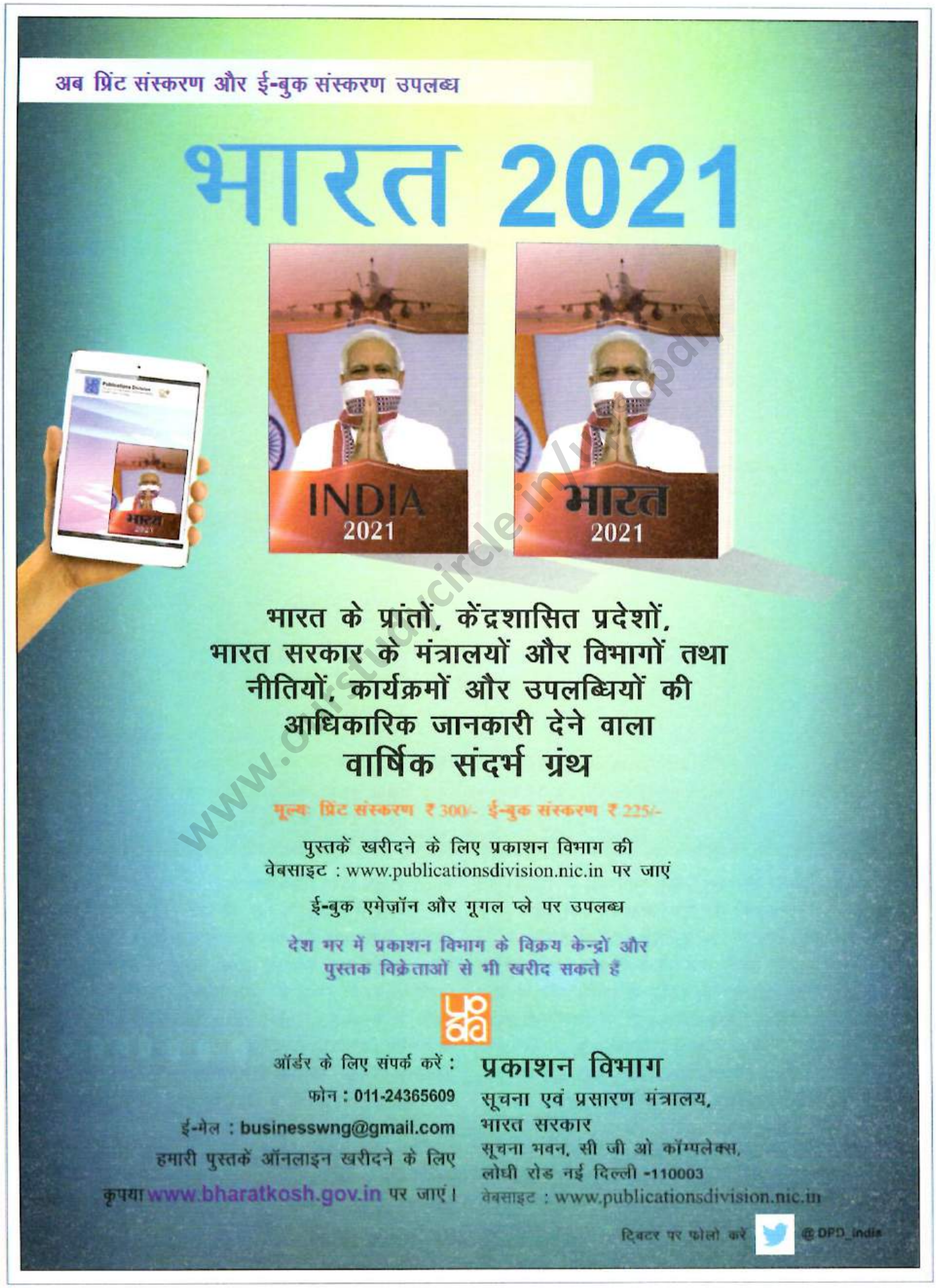

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

पूर्वोत्तर भारत के स्वातंत्र्य वीर

लेखिका - स्वर्ण अनिल

आईएसबीएन : 978-93-5409-069-1
मूल्य : 135 रुपये

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर यह स्वतंत्रता संग्राम ना हुआ होता, अगर भारत माता के वीर सपूत ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से ना उखाड़ देते तो शायद आज स्वतंत्र देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव ना मना रहे होते। इसलिए भारत के कण-कण में उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपार आदर एवं श्रद्धा बसी हुई है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे कर देश को आज़ाद कराया।

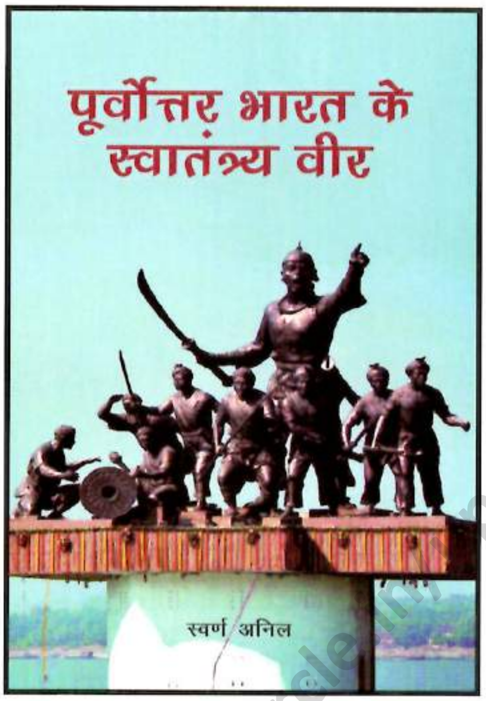

भारत के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विद्रोह एवं आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। समय-समय पर हुए विद्रोह एवं आंदोलन जैसे '1857 का विद्रोह', 'असहयोग आंदोलन', 'नागरिक अवज्ञा आंदोलन', 'भारत छोड़ो आंदोलन' ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। अंततः अगस्त 1947 में भारत को शासकों, क्रांतिकारियों और आम नागरिकों की कड़ी मेहनत, त्याग और निःस्वार्थता के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई।

इस स्वतंत्रता संग्राम में भारत भूमि के पूर्वोत्तर हिस्से के वीर सेनानियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुस्तक 'पूर्वोत्तर भारत के स्वातंत्र्य वीर' के जरिए लेखिका स्वर्ण अनिल ने 22 स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन एवं संघर्षों से पाठकों को अवगत कराने की कोशिश की है।

'भारत छोड़ो आंदोलन' में पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक लंबी सूची है जिसमें एक ओर 17 वर्ष की कनकलाता बरूआ हैं तो दूसरी ओर 60 वर्षीय भोगेश्वरी फुकनानी और दोनों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। पुत्र मोह और अपने प्राणों का मोह छोड़कर मातृभूमि का चयन करने वाली मिज़ो रानी रोपुइलीयानी ब्रिटिश अफसरों की बर्बरता को अपने बेटे के साथ सहते हुए शहीद हुई पर परतंत्रता नहीं स्वीकारी। 'आज़ाद हिंद' की कई अमर महिला सेनानियों का उल्लेख मणिपुर सरकार के दस्तावेज में मिलता है।

पूर्वोत्तर के कई अन्य क्रांतिकारी भी देश प्रेम के अपराध में काले पानी की भीषण और अमानवीय यातनाओं का शिकार हुए। अंग्रेजों की गोलियों को हंसते-हंसते झेलने वाले, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन प्रहरियों की जीवन गाथाओं को संग्रहित करने का लेखिका ने सफल प्रयास किया है।

पुस्तक से लिए गए अंश...

भारत की स्वतंत्रता को समर्पित स्वाधीनता का संग्राम एक ऐसा महान यज्ञ था जिसमें हर भारतीय अस्मिता के प्रति समर्पित राष्ट्रभक्त ने निःस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत भूमि पर कोई भी भाग आत्मोत्सर्ग के इस पर्व में पीछे नहीं रहा था। हमारा पूर्वोत्तर जिसे आज हम अष्टलक्ष्मी अर्थात् 8 राज्यों के रूप में पहचानते हैं इसके शूरवीरों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई परंतु शेष भारत में प्रायः उनकी चर्चा नहीं हुई। अंग्रेजों के दमन चक्र का शिकार बनने के विरोध में पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का वर्णन करने से पूर्व पूर्वोत्तर चर्चा करना समीचीन होगा। हमारा पूर्वोत्तर जिसका वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों से पूर्ववर्ती वैदिक काल में किरात देश के नाम से मिलता है, वह कामरूप और प्रयाग प्राग्ज्योतिषपुर के नाम से विश्व के प्राचीन साहित्य और यात्रा वर्णनों में समृद्ध प्रदेश के रूप में अपना स्थान रखता है।

केवल भारतीय साहित्य नहीं, तीसरी शताब्दी ईसापूर्व से पहली शताब्दी ईसापूर्व के ग्रीक समुद्री व्यापारियों द्वारा लिखित पेरिपल्स एरीथ्रियन समुद्र, जिसे आज एरीट्रियन समुद्र कहते हैं। वर्णनों (स्क्रोल्स) के 66वें अध्याय में पूर्वोत्तर भारत का वर्णन करते हुए यहां के ''किरातों'' का वर्णन किया है। भारत के प्राचीन इतिहास में जिसका विशिष्ट स्थान है वह प्रदेश, आज के 8 राज्यों नहीं, एक समग्र इकाई के रूप में वर्णित है।

पुस्तक खरीदने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाईट : www.publicationsdivision.nic.in

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/

https://telegram.me/upsc_iassquad Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/ https://telegram.me/upsc_iassquad

रजि.सं. डी.एल.(एस)-05/3231/2021-23
Reg. No. DL(S)-05/3231/2021-23 at RMS, Delhi
28 जून, 2021 को प्रकाशित
• 2-3 जुलाई, 2021 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2021-23
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

अब उपलब्ध है...

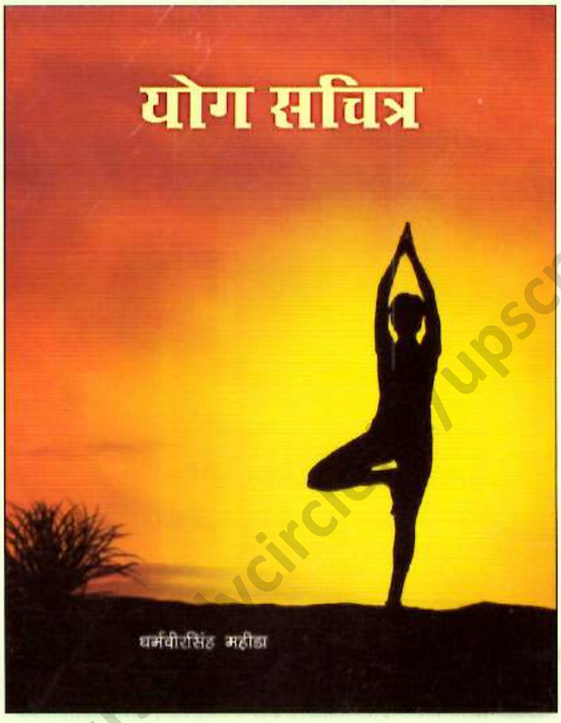

योग सचित्र

मूल्य - ₹ 355/-

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

www.ourstudycircle.in/upscpdf/

प्रकाशक व मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल

Google: www.ourstudycircle.in/upscpdf/